

51.11.21

①

Impact Factor -(SJIF) -8.572  
ISSN - 2278 -9308

FEBRUARY 2022  
ISSUE NO. (CCCXXXVII) 337

# *B.Aadhar*

Peer - Reviewed & Refereed Indexed

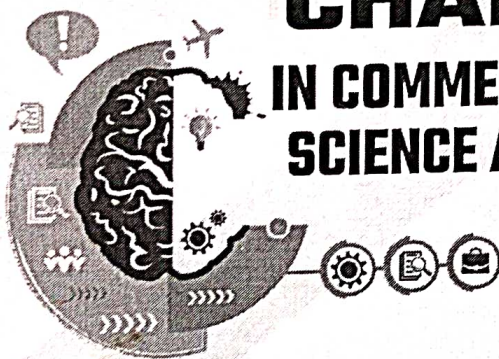
MULTIDISCIPLINARY INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL

International Interdisciplinary Virtual Conference on

## **INNOVATIONS AND CHALLENGES**

### **IN COMMERCE, HUMANITIES, SCIENCE AND TECHNOLOGY**

ICCHST-2022



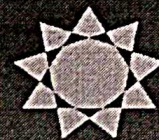
Editors

Dr. Archana P. Khandelwal

Dr. Jagdish M. Saboo



This Journal is Indexed in  
Scientific Journal Impact Factor (SJIF)  
Cosmos Impact Factor (CIF)  
International Impact Factor Services (IIFS)



For Details Visit to : [www.aadharsocial.com](http://www.aadharsocial.com)

*Aadhar* PUBLICATIONS



# B.Aadhar

Peer-Reviewed & Refereed Indexed  
Multidisciplinary International Research Journal

**February, 2022**

ISSUE No- (CCCXXXVII) 337-B

**ICCHST-2022**

**Prof. Virag.S.Gawande**

Chief Editor

Director

Aadhar Social Research &, Development Training Institute, Amravati.

Editor

**Dr. Archana P. Khandelwal**

**Dr. Jagdish M. Ssboo**

SHANKARLAL KHANDELWAL ARTS, SCIENCE AND COMMERCE COLLEGE,  
AKOLA (MS)

**Aadhar International Publication**

For Details Visit To : [www.aadharsocial.com](http://www.aadharsocial.com)

© All rights reserved with the authors & publisher



47	GST And Indian Economy	Dr.D.P.Parate	198
48	A Study Of Impact And Challenges Of Gst On Various Constituents Of Indian Economy	Boob Krishna s	201
49	Crypto Currency& Bitcoin: Scope & Future in India	Amit Vasant Agrawal 1 / Dr. Yogesh K. Agrawal 2	206
50	A Study of Client Satisfaction Towards Service Quality at Bharat Vikas Group India Limited	Dr Dileep Kumar Singh, / Dr. Ramprakash O. Panchariya Dr. Mukesh Bhojwani,	211
51	Need of Employee loyalty in improving organizational Productivity	Dr. Shital Mantri / Dr.Sheetal Waghmare / Vaishali Kale	214
52	पश्चिम विदर्भातील पर्यटन उद्योग राजगाराचे साधन	प्रा. शाम किसनराव तंत्रपाळे	219
53	वरुड शहरातील लघु उद्योगातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालेल्या महिला: एक अध्ययन	प्रा लुम्बिनी हरिदास गणवीर	224
54	रोकड विरहीत व्यवहार व भारतीय अर्थव्यवस्था - एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ. विष्णु एकनाथ घुमटकर	230
55	महिला सक्षमीकरण आणि महिलांचा राजकीय सहभाग	प्रा. रमेश एकनाथ भारुडकर	234
56	महिला सक्षमीकरण आणि बचत गट	प्रा. वैशाली तु. गोरे	238
57	वस्तू व सेवा कर आणि ग्राहक	डॉ. आनंद गोमाजी चव्हाण	241
58 ✓	भारत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार	प्रा.डॉ.नीता नंदलाल तिवारी	246
59	'मेक इन इंडिया'चे धोरणात्मक महत्त्व - भारतीय अर्थव्यवस्थेला सक्षम करण्यासाठीची मोहीम	प्रा.कविता किसन भोये	250
60	प्राणायामाचे महत्त्व	प्रा. डॉ. चंद्रशेखर ब. कडू	256
61	महिला साक्षरता : एक अवलोकन	प्रा. डॉ. आमले समाधान साहेबराव	259
62	भारतात डिजिटल मार्केटिंग उद्योगाची वाढ	प्रा. डॉ. अमोल सतीश राऊत	262
64	भारतातील वाढत्या बँकिंग घोटाळ्यांचे आणि त्यांच्याकारणांचे अध्ययन	डॉ. संजय पी. काळे	266
65	भारतातील शाश्वत विकास आणि हवामान बदलावर शासनाच्या प्रगतीचे अध्ययन	डॉ. राधेशाम पिलाजी चौधरी	270
66	व्यवसाय आणि आर्थिक माहितीच्या लेखा आणि अंकेक्षण मध्ये रोबोटिक्सलेखांकनाची भूमिका	प्रा. डॉ. पी. बी. खर्चे	275

**भारत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार****प्रा.डॉ.नीता नंदलाल तिवारी**

अर्थशास्त्र प्रमुख श्री धावेकर कला महाविद्यालय, खडकी, अकोला  
मोबाईल नं. ९९२३०३६१२६, g-mail- neetatiwari201456@gmail.com

**प्रस्तावना-**

ऐतिहासिक रूप से, भारत, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आगमन तक, एक प्रमुख व्यापारिक राष्ट्र था। उपलब्ध दस्तावेजों से ये ज्ञात होता है कि मध्ययुगीन काल के दौरान, भारत के निर्यात, वस्तुओं की विविधता के साथ-साथ मात्रा दोनों हीं में, उसकी आयात से कहीं अधिक थे। उनमें वस्त्र, कालीन, जड़त सामान, दस्तकारी वस्तुएं, मोती और गहने तथा मसालों सहित कई उत्पाद शामिल थे। आयात के मुख्य सामान, काबुल और अरब से घोड़े, तथा मेवे और कीमती पत्थर थे। भारत में, यूरोप से कांच से निर्मित वस्तुएं, पश्चिम एशिया से साटन जैसे उच्च स्तर के वस्त्र, भी आयात होते थे, जबकि चीन उसे कच्चे रेशम और चीनी मिट्टी के बरतन की आपूर्ति किया करता था। तिरुचि में, नागापट्टिनम, जो व्यापार के लिए चोलों की प्रमुख बंदरगाह थी। चोलकुला वल्लिपट्टिनम के नाम से जाना-माना, यह दक्षिण पूर्व एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों का प्रवेश द्वार था।

वर्तमान सरकार द्वारा और साथ ही सभी पिछली सरकारों द्वारा निर्यात को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र में माना गया है। विकास को बढ़ावा देने तथा विदेशी मुद्रा की अर्जन के लिए निर्यात को अच्छे स्रोत के रूप में देखा जाता है। श्रम प्रधान निर्यात भी रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। "निर्यात या विनाश" वास्तव में एक नारा था जिसका उपयोग हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने साठ के दशक के शुरुआती वर्षों में किया था। जहाँ हमने अपने व्यापार के प्रदर्शन में पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार किया है, फिर भी भारत जैसे बड़े आकार वाले देश के लिए हमारी निर्यात संख्या अपेक्षाकृत अब भी कम है।

कूटनीति में, वैश्विक मामलों में कुशलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए एक राष्ट्र के पास जो ताकत और लाभ होते हैं, विभिन्न कारकों पर निर्भर हो सकते हैं। आज की दुनिया में, विदेशी व्यापार में मजबूती महत्वपूर्ण है। निकट तथा दूर के क्षेत्रों से अधिक से अधिक आर्थिक अंतर संपर्क और वाणिज्य, साझेदारी को मजबूत बनाने और अधिक समझ के निर्माण में योगदान देते हैं। निर्यात, विशेष रूप से गुणवत्तापूर्ण निर्यात, एक निश्चित ब्रांड मूल्य और प्रतिष्ठा प्रदान करता है, जैसा कि हमने जर्मनी या जापान के मामले में देखा है।

**अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता -**

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य कारण ये हैं- प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, उत्पादन, विशेषज्ञता और लागत लाभों के कारकों की उपलब्धता

1. प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण - सभी देश उनके बीच प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण या उनके उत्पादकता स्तरों में अंतर के कारण समान या सस्ते उत्पादन नहीं कर सकते हैं। नतीजतन, वे अपने अधिशेष उत्पादन को उन वस्तुओं के साथ विनिमय करते हैं जो वे अपने देश में कम आपूर्ति में हैं।
2. उत्पादन के कारकों की उपलब्धता - उत्पादन के विभिन्न कारक जैसे श्रम, पूंजी और कच्चे माल, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक राष्ट्रों के बीच भिन्न होते हैं।
3. विशेषज्ञता - कुछ देश वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ फायदे हैं जैसे कि उन्नत तकनीकी जानकारी, उच्च श्रम उत्पादकता, उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां, आदि। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल जूट उत्पादों में माहिर है।
4. लागत लाभ - सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक स्थितियों में अंतर के कारण विभिन्न देशों में उत्पादन लागत भिन्न होती है। कुछ देश अन्य देशों की तुलना में आर्थिक रूप से कुछ सामान का उत्पादन करने के लिए बेहतर

स्थिति में हैं। परिणामस्वरूप, अन्य देशों में कम कीमतों पर उपलब्ध वस्तुओं को आयात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न हैं और उन वस्तुओं का निर्यात करते हैं जिन पर वे बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।

**भारत-अमेरिका व्यापार और TPF का पुनरुद्धार**

भारत-अमेरिका व्यापार संबंध: संयुक्त राज्य अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये भारत सेवाओं के आयात का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

भारत का वृहत उपभोक्ता आकार और आर्थिक विकास की दिशा में प्रगति, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यातकों के लिये एक आवश्यक बाज़ार बनाता है।

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के दौरान दोनों पक्ष एक 'मिनी ट्रेड डील' पर सहमत होने के निकट पहुँच गए थे, जहाँ भारत कुछ उत्पादों पर से टैरिफ हटा देता और बदले में उसे पुनः अमेरिका के 'सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली' (Generalized System of Preferences- GSP) कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाता।

लेकिन बाइडेन प्रशासन नए व्यापार समझौतों के प्रति अभी तक उदासीन ही नज़र आया है।

व्यापार के विस्तार के प्रयास: भारत-अमेरिका ट्रेड पॉलिसी फोरम की शुरुआत से पहले 'यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स' ने एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिये आधार तैयार करने हेतु तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया था।

भारत में भी आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने को लेकर एक सकारात्मक माहौल है, जहाँ प्रमुख क्षेत्रों में 'एफडीआई कैप' बढ़ाने और पूर्वव्यापी कर कानून को निरस्त किये जाने की हाल की पहलों से निवेशकों के भरोसे को बल मिला है और भारत के उदारीकरण के पथ को लेकर आशा प्रकट की गई है।

भारत सरकार ने सुधार के प्रति अपने समर्पण का संकेत दिया है और अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है।

TPF से परस्पर लाभ की स्थिति: अन्य देशों के साथ ही अमेरिका भी उपभोक्ता व्यय में वृद्धि को प्रबंधित करने, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने और व्यापक रणनीतिक उद्देश्यों के साथ वैश्विक आपूर्ति शृंखला को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है।

व्यापार का विस्तार उपभोक्ता मूल्यों को कम कर सकता है और उसके आर्थिक सुधार को अधिकाधिक स्थिर/स्थायी बना सकता है।

दूसरी ओर, भारत भी मूल्य शृंखलाओं को आगे बढ़ाने और महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है।

**व्यापार नीति फोरम (TPF) का महत्त्व**

यद्यपि इस फोरम से किसी बड़ी सफलता के मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन यह बाइडेन काल में एक मज़बूत द्विपक्षीय व्यापार संबंध निर्माण का महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकता है।

अमेरिका, भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण साझेदारों में से एक है और दोनों देशों के बीच निकटता बढ़ी है। चीन को लेकर दोनों देशों की साझा चिंताओं ने व्यापार संबंधों में मौजूद तनाव के बावजूद मज़बूत रक्षा एवं रणनीतिक संबंधों को बल दिया है।

व्यापार नीति फोरम भारत के लिये एक बाज़ार अभिगम्यता पैकेज के सृजन का अवसर प्रदान करता है, जो अमेरिका के साथ व्यापार तनाव को कम करेगा और इससे बाइडेन प्रशासन को 'धारा 232' के तहत टैरिफ को हटाने का राजनीतिक आवरण प्राप्त होगा। यह अंततः भारतीय कंपनियों को लाभान्वित करेगा।

भारत ने वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होने, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने और वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

ये ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें अमेरिकी पूंजी, निवेश और अमेरिकी बाज़ार तक निरंतर पहुँच के साथ बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है।  
संबद्ध चुनौतियाँ



टैरिफ अधिरोपण: वर्ष 2018 में अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ इस्पात उत्पादों पर 25% और कुछ एल्यूमीनियम उत्पादों पर 10% का टैरिफ अधिरोपित किया था।

भारत ने जून, 2019 में अमेरिकी आयात के 28 उत्पादों (लगभग 1.2 बिलियन डॉलर मूल्य के) पर टैरिफ बढ़ाकर जवाबी कार्रवाई की।

हालाँकि, धारा 232 टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका को इस्पात निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष 46% की गिरावट आई है।

आत्मनिर्भरता को संरक्षणवाद समझा जाना: 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' से यह भ्रमित छवि बनी है कि भारत तेज़ी से एक संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है।

अमेरिका की 'सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली' (GPS) से बहिर्वेशन: अमेरिका ने GPS कार्यक्रम के तहत भारतीय निर्यातकों को प्राप्त शुल्क-मुक्त लाभ को वापस लेने (जून 2019 से प्रभावी) का निर्णय लिया।

नतीजतन, 5.6 बिलियन डॉलर मूल्य के भारतीय निर्यात को प्राप्त विशेष शुल्क व्यवहार को समाप्त कर दिया गया, जिससे फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, कृषि उत्पाद और मोटरवाहन पार्ट्स जैसे भारत के निर्यात-उन्मुख क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। आगे की राह

वार्ताएँ आयोजित करना: चार वर्षों बाद जब पहले अमेरिका-भारत 'व्यापार नीति फोरम' की शुरुआत हुई है, यद्यपि इन प्रारंभिक चर्चाओं के माध्यम से कोई विशिष्ट व्यापार सौदे की संभावना नहीं है, किंतु दोनों सरकारें इसी प्रकार की वार्ता के माध्यम से वास्तविक प्रगति दर्ज कर सकती हैं। इसमें मुख्यतः दो आयाम शामिल हैं: लंबे समय से चली आ रही अड़चनों और विवादों को दूर करना और इनका समाधान प्राप्त करना।

21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापार ढाँचे का निर्माण करना, जो आर्थिक गलियारे में विकास और नवाचार को प्रेरित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों सहित दोनों देशों के सर्वोत्कृष्ट को एक साथ ला सकता है। टैरिफ हटाने की पहल: किसी संभावित समझौते की दिशा में पहला कदम यह होगा कि भारत स्वयं पहल करे और अपने प्रतिशोधी शुल्क को हटाने पर एकतरफा रूप से विचार करे। यह व्यापार वार्ता में एक रचनात्मक पक्ष बनने की भारत की इच्छा का प्रतिनिधित्व करेगा।

भले ही अमेरिका की ओर से किसी प्रतिबद्धता के बिना भारत द्वारा टैरिफ हटाना बस एक बेहतर कदम ही होगी, लेकिन यह अंततः द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के लिये फायदेमंद सिद्ध होगा।

चीन का मुकाबला करना: रणनीतिक दृष्टिकोण से, भारत के लिये चीन का मुकाबला करने का एक उपाय यही है कि भारत अपने उन भागीदारों के साथ व्यापार संबंधों को गहन करे जो भारत के विकास का समर्थन करने के लिये प्रतिबद्धता रखते हैं।

अमेरिका के साथ एक समझौता भारत के लिये रणनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से लाभप्रद होगा।

चूँकि अमेरिकी कंपनियाँ अपनी कुछ विनिर्माण गतिविधियों को चीन से बाहर स्थानांतरित करने पर विचाररत हैं, एक जीवंत व्यापार रणनीति, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं को पूरकता प्रदान कर सकती है, और विनिर्माण एवं निर्यात दोनों को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।

डिजिटल विकास को सुगम बनाना: डिजिटल क्षेत्र (जो 100 बिलियन डॉलर से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है) में विकास को बढ़ावा देने के लिये दोनों पक्षों को कई मूलभूत मुद्दों—डिजिटल सेवा कर, सीमा-पार डेटा प्रवाह, साझा सेलुलर मानक आदि को संबोधित करने की आवश्यकता होगी।

यह महत्वपूर्ण है कि डिजिटल सेवा कर के मामले में भारत उभरते वैश्विक समझौतों के साथ अनुकूलता लाए, जिससे व्यापार में तेज़ी आएगी।

इसके साथ ही, भारत और अमेरिका को एक एकीकृत दूरसंचार पारितंत्र में कार्यान्वयन के लिये 5G मानकों पर सहमति बनानी चाहिये।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अमेरिका-भारत सहयोग वैश्विक स्वास्थ्य संरचना के लिये सर्वप्रमुख प्रभावशाली कदम होगा।



वैश्विक महामारी से बाहर निकलते दोनों देशों के लिये यह अनूठा अवसर है कि वे ऐसे स्वास्थ्य पहल के लिये आगे बढ़ें जो भारतीय बाज़ार की बाधाओं को दूर करे, जिससे अमेरिकी कामगारों और भारतीय रोगियों दोनों को हानि पहुँचती है।

इस क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने और अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ावा देने के लिये यह आवश्यक है कि:सरकारें अभिनव चिकित्सा उत्पादों पर बाज़ार आधारित दृष्टिकोण अपनाएँ सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक खरीद नीतियाँ विदेशी फर्मों के साथ भेदभाव नहीं करेंगी चिकित्सा उपकरणों और फार्मास्यूटिकल्स के अनुमोदन में तेज़ी लाने के लिये नियामक संरचनाओं को संरेखित करें ताकि महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक उपचार त्वरित गति से बाज़ार तक पहुँच सकें।

निष्कर्ष-

भू-राजनीतिक उतार-चढ़ाव के इस दौर में दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों का एक साथ आना विवेकपूर्ण होगा। अमेरिका-भारत ट्रेड पॉलिसी फोरम के माध्यम से व्यापार और निवेश संबंधों को मज़बूत करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण आरंभिक कदम हो सकता है।

बढ़ते सांस्कृतिक और रणनीतिक संरेखण की ही तरह बेहतर व्यापार साझेदारी दोनों देशों को महामारी के बाद के परिदृश्य में बेहतर ढंग से आगे बढ़ने में मदद करेगी।

भारत के आकार और विकास की आकांक्षाओं को देखते हुए, हमारे व्यापार संकेतक काफी मामूली हैं। जहाँ हम आबादी के मामले में दुनिया में नंबर 2 हैं तथा साधारण जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के मामले में नंबर 7 हैं, हम निर्यात के मामले में 1.64% हिस्सेदारी के साथ नंबर 19 पर नज़र आते हैं तथा आयात के मामले में 2.34% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ हमारा दर्जा नंबर 13 का है। हमारे विकास के स्तर के हिसाब से हमारा व्यापार जीडीपी अनुपात 39.8 प्रतिशत पर अपेक्षाकृत कम है। भारत का प्रति व्यक्ति व्यापार मात्र 382 अमेरिकी डॉलर है जो आसियान या पूर्वी एशियाई क्षेत्रों के देशों की इसकी संख्या से काफी कम है।

संदर्भ-

१. <https://www.kailasheducation.com>. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, महत्व/लाभ, हानियाँ By: Kailash meena 14 अप्रैल 2021

२. [https://hi.wikipedia.org/wiki/अंतर्राष्ट्रीय\\_व्यापार](https://hi.wikipedia.org/wiki/अंतर्राष्ट्रीय_व्यापार)

३. <https://mea.gov.in/distinguished-lectures-detail-hi.htm?712> भारत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार: कुछ परिप्रेक्ष्य द्वारा राजदूत (सेवानिवृत्त) वी.एस. शेषाद्री

४. <https://www.businessmanagementideas.com>. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा एस. वंदना

५. <https://www.drishtiiias.com/hindi>. भारत-अमेरिका व्यापार संबंध 24 Nov 2021

MAH/MUL/ 03051/2012

ISSN :2319 9318



Special Issue  
01 March 2022

Editor

Dr. Bapu g. Gholap

(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

विद्येविना मति गेली, मतीविना नीति गेली  
नीतिविना गति गेली, गतिविना वित्त गेले  
वित्तविना शूद्र स्वचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले

-महात्मा ज्योतीराव फुले

❖ विद्यावार्ता या आंतरविद्याशाखीय बहुभाषिक त्रैमासिकात व्यक्त झालेल्या मतांशी मालक, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक सहमत असतीलच असे नाही. न्यायक्षेत्र:बीड



"Printed by: Harshwardhan Publication Pvt.Ltd. Published by Ghodke Archana Rajendra & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor Dr. Gholap Bapu Ganpat.



Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205  
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.

At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed  
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295  
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com

All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors

www.vidyawarta.com



- 71) ROLE OF ENTREPRENEURS IN ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDIA  
Mrs. Asma singh sidar, Distt. Korba (C.G) ||278
- 72) Features of Stand-up India  
Prof. Sudhir L. Khadse, Dist – Jalgaon (Maharashtra) ||281
- 73) Use of ICT in Teaching  
Ku.Kirti S.Pandit, Wardha ||283
- 74) Use of ICTs in Social Work Education & Field Work Training during Covid-19...  
Shivaji R. Tuppekar, Amravati ||285
- 75) Use of ICT in Teaching  
Dr.Harsha Dhule (Chikhalkar), Akola ||289
- 76) Use of ICT in Teaching  
Prof. Rahul P.Ghugre, Akola ||293
- 77) USE OF MODERN TECHNOLOGY IN TODAY'S INDIAN MUSIC  
VIVEK SANTOSHRAO CHAPKE, JHUNJHUNU, RAJASTHAN ||296
- 78) RE-SKILLING OF CULTURAL MILIEU: CONTEXTUALIZING DEBATE IN FICTIONS OF ...  
Ratanlal L. Yeul, Akola ||298
- 79) Yoga - way of human well being  
Assistant Prof.Dr. Shakuntala Patil, Ichalkaranji ||302
- 80) USE OF ICT IN TEACHING  
Dr.Maralihalli.YY., Dist:- Haveri State:- Karnataka ||306
- 81) कोरोना काळातील भारतातील मुख्य उद्योगांवर झालेले परिणाम व आव्हाने  
कु. अर्चना रा. बोडे, अकोला ||308
- 82) शास्वत विकास : चिरकालीन विकासाची गरज  
डॉ. नितीन ज्ञानदेव चौधरी, अकोला ||311
- 83) आर्थिक नवप्रवर्तन  
प्रा डॉ नीता नंदलाल तिवारी, अकोला ||315
- 84) मराठी भाषा : सद्यस्थिती  
डॉ. कैलास वानखडे, अकोला(महाराष्ट्र) ||320
- 85) नाविन्यता व उद्योजकता विकासात महाराष्ट्र राज्याचे योगदान  
संतोष देविदास मोहधरे, जि. वर्धा ||325
- 86) अध्यापनात माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर  
सौ. प्राची चैतन्य पाटील, अकोला ||328

जगातील देशांमध्ये आर्थिक उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि औद्योगिकीकरण होऊनही मोठ्या लोकसंख्येला मूलभूत सुविधा, प्राथमिक शिक्षण आणि अन्न पुरवणे हा त्यांच्या विकास धोरणाचा मध्यवर्ती भाग राहिला आहे. जागतिक स्तरावर संपूर्ण निष्ठा आणि प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे, ज्यामध्ये मानवासह पर्यावरणाचे संरक्षण आणि समतोल राखण्याची गर्भित भावना आहे. त्यामुळे सध्याच्या आणि भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी सध्याच्या विकास आराखड्यांमध्ये पर्यावरणाचे कमीत कमी नुकसान होईल याची काळजी घेतली पाहिजे. नैसर्गिक, जैवविविधता आणि नैसर्गिक संसाधने आणि अन्न सुरक्षा यांसारख्या गोष्टीसह मानवी जीवनाच्या मूलभूत गरजांचे संरक्षण केले पाहिजे. ज्या प्रमाणात त्या नैसर्गिक संसाधनाची पुनर्निर्मिती होत आहे त्या प्रमाणात केवळ नैसर्गिक संसाधने मानवी क्रियाकलापांद्वारे वापरली जावीत. सामाजिक जबाबदारी आणि शाश्वत विकास हे पर्यावरण आणि मानवी अस्तित्वाच्या केंद्रस्थानी आहेत यात शंका नाही.

#### संदर्भ ग्रंथसूची :

दत्ता वानखडे शास्वत विकास पीबीडी प्रकाशन  
कथुरीया रेणू सतत विकास संसाधने का पारिस्थिकीय  
प्रबन्धन श्रुती प्रकाशन जयपूर  
कुमार रूसेन २००९, स्थायी विकास: एक वैश्विक  
चिंता

कदम प्रतिभा, २०२१ शास्वत विकास ध्येय: ओळख  
नित्य प्रकाशन भोपाळ

<https://www.dompsc.com/Environment/sustainable-development.php>

<http://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO>

[http://en.wikipedia.org/wiki/Green\\_development](http://en.wikipedia.org/wiki/Green_development)

United Nations Division for sustainable  
Development. Documents: Sustainable Develop-  
ment Issues Retrieved: 2007-05-12

<http://www.susdiv.org/>

□□□

83

## आर्थिक नवप्रवर्तन

प्रा डॉ नीता नंदलाल तिवारी

अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख

श्री धाबेकर कला महाविद्यालय, खडकी, अकोला

\*\*\*\*\*

#### प्रस्तावना

सामान्यतः मानवी सभ्यतेचा विकास हा विज्ञानाच्या प्रगतीशी आणि त्याच्या वाढत्या प्रभावाशी जोडून पाहिला जातो, कारण आदिम अवस्थेपासून समाजाच्या प्रगत अवस्थेपर्यंतचा प्रवास हा विज्ञान आणि त्याच्या शोधांचा परिणाम आहे. खरं तर, वैज्ञानिक शोधांनी आपल्या सभ्यतेला खूप काही दिले आहे, परंतु नवनिर्मितीमुळे या शोधांची उपयुक्तता वाढली आहे. उदाहरणार्थ, चाकाचा शोध लावल्याने माणसाने त्याच्या सर्व अडचणी कमी केल्या आणि जड वस्तू कमी श्रमात वाहून नेणे शक्य झाले, परंतु चाकाचा शोध लागल्यानंतर, चाकाची गाडी जनावराने खेचली, ही घटना नावीन्यपूर्ण होती. नवनिर्मिती आणि शोध यात काही फरक नाही. जिथे आविष्काराचा अर्थ नवीन कल्पना मूर्त स्वरूपात आणणे हा आहे, तर नावीन्य म्हणजे या कल्पनेची उपयुक्तता वाढवण्याची प्रक्रिया आहे. आविष्कार हा पूर्णपणे नवीन कल्पनेचा संदर्भ देतो तर नवकल्पना ही सुधारणा आणि शोध यांच्यातील दुवा आहे.

#### नवप्रवर्तनाचा अर्थ

अर्थशास्त्र, व्यवसाय, तंत्रज्ञान आणि समाजशास्त्र या विषयांमध्ये नावीन्यपूर्ण विषय खूप महत्त्वाचा आहे. नवप्रवर्तन म्हणजे उत्पादन, प्रक्रिया किंवा सेवेमध्ये छोटा किंवा मोठा बदल घडवून आणणे. नवप्रवर्तन अंतर्गत, काही नवीन आणि उपयुक्त पद्धतींचा अवलंब केला जातो, जसे की नवीन पद्धत, नवीन तंत्रज्ञान, नवीन कार्यपद्धती, नवीन सेवा, नवीन उत्पादन

इ. नवनिर्मिती हा अर्थव्यवस्थेचा चालक मानला जातो. नवोपक्रमावर अनेक व्याख्या दिल्या गेल्या आहेत, परंतु त्यापैकी क्रॉसन आणि उपयडिन यांनी दिलेली व्याख्या सर्वात संक्षिप्त आणि पूर्ण आहे, जी खालीलप्रमाणे आहे —

नवप्रवर्तन म्हणजे आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात मूल्यवर्धित नवकल्पनाचे उत्पादन किंवा स्वीकृती, परिपक्वता आणि शोषण उत्पादने, सेवा आणि बाजारपेठांचे नूतनीकरण आणि विस्तार आहे. उत्पादनाच्या नवीन पद्धतींचा विकास आहे आणि नवीन व्यवस्थापन प्रणालींची स्थापना आहे. ही एक प्रक्रिया आणि परिणाम देखील आहे.

संस्थेच्या संदर्भात नवोपक्रमामध्ये कार्यक्षमता, उत्पादकता, गुणवत्ता, बाजारातील वाढ इ. सुधारणे समाविष्ट असते. रुग्णालये, विद्यापीठे, ग्रामपंचायती इत्यादी सर्व संस्था नाविन्यपूर्ण असू शकतात.

ज्या संस्था नवनवीन शोध घेत नाहीत त्यांचा विनाश होतो. त्यांची जागा नवोपक्रमात यशस्वी झालेल्या संस्थांनी घेतली आहे. नवोपक्रमातील सर्वात महत्वाचे आव्हान म्हणजे प्रक्रिया—नवप्रवर्तन आणि उत्पादन—नवप्रवर्तन यांच्यातील संतुलन ठेवणे आहे.

नवप्रवर्तन आणि आर्थिक विकास

अर्थव्यवस्थेला पुढे नेण्यासाठी, आपली उत्पादने आणि सेवा ही तांत्रिक नवकल्पनांचा परिणाम असणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत पुढे येणारे ग्राहकच अर्थव्यवस्थेला गती देतील. देशातील बेरोजगारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे नुकसान, बँकिंग आणि पायाभूत सुविधांच्या विकास कंपन्यांची पडझड आणि कृषी क्षेत्रातील संकट यासारख्या आर्थिक समस्यांसाठी अर्थतज्ज्ञ, राजकारणी, नोकरशहा यांना दोष देऊन काही उपयोग नाही. आपली आर्थिक समस्या आहे असे खेद करण्यात काही अर्थ नाही कारण आपला देश व्यावसायिकांच्या दुष्ट वर्तुळात अडकला आहे जे तांत्रिक नवकल्पनाऐवजी व्यवसाय, रिअल इस्टेट, स्पेक्ट्रम आणि कामगार इत्यादींवर अधिक लक्ष केंद्रित करतात. अर्थतज्ज्ञ आणि आर्थिक धोरणकर्त्यांना दोष देण्यातही अर्थ नाही. परदेशात शिकलेले हे लोक तिथे पूर्णवेळ नोकरी करतात आणि आपला बायोडाटा मजबूत

करण्यासाठी अल्प कालावधीसाठी देशात येतात. आपण इथे राहतो तोपर्यंत एफडीआय, एफडीआय चा जप करा, जसे आपले पूर्वज कठीण काळात राम—राम जपायचे.

वस्तुस्थिती अशी आहे की एकदा आपण वरील नाटकाच्या पडद्याआड डोकावून पाहिल्यावर एक नवीन सत्य समोर येते. देशातील देशांतर्गत ग्राहक आणि संस्थात्मक बाजारपेठा खूपच लहान आहेत आणि ग्राहक आणि निर्णय घेणारे चांगले आर्थिक स्थिती असलेले तंत्रज्ञानापासून दूर आहेत. त्यामुळे नवोपक्रमावर आधारित व्यवसाय वाढणे जवळपास अशक्य झाले. एनसीईईआर च्या अध्ययन हाऊ इंडिया अर्नस स्पेंड्स ऍंड सेव्स अभ्यासानुसार, फक्त ८० दशलक्ष भारतीय कुटुंबांना त्यांच्या मूलभूत गरजांच्या पलीकडे खर्च करण्यासाठी पुरेसे पैसे मिळतात. एनसीईईआर म्हणते की या गटामध्ये व्यवस्थापन, तंत्रज्ञ, व्यावसायिक अशा लोकांचा समावेश आहे ज्यांचे मासिक उत्पन्न सुमारे १३,००० रुपये आहे. उर्वरित देश शेतकरी, मच्छिमार, वाहतूक क्षेत्रातील कामगार, असंघटित कामगार, फेरीवाले, इत्यादींनी बनलेला आहे ज्यांचे मासिक उत्पन्न जेमतेम ४,००० ते ५,००० रुपये आहे. त्यांच्या विशिष्ट गरजांशिवाय इतर काहीही खर्च करण्यासाठी त्यांच्याकडे जागा नाही.

असे नाही की देशात उत्पादनांना बाजारपेठ नाही, परंतु याचा अर्थ असा आहे की उद्योजकांना त्यांच्या संभाव्य ग्राहकांना संतुष्ट करण्यासाठी तांत्रिक नवकल्पनांद्वारे उत्पादनांमध्ये सुधारणा करावी लागेल. देशात विकसित झालेल्या या वस्तूंची किंमतही जागतिक किमतीच्या अर्धा किंवा एक तशतीयांश असेल. देशाच्या सार्वजनिक धोरणातील पुढचे मोठे आव्हान म्हणजे तांत्रिक नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी लष्करी खरेदीसाठी जोर देणे. युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनमधील प्रोफेसर मारियाना मॅझुकाटो यांनी आमचे लक्ष वेधले की तांत्रिक नवकल्पना लष्करी खरेदीवर किती प्रमाणात अवलंबून आहे.

तिच्या दी एंटरप्रेन्योरियल स्टेट : डीबंकींग पब्लिक वसेंज प्राइवेट सेक्टर मिथ्सया पुस्तकात तिने आयफोनचे उदाहरण दिले आहे. प्रत्येकाला असे वाटते की हे

आपल्या काळातील एक अलौकिक बुद्धिमत्ता, स्टीव्ह जॉब्स आणि त्यांची कंपनी ऐपलयांचे उत्पादन आहे. ती स्पष्ट करते की सेल्युलर तंत्रज्ञान स्वतः यूएस सैन्याने केलेल्या गुंतवणुकीतून उदयास आले आहे. आज आपण सगळ्यांना वेड लावलेले टच स्क्रीन मोबाईल फोन, आपली चित्रे-संगीत आणि फाईल्स गोळा करण्यासाठी वापरलेली हार्ड ड्राईव्ह, फोनमध्ये वापरली जाणारी लिथियम-आयन बॅटरी आणि मोबाईल फोनच्या नकाशात वापरलेली जीपीएस, हे सर्व अमेरिकन सैन्याद्वारे गुंतवणुकीमुळे वापरले जाते. वापरले जाते. अमेरिकेच्या विमान वाहतूक आणि अवकाश, वैद्यक आणि जैवतंत्रज्ञान आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी इत्यादी क्षेत्रात लष्कराने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. लष्कराची ही भूमिका अजिबात नवीन नाही. उदाहरणार्थ, ८व्या शतकाच्या सुरुवातीला पोलादाच्या मागणीत झालेली वाढ तलवारीच्या मागणीमुळे झाली.

भारताच्या मोबाईल उद्योगाने एक मोठी संधी गमावली आहे. सरकारी धोरणामुळे भारतीय मोबाइल फोन सेवा प्रदाते मोबाइल नेटवर्क तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापनासाठी आयबीएमसारख्या परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून आहेत. या कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यांसाठी कोणत्याही प्रकारची संधी निर्माण केली नाही. आता भारत ८००० कोरड डॉलरचे मोबाइल फोन आयात करतो. या मागणीमुळे देशात एक दोलायमान आणि जागतिक दर्जाची मोबाइल उत्पादन क्षमता निर्माण होऊ शकली असती. पर्सनल कॉम्प्युटरच्या युगातही, अनेक भारतीय कंपन्यांनी पीसी हार्डवेअर आणि संबंधित सॉफ्टवेअरच्या संदर्भात अतिशय नाविन्यपूर्ण उत्पादने तयार केली होती. पण देशाच्या संरक्षण खरेदी क्षेत्राकडून त्याला पाठिंबा मिळाला नाही आणि उपक्रम मागे पडला.

या क्षेत्रात देशाची प्रगती का होऊ शकली नाही याची अनेक सखोल राजकीय-आर्थिक कारणे आहेत. डॉक्टर. रघुनाथ माशेलकर आणि रवी पंडित यांनी त्यांच्या अलीकडच्या लीपप्रॉगिंग टू पोल व्हॉल्टिंग, क्रिएटिंग द मॅजिक ऑफ रॅडिकल यट सस्टेनेबल ट्रान्सफॉर्मेशन या पुस्तकात काही आशा दाखवल्या आहेत. पोल व्हॉल्टिंग द्वारे तो चार-लीव्हर व्यवस्थेचा

संदर्भ देतो जो इतर लीव्हरच्या संयोगाने कार्य करतो. पहिले लीव्हर म्हणजे तंत्रज्ञान आणि ते म्हणतात की तंत्रज्ञान वापरताना हे लक्षात ठेवले पाहिजे की तंत्रज्ञानासाठी काहीही अशक्य नाही. दुसरे लीव्हर सार्वजनिक धोरण आहे परंतु ते चेतावणी देतात की सरकारने हस्तक्षेप केव्हा करायचा आणि कधी नाही हे अत्यंत काळजीपूर्वक ठरवले पाहिजे.

तिसरा लीव्हर म्हणजे सामाजिक संलग्नता, जे केवळ तेव्हाच प्राप्त होते जेव्हा उत्पादने किंवा सेवा अशा प्रकारे डिझाइन केल्या जातात की ते मोठ्या लोकसंख्येसाठी उपयुक्त ठरतील. विशेषतः जे मार्जिनवर आहेत त्यांच्यासाठी. शेवटचा लीव्हर हा आर्थिक मॉडेल आहे जो या प्रयत्नांना आधार देतो. येथे ते म्हणतात की उत्पादन किंवा सेवेचे मूल्य असे असावे की ते सर्वांना वाजवी वाटेल.

जगभरातील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भांडवल आणि आर्थिक संसाधने जगभरातील कोविड-१९ मुळे कमी होत आहेत. युनायटेड नेशन्स एजन्सी ऑन इंटेलिक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफेयर्स (WIPO) ने बुधवारी एक नवीन अहवाल जारी केला, ज्यामध्ये असे दिसून आले आहे की नवीन आणि संशोधन-केंद्रित कंपन्या आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था सध्याच्या परिस्थितीत जास्त प्रभावित झाल्या आहेत. अहवालानुसार, स्विट्झर्लंड हा नाविन्यपूर्ण क्षेत्रात जगातील आघाडीचा देश आहे, तर स्वीडनने दुसरा क्रमांक पटकावला आहे.

आर्थिक वाढीसाठी आणि संकटातून सावरण्यासाठी नवकल्पना आणि नाविन्यपूर्ण उपायांना चालना देणे महत्त्वाचे आहे.

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अहवालाची ही १३ वी आवृत्ती आहे, ज्याचा उद्देश जगभरातील नाविन्य उपक्रमांवरील प्रगतीचे मूल्यांकन करणे आणि माहिती प्रदान करणे आहे.

कोरोनाव्हायरस संकटामुळे आर्थिक क्रियाकलापांना मोठा फटका बसला आहे, लहान नवीन कंपन्यांसाठी निधीचे पारंपारिक स्रोत, नवीन उपक्रमांचे भांडवल ओतणे आणि नवकल्पना यांच्यासमोर आव्हाने आहेत.

## स्विट्झर्लंडची आघाडी कायम

नवप्रवर्तन इंडेक्सच्या माध्यमातून दरवर्षी नवप्रवर्तन क्षेत्रातील जगातील अर्थव्यवस्थांची यादी तयार केली जाते. या वर्षीही जे देश आधीच पुढे होते त्यांनी कमी-अधिक प्रमाणात आपले स्थान कायम ठेवले आहे.

स्विट्झर्लंड हे नावीन्यपूर्णतेच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे आणि सलग १० वर्षांपासून ते जगातील आघाडीवर आहे.

त्यानंतर स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटन आणि नेदरलँडचा क्रमांक लागतो. कोरियाचे प्रजासत्ताक १० व्या आणि सिंगापूर आठव्या क्रमांकावर आहे, तर चीन १४ व्या क्रमांकावर आहे. परंतु भारत, चीन, फिलीपिन्स आणि व्हिएतनाम या देशांनी अलिकडच्या वर्षांत लक्षणीय प्रगती केली आहे. हे सर्व देश आता नवोन्मेषाच्या बाबतीत पहिल्या ५० देशांच्या यादीत आहेत.

या यादीत मलेशिया ३३व्या, व्हिएतनाम ४२व्या, भारत ४८व्या आणि फिलिपाइन्स ५०व्या स्थानावर आहे. नवोपक्रमात आघाडीवर असलेले जवळपास सर्वच देश उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांच्या गटातील आहेत.

### महत्वाचे तथ्य

२००८-०९ च्या आर्थिक संकटातून सावरल्यानंतर नवनिर्मितीचे प्रयत्न वेगाने सुरू असताना कोविड-१९ चा धक्का बसला आहे.

२०१८ मध्ये, संशोधन आणि विकास (आर एंड डी) खर्च ५.२ टक्के दराने वाढला, जो जागतिक जीडीपीच्या दरपेक्षा खूप जास्त आहे.

विशेषतः उत्तर अमेरिका, आशिया आणि युरोपमधील देशांमध्ये, नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी संसाधनांची कमतरता आहे. परंतु ज्या देशांमध्ये उद्योगांमध्ये भांडवली गुंतवणूक तुलनेने कमी आहे अशा देशांमध्ये नवोपक्रमासाठी आर्थिक संसाधनांच्या कमतरतेचा प्रभाव असमान आणि जास्त असेल.

विज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण प्रणालींवर साथीच्या रोगाचे परिणाम समजण्यास वेळ लागेल, परंतु विज्ञानातील

वाढत्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने, मोठे संशोधन प्रकल्प देखील विस्कळीत झाले आहेत.

कोविड-१९ संकटामुळे आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन आणि किरकोळ विक्री यासारख्या अनेक नवीन आणि पारंपारिक क्षेत्रांमध्ये नावीन्यपूर्णतेला चालना मिळाली आहे.

### निष्कर्ष

नवप्रवर्तन म्हणजे नवनिर्मिती, नवीन, नवीन शैली आणि नवीन विचार इ. सध्याच्या युगात, कवीच्या कल्पनेप्रमाणे, माणूस नवीन उत्पादने तयार करण्यास आणि नूतनीकरण करण्यास तयार आहे.

भारतासमोरील समस्या नावीन्यपूर्ण आणि नवीन कल्पनांच्या माध्यमातून सोडवल्या पाहिजेत. स्टार्टअप्सच्या बाबतीत भारत जगातील आघाडीच्या देशांच्या पंक्तीत सामील झाला आहे. विविध क्षेत्रात धोरणात्मक पाठबळ दिले आहे. नोडल स्टार्टअप केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत जी राष्ट्रीय समन्वय, सुविधा आणि देखरेख केंद्र म्हणून काम करतील. हे सर्व पाळणा केंद्रे (इन्क्युबेशन सेंटर्स) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाचा समावेश असलेल्या नाविन्यपूर्ण क्रियाकलापांमध्ये समन्वय साधेल. भविष्यासाठी योग्य कल्पना स्टार्टअप्सकडून येतील. मोठमोठ्य कंपन्या त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यात आणि टिकवण्यात गुंतल्या जातील. लहान स्टार्टअप्स नावीन्यपूर्ण मार्गाने नेतृत्व करतील. प्रत्येकाने स्टार्टअपला पाठिंबा दिला पाहिजे. मुलांचे संगोपन, अध्यापन, प्रशिक्षण, संशोधन, कला, विज्ञान, संस्कृती विस्तार इत्यादी जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात नावीन्यपूर्णतेचे वर्चस्व दिसून येते. रोज काहीतरी नवीन बघायला मिळतं. काही तरी नवीन करण्याची ऊर्मी शतकानुशतके चालत आलेली आहे, पण आजच्या तरुण पिढीमध्ये ही उर्मी अधिक दिसून येत आहे, त्यांनाही आयुष्य नव्या पद्धतीने जगायचे आहे. ती काळाची गरजही आहे. वस्तू आणि सेवा उत्पादन, निर्यात प्रोत्साहन आणि आयात पर्याय देखील यापासून अस्पर्श राहिले नाहीत. आर्थिक विकासाचा आणि विकासाचा कोनशिलादेखील सतत नवनवीन शोध घेऊनच जोपासता येतो. माणसाने नेहमीच आपले जीवन सुखी आणि समृद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विज्ञानाच्या

प्रगतीमुळे होणारे नवनवीन शोध नवकल्पना अधिक संदर्भ

बळकट करण्यात सक्षम झाले आहेत. मानवी संस्कृतीचा इतिहास हा मानवाने वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी घेतलेल्या विविध टप्प्यांचा इतिहास आहे. अश्मयुगातून प्रगतीचा मार्ग स्वीकारत आज मानवाने अणुयुगात प्रवेश केला आहे. आता त्याने वेळ आणि अंतर या दोन्हीवर आपले पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. मदारी आपल्या माकडावर जसे नियंत्रण ठेवते तसे त्याने निसर्गातील वाईट शक्तींवर नियंत्रण मिळवले आहे. नवकल्पनांचा अवलंब केल्याशिवाय मानवी समाजाच्या सुखी भविष्याची कल्पना करणे व्यर्थ आहे. या घडामोडींचा परिणाम म्हणून पृथ्वीला स्वर्ग जरी शिवला नसला तरी स्वर्ग नक्कीच होऊ शकतो असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या विचार आणि वृत्तीवर नवकल्पनांचा काय परिणाम होतो यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. शिक्षणाची प्रासंगिकता विवेकबुद्धीचा वापर करून नवकल्पनांचे दुष्परिणाम समजावून सांगणे आहे जेणेकरून त्यांच्यामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांना तोंड देता येईल. नाण्याची दुसरी बाजू अशी आहे की काही नवकल्पनांमुळे नैतिक मूल्यांची घसरण झाली आहे. माणसाकडे माणसासाठी वेळच उरलेला नाही. मोबाईलचेच उदाहरण घ्या, या मोबाईलने माणसाला इतके व्यस्त केले आहे की तो सतत त्यात व्यस्त असतो. इतरांचे सुख-दुःख जाणून घेण्यासाठी त्याच्याकडे वेळच उरला नाही. पूर्वी लोक बस, ट्रेनमध्ये प्रवास करताना आपापसात बोलत असत, जिथे जग बोलते तिथे दुःख, आनंद वाटून घ्यायचे, पण आता तसे करायला कोणालाच वेळ नाही. इतर प्रत्येक व्यक्ती मोबाईलमध्ये व्यस्त दिसते. माणसाची विचार करण्याची आणि समजण्याची शक्ती कमकुवत झाली आहे. प्रदूषणासारख्या भयंकर समस्यांमुळे लोकांच्या मनात मृत्यूपूर्वीच मृत्युचा ग्रास बनवत आहे. जर आपण या घडामोडींवर नियंत्रण ठेवू शकलो नाही, तर आपण जोखीम आणि विनाश टाळून आशावादी सकारात्मक विचारांची गौरवशाली परंपरा पुनर्संचयित करू शकतो. अन्यथा नवनिर्मिती कधी कधी विनाशकारी ठरते.

1) <https://hindi/business-standard.com/storypage/php> आर्थिक विकास में अहम नवाचार और उपभोक्ता : अजित बालकृष्णन/ २५ मार्च २०१९

2) <https://news.un.org> कोविड-१९: विश्व भर में नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों को भारी झटका; २ सितम्बर २०२०

3) <https://www.jagran.com> नवप्रवर्तन के साथ उनपर नियंत्रण भी जरूरी ०६ नोव्हेंबर २०१६

4) <https://iasgyan hindi.com>

5) <https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/india> 25 Sept 2020



3

ISSN 2279-0306

# International Journal of Physical Education Health & Sports Sciences

VOLUME : 11 (Special Issue)

MARCH 2022



## PEFI

### 6<sup>TH</sup> NATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL EDUCATION & SPORTS SCIENCES

DATE: 11 - 12 MARCH 2022, VENUE: NDMC CONVENTION CENTER, NEW DELHI

UNDER THE AEGIS OF

KNOWLEDGE PARTNERS

TECHNOLOGICAL PARTNERS



सत्यमेव जयते  
MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS  
Government of India



Lakshmbai National Institute of  
Physical Education,  
Gwalior, Madhya Pradesh



Lakshmbai National College of  
Physical Education,  
Thiruvananthapuram, Kerala



Gujarat  
Technological  
University  
ESTD-2007

## A JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION FOUNDATION OF INDIA

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION  
HEALTH & SPORTS SCIENCES

**TABLE OF CONTENT**

♦ Effect of Nadishodhan Pranayama in the Prevention And Treatment of High Blood Pressure / Junaid Ahmad Parrey, Dr Anil Mili	20
♦ Study of Selected Physiological Variables Between Female students of Akola and Dharani, Maharashtra / Lt. Shweta P.Mendhe	24
♦ Expectation and Perception of Education Service Quality among Perspective Physical Educationists: A Comparative Study / Abhishek Mohindra, Gurmeet Singh, Rakesh Mohindra, Mandeep	27
♦ Relationship between Academic Anxiety and Sport Competitive Anxiety among School State Level Cricketers / Anjan Kumar Biswas, Dr. Mahesh Sawata Khetmalis, Pathik Kabiraj	34
♦ Construction of JCR Test Norms for West Bengal / Asish Biswas, Prof. Madhab Chandra Ghosh	38
♦ Sports Psychology: The Subject we Cannot Aford to Skip / Bamang Meha	45
♦ A Therotical Study on Yoga And It's Multiple Benefits to Human Body / Mr. Basavaraj S Patil	50
♦ Effect of Eight Week Total Resistance Exercise on Selected Physical Fitness Variables Among Junior School Boys / Bidyarani Yumnam, Kh. Rajen Singh	53
♦ Kinematic Analysis of Performance of World Class Javelin Throwers / Biswajit Sharma, Kishore Mukhopadhyay	59
♦ A Comparative Analysis on the Achievement Motivation Among Handbal Players / Mr. Chandrakanth Shirolu, Dr. Jayashree Makawana	70
♦ Comparative Study on Yo-Yo Intermittent Endurance and Repeated Sprint Abiility of Three Diferent Bal Game Players / Dibyayan Ghosh, Gopal Chandra Saha	74
♦ Impact of Indian Traditional Games on physical fitness Development of Citizens / Dr Umesh Rathi	86
♦ Analysis of coaching behaviour between individual game female athletes / Dr. Lakhveer Kaur, Dr. Dalwinder Singh	89
♦ Chalenges and Trends in Physical Education / Dr. Rajni W. Bhojar	94
♦ Current Scenario of Sports Tourism in India / Dr. Sagar P. Narkhede	97



- ♦ Growth and Challenges in Physical Education in Modern Era / Dr. Seema V. Deshmukh
- ♦ Effect of Surya Namaskara and Swiming Practices on Flexibility Among Swimer's / Jagadish Gasti
- ♦ Effect of Yogic Exercises and Mental Health on the Performance of Trunk and Shoulder Flexibility of Sports Hostel Volleybal Players / Mr. Jaiprakash
- ♦ Influence of Psychological Factors on the Diferent Skills Test Performance of Men Footbal Players of Bidar District / Mr. Jaiprakash Samuel, Dr. Girwalkar Sunita S
- ♦ The Traditional Sports of Ladakh / Jigmet Stenzin
- ♦ The Consideration of Women Towards Physical Education & Sports in Bihar as a Career Option / Kumar Aditya
- ♦ Socio-Cultural Deprivation And Achievement Motivation Level Among Rural And Urban Women Athletes / Mr. Mallikarjun Sharanappa / Dr. Jayashree Makawana
- ♦ Chalenges And Future Research in Sports Entrepreneurship / Dr. Manjusha J. Deshmukh
- ♦ Perspectives for Public and Private Partnerships for Sports Development / Mr. Sachin J. Kokode
- ♦ Comparative Study on Happiness Level of Physically Active And Sedentary Students / Ms. Dakshita Singh, Dr. Madhavi Mardikar
- ♦ Physical Fitness Protocol for Minimizing Hypokinetic Diseases / Mursalim Shaikh, Kishore Mukhopadhyay
- ♦ A Comparative Analysis on the Performance Hockey Skil Tests Among Kalaburagi And Ballary District Sports Hostel Players of Karnataka State / Mr. Nagendra Bhimashankar, Dr. Jayashree Makawana
- ♦ Influence of Self Confidence on the Goal Kicking Ability And Game Proficiency of Collegiate Men Footbal Players of Dharawad District / Mr. Pavan Gorawar, Dr. Jayashree Makawana
- ♦ A Study on Personality And Self Confidece Among Inter-Collegiate Cricket Players / Dr. Prasannakumar Shivasharanappa
- ♦ Influence of Age Maturity And Income on Mental Health of National Volleybal Men Officials / Dr. Rajanna, Dr. Rajkumar G. Karve
- ♦ Effect of Yo ga Nidra on Stress of University Immigrant Students / Rajnish Chandra Tripathi
- ♦ Effect of Six Weeks Yogasana Training Programe on Agility And Flexibility Level of Hockey Players / Dr. Ravi G. Nayak

Gasti

110

- An Investigative Analysis on Vital Capacity To Suggest Sports Training Aspects For UAS Raichur Sports Persons / Dr. Rajkumar G. Karve 181
- A Comparative Study of Blood Lactate Clearance of Attackers and Defenders of Junior National Soccer Team of Tripura / Rupali Katoch, Krishnendu Dhar 188
- Connection of Sports and Happiness Among the Adults / Dr. Sangita N. Lohakpure 194
- A Comparative Analysis on Body Mass Index And Physical Fitness Performance Among Sports Hostel Boys Athletes of Hyderabad Karnataka Region / Mr. Sanjeev Kumar Appe, Dr. N. G Kannur 197
- Influence of Self Confidence And Achievement Motivation on the Performance of Junior And Senior Basketball Players Of Kalaburagi Division / Mr. Santosh Kumar Bikku Rathod, Dr. Minaxi Mansukhbhai Patel 205
- The Personality of Indian Olympian Basketball Player Sri. G. Dilip Through The Opinions of Relatives, Friends, Colleagues / Mr. Shankar Sure, Dr. M. S. Pasodi 210
- Comparative Analysis on the Coordination Abilities of Among Tall And Short Men Inter-Collegiate Basketball Players / Dr. Shivakumar 216
- Role of Women In Sports: Challenges And Development / Dr. Shubhangi Damle 221
- Impact of Yoga on the Immune System of The Human Body / SK Rasid Mahammad 224
- The Study of Effect of Physical Activity on Strength and Endurance of Students / Prof. Sunil G. Dhakulkar 230
- Impact of Plyometric Training on Long Jump Performance / Thomas M.A., Dr. Bhakt D.R. 234
- Comparative Study of Coordinative Abilities of Badminton of Buldana / Ulihas Vijay Bramhe 238
- A Comparative Analysis of Jump Shoot, Accuracy Throw, Obstacle Dribble Test Performances of Raichur And Bidar District High School Handball Players / Mr. Vijay Kumar, Dr. Jayashree Makawana 242
- Synthol Oil: A Killer Of Human Body / Vishwa Deep Kaushik 245
- Prevention of Doping in Sports / Anuj Shamsunadar Kela 251
- Social, Cultural, Economic and Environmental Impacts of Sport / Dr. Kalyan Maladhure 255
- The Role of Women in Sport and Sport Education Sport and Global Challenges / Dr. Santosh P. Tayde 260
- Sport, Sports Events and Community: Making Policies to link people / Dr. Kiran Vasantappa Mogarkar 264

# CONNECTION OF SPORTS AND HAPPINESS AMONG THE ADULTS

Dr. Sangita N. Lohakpure<sup>1</sup>

## ABSTRACT

As the worldwide populace a long time rapidly, from a high quality growing older view, selling later existence via recreation participation has been diagnosed as techniques for keeping and boosting the social and mental fitness of older human beings. To higher apprehend the position of recreation participation amongst older adults, the number one cause of the examine turned into to discover the mediating position of social capital on the connection among recreation participation and happiness amongst older adults. Having a "health fam" can imply greater than simply having a collection of human beings you may rely on to workout with you. When you connect to human beings which have shared values (like valuing your fitness and wellness) and hobbies (for something sort of exercising you do), there is routinely a higher risk that your dating can be even more potent because you percentage those things.

## INTRODUCTION

The duration of youth is one of the maximum critical intervals in an man or woman's existence. Adolescents generally undergo this era with problems because of each the guidelines they want to obey in faculty and home conflicts of their families. Responsibilities of existence laden on teenagers and the duration of improvement they undergo motive their troubles to boom and existence ought to emerge as greater complex for them. These situations on occasion pressure them to enjoy undesirable emotions greater intensely. Considering this expanded strain on people for the duration of the duration of youth, it can be said that they require diverse supportive mechanisms to address the troubles they enjoy. In this era, it can be feasible for them to address strain via diverse sports which includes sports activities sports and cultural and creative sports. Initiation of a high quality mind-set closer to sports activities in people might be a bonus for people. Engaging in sports activities sports ought to assist teenagers enhance their communique skills, adapt inside teamwork and thus, socialize. Adolescents who cautiously manipulate their time with sports activities additionally stand out amongst different teenagers with their athlete identification as wholesome teenagers each bodily and mentally and in social relationships. Today, it's far highlighted that sports activities play a widespread position withinside the socialization of people via way of means of enlarging their place of hobbies with a view to meet their diverse expectations. With the famous mind-set closer to sports activities in teenagers, acquisition of the terminal behaviors, which includes assertiveness and teamwork, additionally boom. With sports activities sports, teenagers additionally enhance themselves now no longer simplest bodily and mentally however additionally in phrases of capabilities of teamwork, self-discipline, chivalry, leadership, socialization and communique. The motives for maximum teenagers to have interaction in sports activities aren't simply constrained

<sup>1</sup> Director of Physical Education, Shri Dhabekar Arts college, Khadki, Dist. Akola

to motion and frame. Elements which includes the want for socializing with different people, worry of being by myself and the want for being a social creature have an effect on teenagers' mind-set closer to sports activities. Sports represent a widespread device of communicate that creates potentials and possibilities for affiliations. It is said that those who have interaction in sports activities advantage new social environments and new friendships. Sports are visible as social behaviors that attraction each to the frame and to the soul. Sports are powerful withinside the version of the man or woman to the society and in securing the bodily and intellectual fitness of people. As for loneliness, it's far described as "an unsightly and subjective mental scenario that arises from the inconsistency among the prevailing social family members of the man or woman and the preferred social family members" (9). Considering a lot of these studies, it can be said that high quality mind-set closer to sports activities ought to enhance people' socialization and assist people set up high quality relationships with their environment. In the literature, it's far emphasised that mind-set closer to sports activities is a widespread thing that impacts loneliness). The first speculation of this examine turned into based via way of means of thinking about the consequences of mind-set closer to sports activities on loneliness. (H1: The mind-set closer to sports activities in teenagers is related to loneliness significantly).

According to the World Health Organization (2019), it's far predicted that the variety of human beings elderly 60 years and older will outnumber kids below five years vintage indicating the tempo of populace growing older is getting greater rapid. When it involves a success growing older, from a nice growing older view evolved with the aid of using Havighurst (1961) primarily based totally at the hobby theory, selling a bodily lively life-style has been emphasised for keeping and growing the social and mental fitness of older human beings (Gilleard and Higgs 2002). Whereas growing older is taken into consideration an unavoidable declining technique inflicting fewer social interactions among the growing older character and others withinside the social machine from the conventional medicalized view (Cumming and Henry 1961), a nice growing older view acknowledges that a success growing older is viable via being lively and persevering with social interactions. From this perspective, many research were carried out on selling later existence as a duration of amusement, growth, creativity, independence and improvement, instead of truly that specialize in loneliness, disengagement, and decline (Gergen and Gergen 2001; Tornstam 2005). This line of nice growing older literature has inspired the fitness merchandising motion with the aid of using government, non-profit organizations, and commercial enterprise businesses all the world over reflecting a cultural emphasis on game, bodily hobby, workout, recreation, and amusement as techniques for keeping and boosting the social and mental fitness of older human beings (Gilleard and Higgs 2002; McPherson 1999).

In general, happiness refers to a subjective interpretation of one's existence or the state of affairs one is residing in (e.g., Diener et al. 2003; Keyes 1998; Layard 2005) that is an character's complete evaluation of each one's short-term feelings and a vast cognitive appraisal in their existence. Due to a sturdy reference to an character's fitness and great of existence, happiness has been a count number of brilliant hobby for researchers to examine diverse populations inclusive of older adults. In the extant literature, the bulk of the empirical research at the hyperlink among growing older and happiness located a U-formed dating amongst older adults even after controlling socioeconomic status (e.g., Blanchfower and Oswald 2008; Frijters and Beaton 2012; Goñoy-Izquierdo et al. 2013; Graham and Ruiz Pozuelo 2017). In different words, happiness has a tendency to say no from early maturity to the center maturity and turns returned up as we age. The underlying mechanism of this U-formed dating has been defined as better aspirations of teens than older adults and higher abilities of older adults to conform to the unmet aspiration state of affairs (Schwandt 2016). Nevertheless, Hellevik (2017) disputed that uncritically accepting the U-formed dating among age and happiness with out controlling existence circumstance variables is dangerous. Older adults are much more likely to address significant existence transitions along with lack of a spouse (Holland et al. 2013), bodily challenges (Fässberg et al. 2016), isolation or loneliness (Smith 2012), and lose of cause or existence hobby (Christensen et al. 1999), that can effect their happiness.

## Sport and mental health

The position of sports activities on this dialogue is clean. Not handiest are the long-time period fitness advantages of bodily hobby probably to make a contribution to extended mental well being but, withinside the short-time period, it's far widely known that workout reasons a secretion of endorphins, growing a 'herbal high' and assisting fight stress. Exercise is an alternative for assisting to deal with or save you despair and for this cause it's far prescribed with the aid of using medical doctors in lots of countries. Sports programmes are regularly used the world over as a rehabilitative tool, offering psychosocial assist for human beings suffering from trauma. Sport can sell self-self belief and the improvement of diverse abilities vital for fulfillment in employment, relationships and different regions of existence that effect a individual's basic well being.

## Sport and society

It isn't simply gamers and athletes which could locate happiness via game. Coaches, fit officials, floor workforce and every person else concerned can locate cause in game and it's clean that looking game, in individual or on television, brings quite a few amusement to human beings across the world. Sport also can play a position in growing the happiness of society as a whole. Well run programmes can, for example, have an effect on nearby crime rates, as a current Laureus Sport for Good Foundation booklet reported. Others might also additionally help network brotherly love with the aid of using selling the combination of migrants, preventing discrimination or selling communique among exclusive businesses in a post-war environment.

## A combination of factors

It's essential to be realistic, though, and understand that, in a few conditions and contexts, game can reason terrible emotions. The anger from time to time displayed with the aid of using fans, gamers and coaches in expert game is simply one example. Sport on my own will in no way assure a society's happiness and wellness but, while well-based and blended with some of different elements, it could be an essential component. Increasing the quantity of possibilities for human beings to get concerned in game in any respect tiers ought to be a concern for governments and communities.

## CONCLUSION

Having a "health fam" can imply extra than simply having a set of human beings you could depend upon to training session with you. When you hook up with human beings which have shared values (like valuing your fitness and wellness) and interests (for some thing kind of exercise you do), there is routinely a higher threat that your dating can be even more potent because you proportion those things. And specialists agree, having robust relationships and connections in existence is one of the maximum essential elements in basic happiness.

## REFERENCES

1. Abdel-Khalek, A. M. (2006). Measuring happiness with a single-object scale. *Social Behavior and Personality*, 34(2), 139–150. <https://doi.org/10.2224/sbp.2006.34.2.139>.
2. Ajrouch, K. J., Blandon, A. Y., & Antonucci, T. C. (2005). Social networks amongst guys and girls: The effects of age and socioeconomic status. *The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 60(6), S311–S317. <https://doi.org/10.1093/geronb/60.6.S311>.
3. Alesina, A., & Ferrara, E. L. (2000). The determinants of trust (No. w7621). National Bureau of Economic Research.
4. Asztalos, M., Wijndaele, K., De Bourdeaudhuij, I., Philippaerts, R., Matton, L., Duvigneaud, N., ... Cardon, G. (2012). Sport participation and strain amongst girls and guys. *Psychology of Sport and Exercise*, 13, 466–483. [10.1016/j.psychsport.2012.01.003](https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2012.01.003)
5. Baker, J., Horton, S., & Weir, P. (2010). *The Master's athlete: know-how the function of game and exercising in optimizing aging*. New York, NY: Routledge.

4

3

Impact Factor-8.632 (SJIF)

ISSN-2278-9308

# B.Aadhar

Single Blind Peer-Reviewed & Refereed Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

## March-2023

ISSUE No - (CCCXCVIII) 398 (B)

### A Journey of Indian women



6

**Chief Editor**  
**Prof. Virag S. Gawande**  
**Director**  
 Aadhar Social  
 Research & Development  
 Training Institute Amravati

**Editor**  
**Dr.V.R.Kodape**  
**Principal**  
 Shri Kisanlal Nathmal Goenka Arts & Com,  
 College Karanja (LAD) Dist. Washim

**The Journal is indexed in:**  
**Scientific Journal Impact Factor (SJIF)**  
**Cosmos Impact Factor (CIF)**  
**International Impact Factor Services (IIFS)**

For Details Visit To : [www.aadharsocial.com](http://www.aadharsocial.com)

Aadhar PUBLICATIONS



Impact Factor – (SJIF) -8.632

ISSN – 2278-9308

# B.Aadhar

Single Blind Peer-Reviewed & Refereed Indexed  
Multidisciplinary International Research Journal

**March- 2023**

ISSUE No - 398 -B

**A Journey of Indian women**

**Prof. Virag.S.Gawande**

Chief Editor

Director

Aadhar Social Research &, Development Training Institute, Amravati.

**Dr.V.R.Kodape**

Editor,

Principal,

Shri Kisanlal Nathmal Goenka Arts & Com,  
College Karanja (LAD) Dist. Washim

## Aadhar International Publication

For Details Visit To : [www.aadharsocial.com](http://www.aadharsocial.com)

© All rights reserved with the authors & publisher

67	ग्रामिण महिलांच्या मुलभूत समस्या आणि उपाय	कु.पायल केशवराव पाटील	277
68	ग्रामीण स्त्रियांचे आरोग्य, समस्या व उपाय	प्रा. प्रणिता थेर	280
69	भूमिहिन आंदोलन चळवळ: आणि नांदेड जिल्हयातील दलित स्त्रियांचे योगदान	छाया भिमराव उमरे	284
70	आर्थिक विकासात महिलांची भूमिका	प्रा. डॉ. नीता नंदलाल तिवारी	287
71	संस्कृती संवर्धनात महिलांचे योगदान व महीला सक्षमीकरण	प्रा. प्राची भांबुरकर	291
72	हिराबाई बडोदेकर यांचे नाट्य संगीतामधील योगदान	प्रा. विद्या प्र. गावंडे	294
73	भारतीय विकासाच्या वाटचालीत आदिवासी महिलांचे योगदान	डॉ. वैजनाथ अनमुलवाड	297
74	भारतीय चित्रपट आणि स्त्री	श्री. उज्वल राहुल शेगावकर	300
75	संगीत स्वरयोगिनी : 'पद्मविभूषण' डॉ. प्रभा अत्रेजी	प्रा. डॉ. कु.प्रिती बी. इंगळे (वाकपांजर)	303
76	स्वातंत्र्यपूर्व काळातील महाराष्ट्रीयन महिलांचे साहित्य रचनेतील योगदान	प्रा.भाऊराव रामेश्वर तनपुरे	307
77	मराठीतील दलित स्त्रियांची आत्मकथने : स्वरूप व वैशिष्ट्ये	संजय नामदेवराव आठवले	311
78	महिलांच्या सेवाभाव, नेतृत्व आणि शौर्यगाथा यामध्ये सावित्रीबाई फुले यांचे योगदान	प्रा रेखा दिगांबर आढाव	318
79	पंचायतराज व्यवस्थेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी	प्रा. डॉ. संतोष एस. मिसाळ	325
80	भारतीय स्त्री आणि कौटुंबिक स्वास्थ्य एक अभ्यास	प्रा. डॉ. ठकसेन दादारावजी राजगुरे	329
81	गर्भसंस्कारने गर्भवती महिलांचे स्वास्थ्य संवर्धन करुन बालकाच्या वाढ व विकासात योगदान देणे	प्रा. कु. जयश्री त्र्यंबकराव कात्रे	334
82	भारतीय शेती विकासात महिलांचे योगदान	डॉ. रमाकांत गजभिये	336
83	स्त्रीया आणि मानवाधीकार	डॉ. प्रसन्नजीत रा. गवई	339
84	लोककला विश्वातील लोकप्रिय महिला कलावंत लावणी सम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर	प्रा. जगन्नाथ इंगोले	342
85	विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओ का योगदान	डॉ. अंजुम नहिद रउफ खान	344
86	महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	प्रा. डॉ. जे. जे. जाधव	346





## पंचायतराज व्यवस्थेची ऐतिहासीक पार्श्वभूमी

प्रा. डॉ. संतोष एस. मिसाळ

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख श्री. धाबेकर कला महाविद्यालय, खडकी, अकोला

प्रस्तावना :-

भारत देश हा जगाच्या पाठीवर सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश असून अनेक राष्ट्रांमध्ये स्थित्यंतरे होत असतांनाही भारतात लोकशाही उत्तरोत्तर दृढ होत आहे. भारतीय राज्यघटनेत नागरिकांना प्राप्त झालेले विस्तृत अधिकार जगातील कोणत्याही राष्ट्रांच्या घटनेत आढळत नाही. लोकशाही हा या देशाचा आत्मा आहे. ग्रामीण भागातून तर सर्वोच्च स्थानापर्यंत भारतामध्ये लोकशाही यशस्वी झाली असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून आपल्या भागाचा विकास करून घेतला जातो. प्राचीन काळापासून भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. देशातील ८० टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते म्हणून भारताचा विकास म्हणजे ग्रामीण भागाचा (खेड्यांचा) विकास हे समीकरण बनले. भारतीय खेड्यांच्या विकासाची योजना १९५२ ला सामुहीक विकास योजना या नावाने देशात सुरू झाली व पुढील काळात याचे रूपांतर पंचायत राज यंत्रणेमध्ये करण्यात आल्याचे दिसून येते.

उद्दीष्टे :-

- १) पंचायत राज व्यवस्थेची ऐतिहासीक पार्श्वभूमीबाबत माहिती घेणे.
- २) पंचायत राज व्यवस्थेकरीता अस्तीत्वात आलेल्या निरनिराळ्या समित्यांबाबत माहिती घेणे.
- ३) पंचायतराज व्यवस्थेमुळे महिलांच्या सहभागाची माहिती घेणे. (महिलांचे झालेले सक्षमीकरण)— महिला नेतृत्व
- ४) पंचायत राज व्यवस्थेमुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाची नोंद घेणे.
- ५) प्राचीन काळापासूनच पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात होती.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा इतिहास :-

प्राचीन काळापासून इतिहासामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा उल्लेख आढळतो. प्राचीन काळात अधिकार संपन्न संस्थांच्या उल्लेख आढळतो. तसेच सुख-संपन्न गावांचाही उल्लेख इतिहासकारांनी केल्याचे आढळते. भारतात ग्रामपंचायत ही प्राचीन काळापासून ग्रामीण जिवनाचा एक अविभाज्य भाग होता. वैदिक काळात सभा व समिती ह्या संस्थांचा उल्लेख आढळतो. वैदिक काळात ह्या संस्था राजावर नियंत्रण ठेवण्याचे व न्यायदानाचे कार्य करित. जनहिताची कार्ये न करणाऱ्या राजांना सभा व समितीने पदावरून दूर केल्याची उदा. वैदिक काळात आढळतात. राजा स्वतः सभा समितीच्या बैठकीत उपस्थित राहत असे. यावरून सभा समितीचे महत्व लक्षात येते. जनपद, महाजनपद इ. संस्थांचाही उल्लेख येतो. बौद्ध साहित्यानुसार इ.स. पूर्व ६ व्या शतकाच्या प्रारंभी भारतात १६ महाजनपदे होती. काही गणराज्ये अस्तीत्वात होती. या गणराज्यांचे प्रशासनीक कार्य आधुनीक काळातील लोकशाहीप्रमाणे चालत होते. म्हणजेच सार्वभौम सत्ता जनतेच्या हातात होती. जनता आपले प्रतिनिधी निवडून देत असे. तत्कालीन ग्रिक याकाळातील लेखकांनी उत्कृष्ट प्रशासन व्यवस्था व ग्रामप्रशासन व न्यायव्यवस्थेचा उल्लेख आढळतो. चंद्रगुप्त मौर्याची राज्यव्यवस्था कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र या ग्रंथावर आधारित होती. तर मौर्यांच्या प्रशासन व्यवस्थेची माहिती मेगॅस्थॅनीसच्या इंडीका या ग्रंथावरूनही मिळते. चंद्रगुप्त मौर्याची राज्यव्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्याच्या मृत्यूनंतर एकशे अकरा वर्षे कायम होती.

केंद्रिय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन व स्थानीय प्रशासन, नगर प्रशासन व ग्रामप्रशासन हे चंद्रगुप्त मौर्यांच्या प्रशासन व्यवस्थेचे वैशिष्ट्ये होते. राज्यकारभाराच्या सोईकरीता साम्राज्याचे अनेक प्रांतात विभाजन करण्यात आले होते. याचा कारभार (समाहर्ता) राजप्रतिनिधी पाहत, तर प्रांताचे विभाजन अनेक विषयामध्ये करण्यात आले होते. यावरील अधिकार्याला विषयपती संबोधले जात होते. जनपदावर स्थानिक हा प्रमुख अधिकारी होता. त्यापेक्षा लहान भागावर असलेल्या, अधिकार्याला गोप तर सर्वात शेवटचा घटक म्हणजे ग्राम होय. यावरील प्रमुखाला ग्रामीक किंवा ग्रामणी म्हणत. ग्रामीण भागात प्राचीन काळात तलहाठी शब्दाचा वापर होत असे. या अधिकार्याकडे



ग्रामीण महसूल वसुलीचे कार्य असे यावरून आधुनिक काळातील तलाठी व ग्रामीक व ग्रामणी पासून ग्रामसेवक शब्द अस्तीत्वात आला. नगरप्रशासनात विविध समित्या अस्तीत्वात होत्या. यामध्ये आरोग्य, पाणीपुरवठा, सफाई, मनोरंजन, शिक्षण व सार्वजनिक कल्याणाची कामे सामुदाईक जबाबदारीने पार पाडले जात. प्राचीन काळात सर्वसम्मत निर्णय, निष्काम भावनेने व त्यागपूर्वक कार्य केली जात. रामायण, महाभारत काळात गावांच्या संख्येचे सुव्यवस्थीत व सुस्पष्ट वर्णन आढळते. रामायणात राष्ट्रीय प्रशासनात गावाचे महत्त्व तसेच भूमीकेचा उल्लेख मिळतो. रामायणात राजकर्तार ! पद आहे. रामायण युगात जतपदांचे अस्तीत्व होते. तसेच ग्रामप्रमुखाला ग्रामणी संबोधण्याचा उल्लेख मिळतो.

गुप्तकाळ :-

गुप्तकाळ व मौर्यकालीन प्रशासनात बरेच साम्य होते. उत्तर व दक्षिण भारतात परंपरागत मुखीया होते. गावाचे प्रशासन ग्रामाध्यक्ष नावाचे पद धारण करणाऱ्या प्रमुख व्यक्तीकडे होते. ग्रामीण भागातील सर्व प्रशासनाची जबाबदारी व न्यायदानाचे कार्येही ग्रामीण भागातच पार पाडले जात. एकंदरीत आधुनिक काळातील प्रशासनापेक्षा वास्तववादी व यशस्वी प्रशासन प्राचीन काळात असल्याचे स्पष्ट होते.

मोगलकाळ :-

मोगल प्रशासन काळातही भारताच्या ग्रामीण व्यवस्थेला धक्का लागला नाही. एखादा सुलतान व सम्राट बदलल्यास त्याचा ग्रामीण जिवनावर कोणताच फरक पडत नसे. या काळातही ग्रामीण प्रशासन व्यवस्थेत फारसे बदल झाले नाही. गावातील मुखीयाचे पद महत्त्वपूर्ण होते. त्याला पटेल संबोधले जायचे त्याच्या हाताखाली विविध विभाग होते व त्यानुसार ग्रामप्रशासनाचे कार्य पार पाडले जात असे. सुलतानशाही काळातील साम्राज्याची विविध भागात विभाजन करण्यात आले होते. प्रांताना इत्ना तर अल्लाउद्दीन खिलजीच्या काळात याला सुभा संबोधण्यात येत असे. याची रचना आधुनिक काळातील राज्याप्रमाणे होती. सुभ्याचे लहान भाग परगणा होते. परगण्यावर चौधरी नावाचे अधिकारी होते तर ग्राम प्रमुखाला महत्त्वाचे स्थान होते. मराठा सत्तेच्या काळात देशमुख, देशपांडे, पाटील, कुळकर्णी यांच्याकडेच गावाच्या कारभार होता. ग्रामीण भागातील स्वतंत्र वृत्ती व ग्रामप्रशासनाचे स्वतंत्र अस्तीत्व व कार्य यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांना मराठा राज्य निर्माण करतांना या घटकांची बहुमोल मदत झाली.

ब्रिटीश सत्ताकाळात ह्या संस्था काही प्रमाणात अस्तीत्वातही होत्या व बऱ्याच प्रमाणात यांचे अस्तीत्व कमी झाले होते. ब्रिटीशांना या संस्थांच्या महत्त्वाबद्दल माहिती नसल्यामुळे त्यांनी पंचायतींना नाकारले मात्र ब्रिटीश शासनांना पंचायतराज संस्थांचे महत्त्वाचे अनुभव आल्यानंतर त्यांनी ह्या संस्थांना शक्तीशाली बनवण्याकरीता प्रयत्न केले. मात्र त्यांनी ग्रामीण स्वशासनाच्या स्थानावर अधिकारी तंत्राला महत्त्व दिले. परंतू ब्रिटीशकाळात गावाची आत्मनिर्भरता नष्ट होऊन पंचायत व्यवस्थेत शिथिलता आल्याचे दिसून येते. इ.स. १८८२ पासून भारतात प्रतिनिधी स्थानीक संस्थांचा प्रारंभ झाला. इ.स. १८७० ला स्थानिक स्वशासनाच्या विकासातील एका नवीन अध्यायाला सुरुवात झाली. लॉर्ड रिपन भारतातील स्थानिक स्वशासनाचा पिता मानला जातो. लॉर्ड रिपनने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाद्वारे ब्रिटीश शासनाच्या अधिन सर्व गावांपर्यंत कायदेशीररित्या स्थानीक स्वशासनाचा विस्तार केला. यामुळे स्थानीक संस्थांना लोकतंत्रीय आधारावर स्थापित करण्याचा प्रशंसनीय प्रयत्न करण्यात आला.

महात्मा गांधीजींचे पंचायत संबंधी विचार :-

म. गांधीजींची आदर्श ग्राम योजना आदर्श होती. गांधीजींच्या मते आदर्श गाव या प्रकारे असावे की घरामध्ये पुरेसा प्रकाश व हवा येऊ जाऊ शकेल. गावातच अशा वस्तू बनवल्या जातील ज्या पाच मैलाच्या सिमेच्या आत उपलब्ध असतील, प्रत्येक घराच्या मागेपुढे मोठे आंगण असेल ज्यामध्ये नागरीकांना आपल्याकरीता भाजी-पाला लावू शकतील व आपल्या पशूंना ठेवू शकतील, गावाच्या गल्ल्यां व रस्त्यावर धूळ नसेल, आवश्यकतेनुसार गावात विहारी असतील तेथून सर्व गावकरी पाणी भरतील. सर्वाकरीता प्रार्थना मंदीर असेल, सार्वजनिक सभेकरीता वेगळं ठिकाण असेल. एकंदरीत स्वयंपूर्ण ग्रामीण व्यवस्था असावी. गावातील गरज गावातच बागविल्या जाव्यात, खेडे स्वयंपूर्ण असावे हे म. गांधीजींचे स्वप्न होते.

गांधीच्या मते स्वातंत्र्याचा अर्थ म्हणजे देशातील सर्वच लोकांचे स्वातंत्र्य असायला पाहिजे. केवळ जनतेवर शासन करणाऱ्यांचे स्वातंत्र्य गांधीजींना अपेक्षित नव्हते. शासनाने लोकांच्या व्हायला हवे. प्रत्येक गावात पंचायतराज येईल त्यांचे पूर्ण सत्ता व ताकत असेल. एकंदरीत गावाने स्वयंपूर्ण बनून आपल्या आवश्यकता पूर्ण करून घ्यायला हव्यात कारण गावातील हा आपला कारभार सर्व स्वतः चालवतील. म. गांधीजींच्या आदर्श ग्राम स्वयंपूर्ण खेडी मुळेच, गांधीजींना आधुनिक भारतातील ग्रामीण स्वराज्याकरीता ग्रामपंचायतचे सर्वात मोठे शिल्पकार संबोधले जाते. देशातील ८० टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते त्यांना सुखी, संपन्न व स्वावलंबी बनविल्याशिवाय स्वतंत्र भारताची कल्पना केली जाऊ शकत नाही. त्यांच्या मते भारताचा आत्मा गावात आहे. जोपर्यंत गाव स्वतंत्र होणार नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळाले असे म्हणता येणार नाही.

स्वातंत्र्य प्राप्तीपूर्वी (आर्थिक, सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात) उद्धवस्त झालेल्या भारताचा स्वातंत्र्य प्राप्त केल्यावर सर्वांगीन विकास घडवून आणल्याचे मोठे ध्येय भारत सरकारसमोर होते. खेड्याच्या विकासाशिवाय देशाचा विकास अशक्य या गांधीजींच्या विचाराप्रमाणे स्वातंत्र्यानंतर खेडे विकासाचे अनेक कार्यक्रम आखण्यात आले. २ ऑक्टो. १९५२ ला सामुदायीक विकास कार्यक्रम व या कार्यक्रमाचे विस्तारीत रूप म्हणजे ३ ऑक्टो. १९५३ चा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम होय. याचा उद्देश लोक सहभागातून ग्रामीण विकास घडवून आणणे व ग्रामीण नागरीकांच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात परिवर्तन करणे हा होता. पुढील काळात पंचायतराज समित्यांमध्ये सुधारणा, बदल योजना इ. करीता विविध समित्यांची स्थापना करण्यात आली. यानुसार विविध समित्यांना सखोल अभ्यास करून आपले अहवाल शासनाला सादर केले. विविध सुधारणा व बदलांच्या प्रक्रियेमधून ताऊन सुलाखून आधुनिक काळातील पंचायत राजव्यवस्था कार्यरत आहे. यामुळेच भारतीय लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण घडून आले. बलवंतराय मेहता समिती, अशोक मेहता, रूपाली राव समिती, सिंघवी समिती इ समित्यांच्या शिफारसी व अभ्यास आधुनिक काळातील पंचायतराज व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल ठरले.

आधुनिक काळातही ग्रामसभेला जास्त अधिकार असावे अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व सामाजिक संघटना करत आहे. महाराष्ट्रातही काही ग्रामसंघटनांचे कार्य निश्चितच प्रशंसनीय आहे. महाराष्ट्र शासनाद्वारा विविध स्वरूपाचे पुरस्कारही प्रदान करण्यात येत आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांना शासनामार्फत आरक्षण प्राप्त असल्यामुळे त्यांना आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवता आला. आधुनिक काळात पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये महिलांचे प्रमाण मोठ्य प्रमाणात असून ग्रामीण भागाचा विकास घडवून आणाव्यात पंचायत राज व्यवस्थेचे योगदान मोठ्य प्रमाणात असल्याचे दिसून येते.

७३ व्या घटनादुरुस्तीने महिलांना पंचायत राजव्यवस्थेमध्ये १/३ जागांचे आरक्षण मिळाले. त्यानुसार ग्रामीण भागातील महिला राजकीय प्रक्रियेत सामील झाल्या. संपूर्ण भारतात २३ घटक राज्यात एकूण पंचायत समितीमध्ये सहभागी होणारे सदस्य १,२९,८२९ आहेत. त्यात ३८,०१२ महिला आहेत. ज्याचे प्रमाण ३१.३७ टक्के आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर व पंचायत समितीस्तरावर ३३ टक्के सहभाग आढळतो. कर्नाटक, तामिळनाडू, उडिसा व मणिपूर या घटक राज्यात तिन्ही स्तरावर निर्वाचित महिलांचे प्रमाण ३५ से ४० टक्के आहे. मणिपूर सारख्या छोटयाशा घटक राज्यात तिन्ही स्तरावर निर्वाचीत महिलांचे ४० टक्के च्या आसपास आहे. एकूण ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे २४३ कलमानुसार पंचायतीत एकूण संख्येच्या १/३ जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. पंचायत अध्यक्ष पद सुद्धा प्रत्येक स्तरावर १/३ महिलांसाठी आरक्षित आहेत. परिणामतः पंचायत व्यवस्थेत स्तरावर ७,६८,५८२\* ह्य आणि सरपंचपदी ३८,५८२ ह्य महिला सत्तेत सहभागी झाल्यात.

निष्कर्षः

- १) भारतात प्राचीन काळापासूनच ग्रामीण भागात पंचायतराज व्यवस्था अस्तीत्वात होती.
- २) प्राचीन काळापासूनच भारतात पंचायतराज व्यवस्था अस्तीत्वात होती व आधुनिक काळापेक्षाही जास्त वास्तववादी व कार्यक्षम प्रशासन अस्तीत्वात होते.
- ३) ब्रिटीशांच्या काळात पंचायत व्यवस्थेला काही प्रमाणात अवकळा आली मात्र ब्रिटीशांनी पुढील पंचायत व्यवस्था बळकट केली मात्र अधिकारी तंत्राला महत्व दिले.



- ४) म. गांधीजींची आदर्श ग्रामची संकल्पना आजही फारशी यशस्वी झाली नाही.
- ५) पंचायतराज व्यवस्थेमुळे महिलांचा राजकारणातील सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढला.
- संदर्भ :
- १) पंचायत राज डॉ. वा. भा. पाटील
  - २) प्राचीन भारताचा इतिहास (प्रारंभापासून ते १५२६) — दिक्षीत
  - ३) महाराष्ट्र प्रशासन डॉ. वा. भा. पाटील
  - ४) प्राचीन भारतीय संस्कृती व सभ्यता — कोसंबी डी.डी.
  - ५) भारतातील स्थानीक स्वशासन — विशेष संदर्भ, महाराष्ट्र राज्य, के. आर. बंग
  - ६) आधुनिक महाराष्ट्राचे राजकारण — व.म. सिरसीकर
  - ७) प्राचीन भारताचा इतिहास— डॉ. कठारे अनिल



# Vidya Bharati Mahavidyalaya, Camp, Amravati (M.S.)

Vidya Bharati Shaikshnik Mandal, Amravati's

C. K. Naidu Road, Camp, Amravati- 444 602

- \* Re-accredited with 'A' Grade by NAAC in Three Cycles Consecutively.
- \* CPE Status by UGC- Thrice \* Mentor College under Paramarsh Scheme of UGC
- \* Lead College by SGB Amravati University, Amravati. ISO Certification 9001: 2015
- \* Green Award Certification.



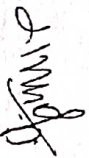
## National Conference on 'New Directions in Humanities'


Date: February 17th, 2023

### CERTIFICATE

This is to certify that श्री. अमरेश एच. तांडे श्री एलेकर कला महाविद्यालय, अकोला  
has participated / Presented Paper / Worked as a Resource Person / Chaired Session in National Conference on 'New Directions in Humanities'  
organized by Vidya Bharati Mahavidyalaya, Amravati on February, 17th, 2023 and presented a paper on \_\_\_\_\_

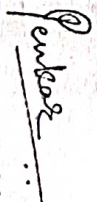
श्री. अमरेश एच. तांडे

  
Dr. R. M. Patil  
Organizing Secretary

  
Dr. A. D. Chauhan  
Organizing Secretary

  
Dr. S. D. Wakode  
Organizing Secretary

  
Dr. P. G. Bansod  
Coordinator, IQAC

  
Dr. Pradnya S. Yenkar  
Principal

Impact Factor-8.575 (SJIF)

ISSN-2278-9308

# B.Aadhar

Single Blind Peer-Reviewed & Refreed Indexed  
Multidisciplinary International Research Journal

FEBRUARY 2023

New Directions in Humanities



VOLUME - B

**SOCIAL SCIENCES  
AND HUMANITIES**

Words in the cloud include: Trends, Group behaviour, Record Recipe, Nutrients, Identity, Secondary source, Inquiry, Garments, Behaviour, Cognitive, Nutrition, Investigate, Psychology, Bias, Food preparation, Food security, Regulations, Communicate, Assets, Analyse, Children, Metabolism, Fabrics, Human origins, Culture, Primary source, Anthropology, Infant, Research, Injustice, Parent, Design, Fashion, Mental Health, Thesis, Human mind, Equality, Family.

Chief Editor  
Prof. Virag S. Gawande  
Director  
Aadhar Social  
Research & Development  
Training Institute Amravati

Editor  
Dr. Pradnya S. Yenkar  
Principal,  
Vidya Bharati Mahavidyalaya,  
Camp, Amravati



- This Journal is indexed in :
- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
  - Cosmos Impact Factor (CIF)
  - International Impact Factor Services (IIFS)

For Details Visit To : [www.aadharsocial.com](http://www.aadharsocial.com)

Aadhar PUBLICATIONS

**INDEX**

No.	Title of the Paper	Authors' Name	Page No.
1	Pandemic stress and challenges in education	Dr. Vikas T. Adlok , Dr. Govind M. Tirmanwar	1
2	Challenges for Academic Libraries in Pandemic COVID 19	Dr. Vishalsingh Rameshsingh Shekhawat	4
3	Pandemic and Psychophysical Health Challenges	Dr. Sheetal Shinde	9
4	Impact of pandemic Covid-19 on Fisheries	Dr. Anju P. Khedkar (Vikhar)	11
5	New Challenges in psycho-physical health in post-covid-19	Dr. P. B. Ingle	14
6	Historical Perspective of Pandemic in India	Prof. P. D. Shrugare	17
7	A Study on Use of Technology in Education: An Opportunity or A Challenge	Dr. Pallavi Mandaogade (Jain)	21
8	The Relationship of Humanities to other Knowledge Domains	Prof. Dr. Ananda B. Kale , Prof. Manisha Kirtane	26
9	R.K. Narayan's Malgudi days: The mirror of Society	Savita.M. Lonare	28
10	Student's Perspectives On Learning Physics During Pandemic	R. B. Butley	30
11	Use of Surprise and Twist in the Short Stories of O. Henry	Prof.V.P. Shekokar	35
12	A study of the Mental Stress and Mental health of Police Employee during Corona period	Vidhya T. Ambhore	37
13	Relationship Between Narcissism, Social Media Use And Self Esteem	Sonali Ramesh Khandekar , Dr. Shafiq Yusufkhan Pathan	42
14	Use of Technology in Education during the Pandemic	Dr.Suraj K. Rodde	47
15	कोवीड-19 कालावधीनंतर महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या मानसिक स्वास्थ्याचा अभ्यास	वैशाली ढोले , रमेश पठारे	50
16	कोविड-१९ साथीच्यारोगाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा आर्थिक व सामाजिक परिणाम	प्रा. दिपाली अनुल पडोळे	58
17	कोव्हीड नंतरचे मानसिकस्वास्थ, आव्हाने व उपाय	डॉ. गजानन र. रत्नपारखी	60
18	शिक्षण आणि आव्हाने	डॉ. दामोदर दुधे	63
19	नंदा खरे यांच्या साहित्यातील नवजाणिवा	अभिजित अशोक इंगळे	67
20	शैक्षणिक समस्यांचे विश्लेषणात्मक अध्ययन	प्रा. अमरिश एस. गावंडे	70
21	डॉ. सुखदेव ढाणके यांच्या पिंडपातविषयी - आशयअभिव्यक्ती	कु. ज्येती भिकुसा शेंदुरजणे , प्रा. गजानन बनसोड	74



## शैक्षणिक समस्यांचे विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रा. अमरिश एस. गावंडे

प्रमुख, समाजशास्त्र विभाग श्री. धाबेकर कला महाविद्यालय, खडकी, अकोला

प्रस्तावना :

अश्व म्हणजे घाडे, प्रत्येक घोडा पाहणे, त्याचा खरारा करणे, त्याच्यावर मांड ठोकणे, त्याला गाडीला जुपणे हे त्यात कोठेही नाही. शब्द आला की ज्ञान झाले अशी वाळवोध विचारपध्दती त्यात आहे. अदी क्रिकेट सुध्दा पटांगणत खेळायची गोष्ट नव्हे कि 'वा पाहण्याची सुध्दा गोष्ट नव्हे. तर बोलण्यापुरते किंवा एकमेकांना आकडेवारी सांगण्यापुरते. सारांश मैदानी खेळ म्हणजे फार तर टीव्ही वर पाहण्याचा खेळ एवढेच.

शिक्षणशास्त्रातले नवे नवे शब्द आणि ते सुध्दा इ ग्लिश या एकचा खिडकीतून येणारे. हे शब्द व चित्रे सध्या इंटरनेट जमान्यात फार वेगाने आपल्याकडे येते व हवेत विरतात. याचमुळे शिक्षणात अनेक समस्या निर्माण होतात. जगभरात अनेक देश परस्परांमधल्या कलहाने पोखरले आहेत. संपूर्ण मानव जातीच्या समोरची मुख्य समस्या म्हणजे शिक्षणाचा न्हास. यावेळी गरज आहे मानवाच्या अस्तित्वाबरोबर त्याचे कल्याण साधण्याची. यासाठी आवश्यकता आहे शिक्षणाची जागतिकीकरण, आधुनिकीकरण, याच्या रेट्याने समाज पूर्णपणे

प्रत्येक देशाचा विकास हा त्या देशातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा विकास आधारित असतो व शिक्षणाचा दर्जा हा त्या देशातील शिक्षकांवर असतो शिक्षकाची गुणवत्ता ही शिक्षक शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर आधारित असते. पर्यायाने शिक्षक शिक्षणाच्या गुणवत्तेसंदर्भात प्रत्येक देशाने गांभीर्यनि विचार करून योग्य ती पावले उचलणे गरजेचे आहे आणि जर शिक्षण शिक्षकाचे काही भविष्य नसेलतर निश्चितच देशाच्या विकासाला बाधा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिक्षक शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा विचार करणे गरजेचे आहे

शिक्षक शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे निकष व त्याच्या मापनाच्या पध्दती आज निश्चित आहेतच असे नाही. तरीही नॅकने शिक्षक शिक्षणाच्या गुणवत्तेविषयी सात घटकांसदर्भात विचार केलेला आहे. त्यामध्ये अभ्यासक्रम नियोजन व रचना, अभ्यासक्रम संक्रमण व मूल्यमापन, संशोधन विकासकार्य व विस्तारकार्य, भौतिक सुविधा व अध्ययन स्रोत संघटन व व्यवस्थापन, विद्यार्थी विकास व चैतन्यदायी अभ्यासक्रम संदर्भात विचार केला तर निश्चितच शिक्षक प्रशिक्षणातून विद्यार्थी पालक व समाज व राष्ट्राच्या गरजांची अपेक्षांची पूर्तता करणारा शिक्षक हा तावून सुलाखून बाहेर पडेल.

अध्ययन पद्धती :

सामाजिक घटनांचे वैज्ञानिक पद्धतीने अध्ययन करून कार्यकारण संबंध प्रस्थापीत करणे आणि ज्ञान वाढविणे यास सामाजिक संशोधन असे म्हणतात. सामाजिक शास्त्रामध्ये संशोधन करित असतांना तथ्य संकलन आणि तथ्यांचे विश्लेषण व निर्वचन करण्यास महत्व आहे. या संदर्भात पॉलिंग यंग असे म्हणतात, की 'क्रमबद्धता, अर्तगत संबंध, सामान्य स्पष्टिकरणे आणि नैसर्गिक नियम यांच्या द्वारे नविन तथ्य शोधून किंवा जुन्या ज्ञानाची पडताळणी घेण्याची सामाजिक संशोधन हि एक पद्धतशीर प्रक्रिया आहे.' प्रस्तूत शोध निबंधामध्ये वृद्धांच्या सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांचे अध्ययन करण्यात आले आहे. अध्ययन करित असतांना संशोधन पद्धतीचा यथोजित वापर करण्यात आला आहे. प्रस्तूत शोध निबंधामध्ये तथ्य संकलनासाठी नमुना निवड करतांना संभाव्यता नमुना निवड पद्धतीमधील यादृच्छिक पद्धतीचा वापर करण्यात आला असून लॉटरी पद्धतीने नमुना निवड करण्यात आली आहे. संशोधनामध्ये वस्तुनिष्ठता निर्माण करण्यासाठी काही अंशी गैर संभाव्यता नमुना निवड पद्धतीचा आधार सुद्धा घेण्यात आला आहे.

सामाजिक शास्त्रामध्ये अध्ययन करित असतांना तथ्य संकलन अत्यंत महत्वाचे आहे. तथ्य संकलन नही वैज्ञानिक पद्धतीची पहीली आणि महत्वाची अट आहे. कारण अभ्यास विषयासंबंधीचे निष्कर्ष अधिक वस्तुनिष्ठ व सर्वमान्य होण्यासाठी तथ्यांचा आधार घ्यावाच लागतो. सामाजिक संशोधनामध्ये अनुभवजन्य तथ्य संकलित करावी लागतात. त्यांच्याच आधारावर निष्कर्षांचे प्रतिपादन केले जाते. तांत्रिक साधनांच्या माध्यमातून संकलीत तथ्यांच्या विश्वसनीयतेवर संशोधनाचे यशापयश





अवलंबून असते. तथ्य संकलन हे संशोधनामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. या संदर्भात प्रसिद्ध विचारवंत गुड आणि हॅट असे स्पष्ट करतात, की 'तथ्य एक अनुभव शिद्ध सत्यापनीय निरीक्षण आहे.' प्रस्तुत शोध निबंधामध्ये प्राथमिक तथ्यसंकलन पद्धतीमधील मुलाखत अनुगृहीत्या माध्यमातून तथ्य संकलन करण्यात आले आहे. तसेच दुय्यम तथ्य संकलन पद्धतीचा वापर तथ्य संकलनासाठी करण्यात आला आहे. दुय्यम तथ्य संकलन पद्धतीमधील प्रकाशित आणि अप्रकाशित कागदपत्र, अहवाल लेख, पुस्तके, वर्तमान पत्रे, साह्याकिय माहिती, जणगणना अहवाल इत्यादींचा वापर करण्यात आला आहे.

शोध निबंधाचे त्रेश :

कोणत्याही शोध कार्यला योग्य दिशेने पूर्णत्वास नेण्याकरीता शोध कार्याचा त्रेश निश्चित असणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत शोध निबंधाचे त्रेश पुढील प्रमाणे स्पष्ट करता येतील.

- १) वृद्धांची आर्थिक स्थिती अभ्यासणे.
- २) वृद्धांच्या सामाजिक स्थितीचे अध्ययन करणे.
- ३) वृद्धांच्या आरोग्याच्या समस्यांचे अध्ययन करणे.
- ४) वृद्धांची मानसीक स्थिती अभ्यासणे.
- ५) वृद्धांच्या कौटुंबीक स्थितीचे अध्ययन करणे.
- ६) वृद्धांचे वर्तमान परिस्थितीमधील दर्जाचे अध्ययन करणे.

तथ्यांचे विश्लेषण आणि निर्वचन :

प्रस्तुत शोध निबंधामध्ये वृद्धांच्या सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांचे अध्ययन करण्यात आले आहे. प्राथमिक आणि द्वितीयक तथ्य संकलनाच्या पद्धतीच्या माध्यमातून प्राप्त तथ्यांचे विश्लेषण आणि निर्वचन करून वैज्ञानिक पद्धतीच्या आधारे वास्तविक निष्कर्ष प्रतिपादन करण्यात आले आहेत. गृहितकृत्याच्या वा संशोधन समस्येच्या किंवा एखाद्या सिद्धांताबाबत संकलित तथ्यांवर विचार करून त्यांचे विश्लेषण केले जाते. तथ्यांचे विशिष्ट प्रकारे संघटन करून सिद्धांताची किंवा गृहितकृत्यांची पडताळणी करता यावी किंवा नवीन सिद्धांत मांडता यावा याकरिता विश्लेषण करणे आवश्यक असते.

ज्ञानमंदिरात दिले जाणारे ज्ञान जागतिक संकटामुळे बंधनात आहे. मार्च पासून ही ज्ञानमंदिरे विद्यार्थ्यांविना ओस पडली आहेत. या परिस्थितीत नवीन शैक्षणिक वर्षाची चाहूल लागली. पालकांना प्रश्न पडू लागला. शाळा कधी सुरू होणार आणि या मुलांचे शिक्षण शाळेत कधी सुरू होणार? आता पालकही मुलांच्यामुळे घरी अडून बसले. आपल्या पाल्याच्या तावडीतून आपली सुटका कशी होणार? या विवचनेत पालक पडले.

कोरोना महामारीने मात्र जगाला बदलायला भाग पाडले. (म्हणूनच डार्विनचा उत्क्रांतीचा सिद्धांत आठवडा) त्याचा एक भाग म्हणून ऑनलाइन शिक्षण पद्धती सुरू होती. पण ती आता जोर धरू लागली. व्हॉट्सअप, दीक्षा अॅप, यू ट्यूब, झूम अॅप, गुगल मीट, विविध शैक्षणिक व्हिडिओज, सीडी, चॅनेल्स, शैक्षणिक वेबसाईट यांच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यासाठी वातावरण तयार झाले. या ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीत सर्वांना कुतूहल वाटायला लागले.

मुलांच्या शिक्षणासाठी पालकांनी अँड्रॉईड मोबाईल, टॅब, लॅपटॉप, डेस्कटॉप खरेदी केले. मुले शिक्षणात दंग झाली. नंतर समस्या यायला लागल्या. ग्रामीण भागात नेटवर्क नाही. पावसाळा सुरू झाला, वीज नाही. त्यामुळे मोबाईल चार्ज होत नाही. काही ठिकाणी झूम अॅप द्वारे शिक्षण घायला सुरवात झाली पण मुलांच्या गोंगाटाला आवरणे अवघड होऊन बसले. शिक्षक व्हॉट्स अॅपवर पीडीएफ स्वरूपात पाठाची माहिती पाठवू लागले. स्वतः तयार केलेले व्हिडिओसुद्धा पाठवले. मुलेसुद्धा या गोष्टी नवीन असल्याने आकृष्ट झाली. आता एकेक समस्या पुढे येऊ लागल्या. मुले मोबाईल, टॅब, लॅपटॉप यांचा शिक्षणासाठी वापर न करता कार्टून बघणे, इतर कार्यक्रम बघण्यात दंग होऊ लागली. शिकणे हा मूळ उद्देश वाजूला झाला. मुले या स्क्रीनवर जास्त वेळ राहिल्याने डोळ्यांच्या समस्या निर्माण झाल्या. मुलांचे मैदानी खेळावरचे लक्ष कमी झाले. व्यायाम कमी झाला. मुले मोबाईल, टीव्ही यातच अडकून पडली. सध्याच्या काळात मुलांना घरी आवरणे पालकांना अवघड होऊन बसले आहे. कारण मुले पालकांचे ऐकत नाहीत, हट्टी, चिडचिडी झाली आहेत.



कोरोनाला रोखण्यासाठी अनेक देशांनी शिक्षणसंस्थासुद्धा बंद केल्या आहेत. 'युनेस्को'च्या अहवालानुसार एप्रिल २०२० मध्ये १८८ देशांत १५४ कोटी विद्यार्थी घरी बसले आहेत. भारतात १५ लाख शाळा बंद होत्या. त्यामुळे २६ कोटी विद्यार्थी व ८९ लाख शिक्षक घरी बसले आहेत, तर उच्च शिक्षणात ५० हजार शिक्षणसंस्था बंद आहेत व ३.७० कोटी विद्यार्थी आणि १५ लाख महाविद्यालयीन शिक्षक घरी बसले आहेत. ३० कोटी विद्यार्थ्यांनी रिकामेपणे घरी बसणे हा एक टाइमबॉम्ब आहे. सध्या कोरोनाची समस्या ही कोवळ आरोग्याची समस्या आहे, असे मानले जात आहे. पण या संकटाला शैक्षणिक समस्यांची नाजू आहे, हे सुद्धा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. लोकांचे रिकामेपण, एकटेपण घालविण्यासाठी रामायण, महाभारतसारख्या माहिती दूरदर्शनवर दाखवून भूतकाळातल्या आभासी जगात जनतेला रमवून, वर्तमानातील समस्यांवर मात करता येणार नाही. 'युनेस्को'ने शाळाबाह्य झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर तातडीने मार्ग काढण्याच्या सूचना आपल्या सभासद देशांना दिल्या आहेत. शिक्षणात आलेल्या या व्यत्ययाने मुलांना शिक्षण हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे, असे मत 'युनेस्को'ने नोंदविले आहे. दूरशिक्षण, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, यू-ट्यूब, हॅंगआउट, मल्टीमीडिया, मोबाइल फोन, ई-लायब्ररी, दूरदर्शन इ. माध्यमांतून अनेक देशांनी तातडीने, मुलांचे शिक्षण खंडित होऊ नये, म्हणून वरील प्रकारचे उपक्रम सुरू केले आहेत. भारतात मात्र परीक्षा रद्द करणे, परीक्षा पुढे ढकलणे, परीक्षा न घेता मुलांना पुढच्या वर्गात प्रवेश देणे एवढ्यापुरतेच निर्णय घेतले जात आहेत. परिस्थितीची अनिश्चितता लक्षात घेतली, तर भारतानेसुद्धा दीर्घ काळासाठी शैक्षणिक धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. भारतात उच्च शिक्षणात व मेडिसीन, इंजिनीअरिंग, कॉमर्स व मॅनेजमेंट यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या वरच्या स्तरातील असल्यामुळे लॅपटॉप, इंटरनेट इ. खर्च त्यांना परवडतो. त्यामुळे प्रामुख्याने अभिजन वर्गाच्या छोट्या गटांचा अभ्यास, ऑनलाइन चालू आहे. हाच अनुभव शालेय शिक्षणातही आहे. ज्या उच्च मध्यमवर्गीयांची मुले, सर्व सोयींनी युक्त अशा पंचतारांकित शाळेत जात आहेत, त्यांचेही ऑनलाइन शिक्षण चालू आहे. समस्या आहे, ती बहुसंख्य कष्टकरी, गरीब वर्गातील मुलांची. भटके-विमुक्त, आदिवासी, ग्रामीण भागातील सरकारी किंवा अनुदानित शाळेत जाणाऱ्या मुला-मुलींची!

माहिती तंत्रज्ञानामुळे शिक्षणाचा प्रसार, शिक्षणाचा विस्तार, शिक्षणाचा दर्जा, शिक्षणाची संधी वाढविण्यास भरपूर वाव आहे. 'ट्राय'च्या अहवालानुसार भारतात २०२० मध्ये इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या ६८.४५ कोटी आहे. मोबाइल फोन वापरणाऱ्यांची संख्या ४८.८२ कोटी आहे. तर, इंटरनेटसह स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांची संख्या ४०.७२ कोटी आहे. तर टीव्ही पाहणाऱ्यांची संख्या ७६ कोटी आहे. हा माहिती तंत्रज्ञानाचा विस्तार झालेला दिसत असला, तरी त्यात प्रचंड विषमता आहे. भारतात ५२ टक्के जनता इंटरनेटचा वापर करते. म्हणजे निम्मा भारत इंटरनेटच्या लाभापासून वंचित आहे. ग्रामीण भागात ३६ टक्के जनता व शहरात ६४ टक्के जनता इंटरनेटचा वापर करते, तर ६७ टक्के पुरुष व ३८ टक्के स्त्रिया भारतात इंटरनेटचा वापर करतात. माहिती-तंत्रज्ञान हे शहरी, सधनवर्ग व पुरुष यांचीच सध्या तरी मक्तेदारी होत आहे. त्यामुळे 'नॅशनल डिजिटल लायब्ररी', 'स्वयम', शोध गंगा इ. सरकारी प्रकल्पांचा फायदा मर्यादित होत आहे. या प्रकल्पांच्या ऑनलाइन शिक्षणात, कम्प्युटरची किंमत, इंटरनेटचा खर्च, विजेचा पुरवठा इ. प्रमुख अडचणी आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षण ही चौन शहरातील सधनवर्गाला परवडते! अनेक अप्रगत देशातसुद्धा अशीच परिस्थिती आहे. म्हणून त्या देशांनी टीव्ही माध्यमांचा वापर शाळा बंदच्या काळात जास्त करायला सुरुवात केली आहे. भारतात मात्र अशा कोणत्याही योजनेची साधी चर्चाही सुरू झालेली नाही. भारतात नऊशेहून अधिक चॅनेल्स आहेत व घरी बसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी या चॅनेलचा वापर कसा करून घेता येईल, याबद्दल शिक्षण खात्याकडून काही पावले उचलली जाणे आवश्यक आहे. परदेशात शिक्षणासाठी गेलेले भारतीय विद्यार्थी व त्यांचे पालक यांच्यासमोर लॉकडाऊनमुळे अडचणींचे डोंगर उभे राहिले आहेत. अभ्यासक्रमाचे बिघडलेले वेळापत्रक, आर्थिक ताण, व्हिसाच्या मुदतीचे प्रश्न, नोकरी मिळण्याची अनिश्चितता, शिक्षणकर्जाच्या हप्त्यांचे दडपण इ. मुळे परदेशातील भारतीय विद्यार्थी दडपणाखाली आहेत. काही परदेशी विद्यापीठे या काळात पर्याय म्हणून चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक याचा वापर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण, एकूण क्लृप्त, हळू, हळू परदेशातील भारतीय विद्यार्थी संकटात आहेत. त्यांना मदत करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय



अर्थ मंत्रालय व मानव विकास मंत्रालयांनी एकत्रित योजना करणे ही काळाची गरज आहे. शैक्षणिक नुकसान म्हणजे परीक्षा पुढे ढकलणे नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात खंड पडणार नाही, याची काळजी घेणे होय. कष्टकरी जनतेची मुले डोळ्यांसमोर ठेवून शाळा बंदच्या काळात या समाजघटकातील मुलांचे शिक्षण कसे अखंडपणे चालू राहील याची योजना केंद्र व राज्य सरकारनी तातडीने करावी.

संदर्भ ग्रंथ सूची :

- १) कन्हाडे वी.एम., शास्त्रीय संशोधन पद्धती, पिंपळापुणे अँड पब्लिशर्स, नागपूर,
- २) आगलावे प्रदिप, सामाजिक संशोधन पद्धतीशास्त्र व तंत्रे, श्री. साईनाथ प्रकाशन, धरमपेट नागपूर-१०,
- ३) www.majapaper.com, दिनांक १/१०/२०१३
- ४) गोखले प्रदिप, पटवर्धन शशी, गद्रे अरूण, मलोसे राजेंद्र, सामान्य ज्ञान व सामाजिक जाणीव अधिष्ठान अभ्यासक्रम, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक
- ५) कुळकर्णी पी.के., भारतातील सामाजिक समस्या, विद्या प्रकाशन, नागपूर
- ६) आगलावे प्रदिप, समाजशास्त्र परिचय, श्री. साईनाथ प्रकाशन, धरमपेट नागपूर-१०
- ७) <http://www.sjis.com/pages/pdfFiles/146814371146.%20Vijay%20Shimpi.pdf>
- ८) <https://www.esakal.com/kokan/during-corona-situation-online-education-option-students-upadation-very-important-online>
- ९) <https://maharashtratimes.com/editorial/ravivar-mata/corona-virus-and-education/articleshow/75097781.cms>

ISSN: 2278-9308.

6

Factor 8.632 (SJIF)

# CERTIFICATE


## B. Aadhar

Peer Reviewed & Index Multi-Disciplinary International Research Journal

Prof. Sidharth A. Patil

This certificate is granted to.....  
(Librarian) Shri. Dhabeekar Arts College Khadki Dist. Akola ..... He had submitted his research

paper for publication in *B. Aadhar, Peer Reviewed Indexed International Research Journal*. The title of the paper is "..... Cloud Computing And Its Applications: Enhancement Of Library Services..... The paper was given for Peer Review. After approval from the review process, the present editor, had published the research paper in *B. Aadhar Journal*. The present journal is a single blind peer reviewed journal. The research paper was published in April, -2023 bearing ISSN 2278-9308.

  
Chief Editor



Impact Factor-8.632 (SJIF)

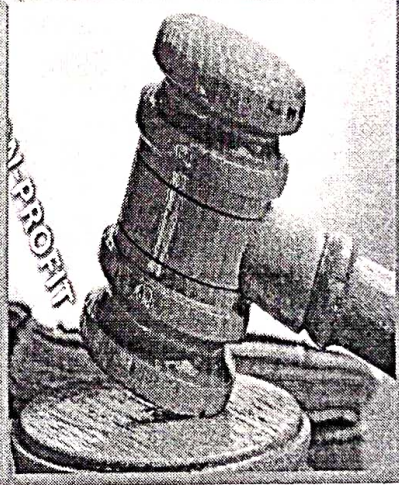
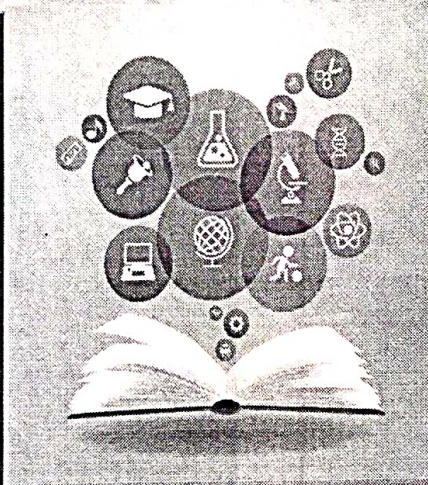
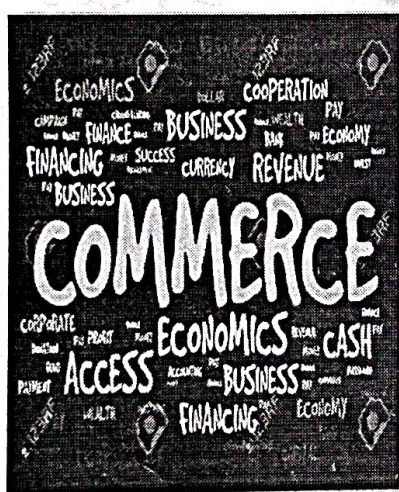
ISSN-2278-9308

# *B.Aadhar*

Single Blind Peer-Reviewed & Refereed Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

April -2023  
ISSUE No - (CDVII) 407



**Chief Editor**  
**Prof. Virag S. Gawande**  
Director  
Aadhar Social  
Research & Development  
Training Institute Amravati

**Editor:**  
**Dr.Dinesh W.Nichit**  
Principal  
Sant Gadge Maharaj  
Art's Comm,Sci Collage,  
Walgaon.Dist. Amravati.

**Executive Editor:**  
**Dr.Sanjay J. Kothari**  
Head, Deptt. of Economics,  
G.S.Tompe Arts Comm,Sci Collage  
Chandur Bazar Dist. Amravati



**This Journal is indexed in :**  
- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)  
- Cosmos Impact Factor (CIF)  
- International Impact Factor Services (IIFS)

For Details Visit To : [www.aadhar-social.com](http://www.aadhar-social.com)

**Aadhar P**UBLICATIONS



40	महात्मा गांधी यांचे विचार – एक विश्लेषणात्मक विवेचन डॉ. रामदास बाबाजी निहाळ	178
41	महात्मा जोतीराव फुले यांचे स्त्री उद्धाराचे कार्य आणि 21 व्या शतकातील स्त्रीजीवन प्रा.डॉ.साईनाथ शेटोड	182
42 ✓	Cloud Computing And Its Applications: Enhancement Of Library Services Prof. Sidharth A. Patil	186
43	पंडिता रमाबाई: भारतीय राजनीतिक और सामाजिक सुधारों में एक अग्रणी प्रतीक Ravina Kumari	189



## Cloud Computing And Its Applications: Enhancement Of Library Services

Prof. Sidharth A. Patil

(Librarian) Shri.Dhabekar Arts College Khadki Dist. Akola

### Abstract

Cloud computing is a new phenomenon in the history of services provided over the Internet. This completely changed the way computers use power, regardless of geographic location. The main advantage for organizations and businesses is that it provides services using third-party hardware or software or platform. It is very economical because it saves cost and maintenance. Cloud service comes in many different forms. To minimize costs and avoid duplication of resources, libraries are increasingly using infrastructure, software, hardware and new technologies such as server virtualization and cloud computing. This paper has attempted to provide an overview of how cloud computing service, platform and infrastructure forms have been used to meet library needs. This article discusses the functions, types, advantages and disadvantages, the role of a cloud librarian, the use of technology and cloud computing initiatives. Libraries have also tried to identify areas where this technology can be used to provide better library services and increase the productivity of library staff.

### Introduction

Until recently and now, too many organizations and individuals use computers to work alone, at work or at home, investing in hardware, software and maintenance. The current need is to introduce the latest technology in the organization. With the help of technology, it can ensure quick and important access to all information when needed. Cloud computing is the use of the Internet for computing needs. This technique has so many uses. For example, using programs, saving data, etc. An example of such services is also the use of computing power or a platform to create applications. From email to word processing to photo and video sharing, there are many services to choose from. These services can be accessed through any internet connection and are secure. These services are also supported. The best living example of this is Gmail, which is increasingly used by organizations and individuals to maintain their email services. Google Apps, free for educational institutions, is widely used to run various applications, especially email services, which previously ran on their own computer servers. This has saved the organization costs, as they pay for applications and services on a per-use basis, as well as computer staff time that they can invest in running other services. Google is responsible for updating, backing up and maintaining the servers. Libraries use computers to run services such as Integrated Library Management Software (ILMS), website or portal, digital library or institutional archive, etc. They are maintained either by the computer staff of the parent organization or by library staff. This requires investment in hardware, software and personnel to maintain these services, as well as to support them and update them when a new version of the software is released. "Many university libraries are now virtualizing servers and desktops, collaborating with other campus organizations, and saving money and staff time" (Kelley, 2012). Cloud-based services offer libraries the opportunity to free up resources for information technology and focus on the core competencies of libraries, i.e. management, organization and distribution of information. "Cloud-based services also bring modern services to libraries with less IT expertise," says Zhu (2012). Library professionals, who often lack server maintenance training, find it difficult to perform some of these functions without the help of IT staff inside or outside the organization. Now, cloud computing has become the new buzzword in the library industry, a boon in disguise to run various ICT services without much hassle, as third party services manage the servers and update and back up data. Although there are some problems with using cloud services such as privacy, security, etc., some libraries have already adopted this new technology to run some of their services. Many libraries are now customizing 3M Cloud Library applications.

### Cloud Computing

Cloud computing is a new phenomenon. Many individuals and organizations use this technology model for IT services. The advantage is that they are saved from having to host and operate multiple servers on their own network. This saves them the burden and risk of constant hardware failures. They have to worry about software installation, update or backup problems. It also saves on administrative



costs. According to Wikipedia, cloud computing refers to "the delivery of computing as a service, not a product, where shared resources, software and data are delivered to computers and other devices as a metered service over a network, typically the Internet." "The idea of cloud computing arose to outsource computing infrastructure, store customer data and applications through a remote server" (Hosch, 2009; Knorr and Gruman, 2008). In the cloud computing model, organizations only need to purchase or pay for the services that the organization needs. In this opt-in model, organizations must ask service providers to add or remove services as needed. Christy and Carina of the Gartner Group define cloud computing as "a style of computing in which massively scalable and flexible IT capabilities are offered as a service to external customers using Internet technologies." To simplify the concept, cloud computing can be defined as "only sharing and using applications and resources in the network environment to do work, without worrying about the ownership and control of network resources and applications" (M.-S. E Scale, 2009). Cloud computing is a very flexible model. In it, users can also build or prepare their own applications that can be used by others over the Internet. In fact, it provides a common computing platform.

#### **Types of Cloud Computing**

The IT model of cloud computing has a wider meaning as it basically has three different services viz. SaaS, PaaS and IaaS.

##### **Software as a Service (SaaS)**

Software as a service, or SaaS, is a service where software or applications are offered to users as a service. So we usually know it as subscription software. The program can be accessed online using any suitable client such as a web browser. In this model, users get access to applications through licenses or subscriptions. The software is offered on a so-called pay-as-you-use basis, where the user has to pay only for the software or applications he intends to use, or for free. Examples of such services are Google Apps, Salesforce, etc. It is centrally hosted with little scope to customize or manage applications or software. However, there are advantages such as the user not having to worry about maintaining, installing, updating or maintaining software or applications. In addition, the user has low initial costs and access to (usually 24/7) support services.

##### **Platform as a Service (PaaS)**

A platform as a service is a class of services that provide a platform or environment that developers can use to build the applications or software they need and that users can access simply through a web browser on the Internet. Software deployment and configuration settings are performed by users. Businesses of all types, regardless of size, use this service because it is very hassle-free and there is no need to worry about maintaining the software infrastructure hardware. In this model, companies are helped to build, test and deploy web-based applications. Organizations don't need to invest in the infrastructure they need to build web and mobile apps. They simply need to rent operating environments from vendors such as Windows Azure, Google AppEngine and Force.com. However, the downside is that applications or software created using the services of these vendors are usually locked to the same platform. This service is like a water and electricity network where users only have to "touch" and take what they need without any complexity. It is based on a subscription model. Users pay only for what they use. Users can focus on innovation instead of complex infrastructure.

##### **Cloud Computing: Application In Libraries**

Some organizations and business houses act as a cloud service provider for library software, search engines and digital libraries, etc., and provide a cloud computing platform for this.

Some of them are:

##### **OCLC Net Weight**

OCLC excels in the use of cloud computing in libraries and is a model for others. Together, OCLC has been a cloud service provider for many years, providing online cataloging tools and allowing member institutions to use their own centralized data repository<sup>13</sup>. OCLC implemented a Worldshare Management Services (WMS) plan for library management systems. This service includes services in many areas such as acquisition, analysis, resource sharing, cataloging and license management components. It enables the entire library to be managed in a cloud-based application. Webscale's main goal is to make it easier for libraries to share their resources, information and innovations. To this end, it has certain functions that together provide better library services to the users. In other words, it offers libraries cost advantages and efficiencies that are not possible when using different specialized systems<sup>13</sup>. The service promises to include privacy, security, scalability and technical support.





#### Duraspace's DuraCloud

Duraspace provides open source data storage solutions, implementing key projects for organizations and libraries to share scholarly literature using DSpace and Fedora Commons. It is specifically dedicated to the improvement and maintenance of Fedora and DSpace. These open source data storage solutions are very famous for their IR solutions. Its new service, DuraCloud, provides cloud-based digital storage services that are cost-effective and easy for libraries. DuraCloud helps libraries transfer content to the cloud and store it with different service providers to avoid the risk of data loss. Cloud solutions offered include online backup, storage and archiving, media access, online sharing and cloud delivery.

#### Enhancement Of Library Services By The Use Of Cloud Computing

- E-book rental service: Cloud platform is becoming popular for e-book rental.
- Federation/Common Catalogue/OPAC: Online libraries can use the same platform and provide access to their collection on one platform. Cloud technology makes it easy to create a syndicate list.
- Document download service: If internet access is enabled, documents can be easily downloaded.
- Digital storage/scanning service: digitization and scanning work can be done centrally, thus avoiding duplication of time-consuming work. Libraries can preserve the collection digitally as an archive.
- Article Delivery Service: Libraries can use a cloud computing service to deliver articles to patrons. Publishers are already using this technology to provide access to libraries.
- Current Awareness Service: With the help of cloud service, current awareness of all customers has become easy.
- Document sharing: With cloud services, document sharing has become easy.
- Bulletin Board Service: Using this technology, we can provide new services to the bulletin board.

#### Conclusion

Cloud computing is a new phenomenon in computer system technology. It happened because of the development of the Internet and related technologies. The phenomenon is evolving and will be very useful to organizations if the services are used carefully. However, this technology is very useful for organizations such as libraries to automate and manage services. This technique has some advantages. This technology frees library staff from managing servers. In general, it can be seen that library staff find it difficult to manage technologies. The reasons could be their skill level; The IT department may lack support or organizations may lack IT equipment. In this situation, the library staff prevents the automation of library work or the development of digital library services, etc. This technology can be of great importance in the implementation of modern ICT operations in libraries. Library professionals do not have to worry about the technical side of ICT operations. They just need to increase the content of the resources.

#### References

- [1] D. A. Kumar and S. Mandal, "Development of Cloud Computing in Integrated Library Management and Retrieval System". *International Journal of Library and Information Science*. 2013. 5 (10). 394-400
- [2] Christy, Pettey and Forsling, Carina. Gartner emphasizes five characteristics of cloud technology. 2009. <http://www.gartner.com/newsroom/id/1035013> (accessed 08/19/2014).
- [3] S.Y. Bansode and S.M. Pujar, "Cloud Computing and Libraries". *DESIDOC Journal of Library and Information Technology*, Vol. 32, n-ro 6, November 2012, pp 506-512
- [4] Mark Shane E. Scale, "Cloud Computing and Collaboration", *Library With Tech News*, Vol. 26 El.: 9, pp 10-13 <http://www.libraryjournal.com/article/CA6695772.html> (accessed 22.8.2014)
- [5] CA6695772.html (accessed 22.8.2014)
- [6] S. Dhamdhare and R. Lihikar, "Common and Emerging Cloud Library Technologies". *International Journal of Library and Information Science*. 2013. 5 (10). 410-416
- [7] on AWS. 2014 year. <http://aws.amazon.com/what-isaws/> (accessed July 4, 2014).

Impact Factor-8.632 (SJIF)

ISSN-2278-9308

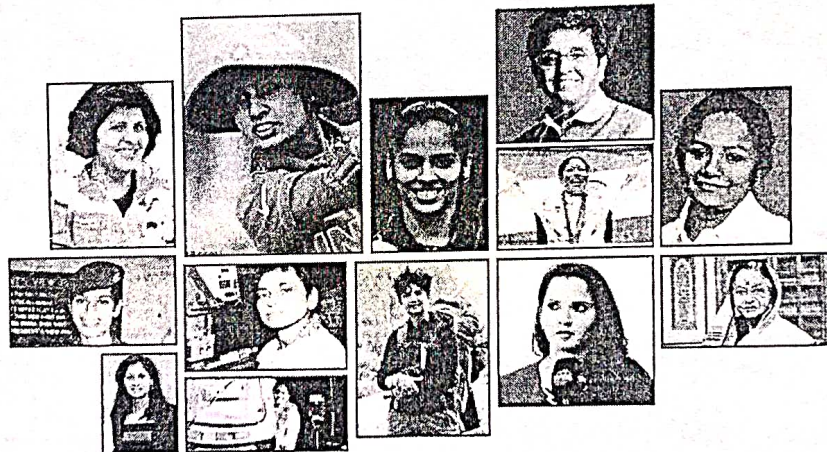
# *B.Aadhar*

Single Blind Peer-Reviewed & Refereed Indexed  
Multidisciplinary International Research Journal

**March-2023**

ISSUE No - (CCCXCVIII) 398 (A)

**A Journey of Indian women**



**Chief Editor**  
Prof. Virag S. Gawande  
**Director**  
Aadhar Social  
Research & Development  
Training Institute Amravati

**Editor**  
Dr.V.R.Kodape  
**Principal**  
Shri Kisanlal Nathmal Goenka Arts & Com,  
College Karanja (LAD) Dist. Washim

**The Journal is indexed in:**

Scientific Journal Impact Factor (SJIF)

Cosmos Impact Factor (CIF)

International Impact Factor Services (IIFS)

For Details Visit To : [www.aadharsocial.com](http://www.aadharsocial.com)

**Aadhar P**UBLICATIONS



# B.Aadhar

Single Blind Peer-Reviewed & Refereed Indexed  
Multidisciplinary International Research Journal

**March- 2023**

ISSUE No - 398 -A

## A Journey of Indian women

**Prof. Virag.S.Gawande**

Chief Editor

Director

Aadhar Social Research &, Development Training Institute, Amravati.

**Dr.V.R.Kodape**

Editor,

Principal,

Shri Kisanlal Nathmal Goenka Arts & Com,  
College Karanja (LAD) Dist. Washim

**Aadhar International Publication**

For Details Visit To : [www.aadharsocial.com](http://www.aadharsocial.com)

© All rights reserved with the authors & publisher

**INDEX**

No.	Title of the Paper	Authors' Name	Page No.
1	A Review on Role of Women in Agriculture Development in India	K.M. Ranjalkar	1
2	Role of Indian women in science and technology	Kiran F Shelke	4
3	Status Of Modern Women In India	Dr. Baljeet Kaur R. Oberoi	7
4	Problems and Issues of Women Education in India	Dr. D.B. Raghuwanshi	11
5	Role of Self Help Groups in Women Economic Empowerment	Dr. Rita Deshmukh	14
6	Status Of Indian Women In Past And Present	Dr.C.N.Rathod	17
7	Women's in Sports	Dr.Sangita A. Deshmukh	19
8	Participation Of Women In Sports: Sports Leadership And Growth	Prof. Anjali Digambar Barde	22
9 ✓	Women's Political Participation And Leadership In India	Pro.Siddharth A Patil	25
10	Women And Social Media	Dr. Vinod B. Chavhan	28
11	Women Empowerment And Their Working Problem In Post-Independence India	Prof. Avinash R. Pawar	33
12	Women Economic Empowerment: Facts and Figures	Prof. Gajanan Y. Wankhade	37
13	Vo <sub>2</sub> max Analysis In Different Team Game Of Amravati University Players	Prashant Sudhakar Rao Charjan	39
14	Journey of Rural Women in Agricultural Revaluation	Prof.Dr. Jyoti R. Maheshwari	44
15	Women in India and Domestic Violence against them :A Critical Analysis	Dr. Anjali R. Wath	47
16	Obstacles faced by Women in Sports and their social status	Dr. Sanjay Deshmukh	50
17	An Emergence of Feminine Consciousness in the Select works of Indian Women Novelists	Dr.B.S.Kavhar	52
18	Importance Of Woman Empowerment In India- An Economic Perspective	Mr. R. Prabakaran , Dr. B. Purushothaman	55
19	Women And Their Education Post-Independence India	Prof.Varsha D. Borde	60
20	Contribution Of Women In Science And Technology In Present Era	Dr. Shyam K. Lande	63
21	A Study Of Trends Of Woman's Higher Education In India	Dr. Shubhangee L. Diwe	66
22	Women And Sports: A Way Towards Health And Wellness	Dr. Seema V. Deshmukh	70

## Women's Political Participation And Leadership In India

Pro.Siddharth A Patil

Librarian Shri Dhabekar Arts college Khadki, Dist. Akola

### Abstract

The political participation of women is considered an integral part of any development. However, India's gender equality policy is still under scrutiny. Since independence in 1977, many initiatives have been taken to increase the political representation of women by decentralizing power in various local government bodies in India. The functioning of Panchayati Raj institutions increased the inclusion of marginalized segments of society, including women, in the decisive role of political institutions. Therefore, this study aims to investigate the political leadership of women in local government institutions using qualitative methods such as document analysis of the Panchayati Raj Institutions Amendment Act and expert interviews with selected women representatives in one district of Kerala state. The paper seeks to identify the challenges faced by women in political leadership in India, the largest democratic country. Different development projects require expert opinion and self-sustaining practice; therefore women must be competent to manage the administration easily. Various forms of sexual violence against women in politics in the form of verbal harassment, challenges to personal dignity and sexism prevent women from participating in politics. Finally, since the cooperation of male colleagues is an integral part of successful governance, female representatives tend to use different mechanisms to build mutual trust. The experiences of women politicians show that in order to increase the participation of women in politics and to maintain their participation in governance, it is necessary to formulate viable political measures at the state and national level.

### Introduction

The World Bank considers the empowerment of women a key factor in general social development. The Millennium Development Goals (2019) emphasized gender equality and the empowerment of women as an opportunity to achieve meaningful progress in emerging economies. Therefore, each country needs different programs to balance its gender and strengthen the political life of women. Empowerment should be seen as part of seeing oneself as an active decision maker (King and Mason, 2001). Empowering women allows them to focus their lives on setting and organizing agendas and demanding help from the state and community. As in many cultures, the role of women can be seen as integral in terms of growth, but sometimes does not emphasize the same status as men. That is why it is believed that women need more help for their huge position in decision-making and social development. The term empowerment describes the feeling of gaining power and participating in decision-making (Naz, 2006; Karl, 1995). The Beijing Declaration (1995) emphasized that the empowerment and full participation of women on the basis of equality in all cultural spheres, including participation in decision-making processes and authority, is essential to achieve inclusion, growth and harmony. That is why the United Nations declared women's empowerment as the fifth of its Millennium Development Goals 2000-2015. Alexander et al. (2016), women's political empowerment is understood as the improvement of women's resources, skills and achievements to achieve equality in influencing and exercising political power. Political empowerment is a method that allows women to increase their mobility and break isolation, build self-confidence and image, shape their presence by participating in decision-making in the administration in the context of awareness and critical evaluation, monitoring and influence. growth progress Thus, in most cases, the national government excels in promoting women's participation in politics, trying to change the way society thinks and create more forums for women as part of political decision-making (Maailmapank, 2001; Oxaal, 1997). Therefore, it is imperative to encourage decentralization of power and authority to support the voiceless segment of the cultural sectors. Therefore, it is important to encourage the participation of the marginalized section in decision making for the sake of empowerment. Inequality not only reduces women's ability to improve themselves, but also hinders their personal growth and skills. There is clearly no discussion of women's inequality as a violation of human rights, and women's under-representation was very noticeable in Scandinavian parliaments (Randall, 1 ; UN, 2019). The present paper is an strive to research the fame of woman empowerment in India the usage of numerous signs primarily based totally on facts from secondary sources. The examine famous that



woman of India are surprisingly disempowered and that they experience incredibly decrease fame than that of guys no matter many efforts undertaken via way of means of government. Gender hole exists concerning get right of entry to to training and employment. Household selection making energy and freedom of motion of woman range significantly with their age, training and employment fame. It is observed that recognition of unequal gender norms via way of means of woman are nonetheless triumphing withinside the society. More than 1/2 of of the woman consider spouse beating to be justified for one motive or the different. Fewer woman have very last say on the way to spend their income. Control over coins income will increase with age, training and with location of residence. Women's publicity to media is likewise much less relative to guys. Rural woman are extra vulnerable to home violence than that of city woman. A big gender hole exists in political participation too. In the closing 5 decades, the idea of woman empowerment has gone through a sea alternate from welfare orientated technique to fairness technique. It has been understood because the procedure via way of means of which the powerless advantage more manage over the situations in their lives. Empowerment in particular consists of manage over sources and ideology. According to Sen and Batliwala (2000) it results in a developing intrinsic capability greater self confidence, and an internal transformation of one's recognition that permits one to conquer outside barrier. This view specifically emphasizes on vital factors. Firstly, it's far a energy to obtain favored dreams however now no longer a energy over others. Secondly, concept of empowerment is extra relevant to folks that are powerless- whether or not they may be male or female, or institution of individuals, magnificence or caste. Though idea of empowerment isn't unique to woman, but it's far precise in that and it cuts throughout all sorts of magnificence and caste and additionally inside households and households (Malhotra et al, 2002). Women empowerment is likewise described as a alternate withinside the context of a woman's existence, which permits her elevated ability for main a satisfying human existence. It receives meditated each in outside qualities (viz. health, mobility, training and attention, fame withinside the family, participation in selection making, and additionally at the extent of fabric security) and inner qualities (viz. self attention and self confidence) [Human Development in South Asia (2000) as quoted by Mathew (2003)]. UNDP (1990) for the primary time delivered the idea of Human Development Index (HDI) that developed to begin with as a broader degree of socio-financial development of a state however it have become famous as a degree of common achievements in human improvement for each the sexes. Contrary to the overall perception that improvement is gender neutral, facts display that woman lag at the back of guys all around the global which include India in nearly all factors of existence. It is because of this that the focal point on human improvement has been to spotlight the gender measurement and persevering with inequalities confronting woman due to the fact 1995 (UNDP 1995). The Report cited that with out empowering woman typical improvement of humans isn't viable. It similarly pressured that if improvement isn't engendered, is endangered.

#### **Women in Indian Politics**

Despite being seen as central to all other advances in any society, the political empowerment of women faces many obstacles, especially in developing countries, including India. Although in developed countries women have more opportunities and freedom to actively participate in political life, in developing countries it causes many restrictions for women due to deeply embedded cultural, religious and social beliefs about the status of women in culture. participate in decision-making in developing countries. Therefore, the participation of women in the power structure and political influence is still not sufficient to analyze the position of women in the political system. In order to improve the participation of women on the political stage, it is necessary to strengthen the influence of women through several programs and action plans at the local, national and societal levels.

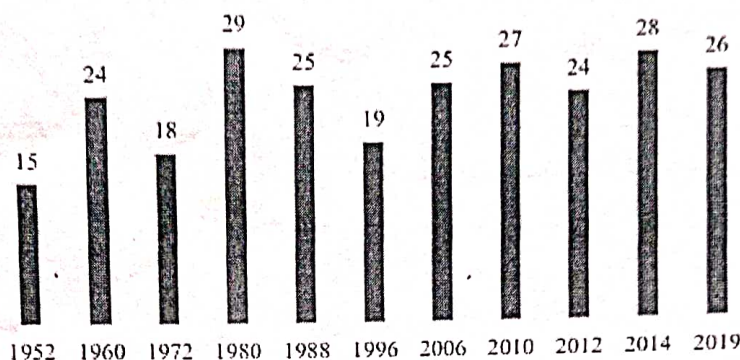


Fig.1. Number of women members in Rajya Sabha (Council of States)

**Conclusion**

Implementation of the Panchayat Raj Institutions Act plays an important role in decentralizing power to local governments and empowering women. Although the participation of women at the LSG level is higher in the southern Indian state of Kerala, the results of baseline data collected from Idukki district reveal various challenges faced by elected women representatives. Cultural barriers and patriarchy continue to prevent women from participating in the political spectrum and democratic governance. Greater responsibility in domestic activities prevents women from running for politics for a longer period of time. In most cases, in order to increase social skills and communication in society, women must be connected to the party and its activities, which sometimes seems like an additional duty for them to obey or act according to the interests of the party. Lack of sufficient financial stability prevents women leaders from focusing on creating their own space in politics. Patriarchy and gender segregation at the highest political levels, even after years of working in party activities, is a major catalyst that prevents women from remaining in politics. Different development projects require expert opinion and self-sustaining practice; therefore women must be competent to manage the administration easily. Various forms of sexual violence against women in politics in the form of verbal harassment, challenges to personal dignity and sexism prevent women from participating in politics. Finally, since the cooperation of male colleagues is an integral part of successful governance, female representatives tend to use different mechanisms to build mutual trust. The experiences of women politicians show that in order to increase the participation of women in politics and to maintain their participation in governance, it is necessary to formulate viable political measures at the state and national level.

**References**

1. Anonymous 1. Interview/ Interviewer: T. Varghese. Idukki, India, about 2 hours, Malayalam (accessed 6 March 2019).
2. Anonymous 2. Interview/ Interviewer: T. Varghese. Idukki, India, about 2 hours, Malayalam (accessed 9 March 2019).
3. Anonymous 3. Interview/ Interviewer: T. Varghese. Idukki, India, about 3 hours, Malayalam (accessed 10 March 2019).
4. Anonymous . Interview/ Interviewer: T. Varghese. Idukki, India, about 2 hours, Malayalam (accessed 25 March 2019).
5. Anonymous 5. Interview/ Interviewer: T. Varghese. Idukki, India, about 3 hours, Malayalam (accessed 7 April 2019).
6. Anonymous 6. Interview/ Interviewer: T. Varghese. Idukki, India, about 1 hour, Malayalam (accessed 19 April 2019).
7. Anonymous 7. Interview/ Interviewer: T. Varghese. Idukki, India, about 2 hours, Malayalam (accessed 22 April 2019).
8. Bryld, E. (2001). Increasing participation in democratic institutions through decentralization: Empowering women and scheduled castes and tribes through panchayat raj in rural India. *Democratization*, 8(3), 19-172.



ISSN 2454-1974

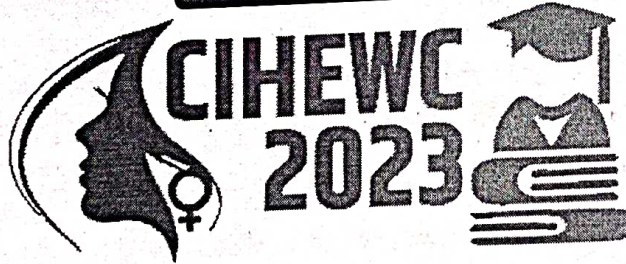
# THE RUBRICS

e Journal of Interdisciplinary Studies  
International, Peer Reviewed, Indexed



One Day National Multidisciplinary Conference On  
Current Issues in Higher Education and Women's Contribution

10<sup>th</sup> March 2023



Conference Proceeding: Special Issue Editors  
Ms. Priyanka Ruikar, Dr. Manoj Bhagat  
Dr. Pritee Thakare, Dr. Shrikant Rasekar

Organized by

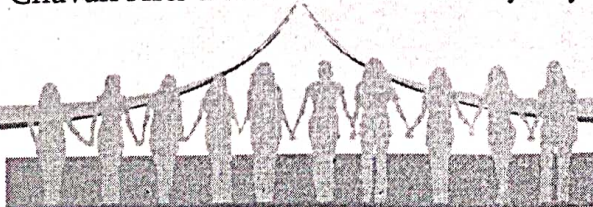
SGBAU Amravati University, Amravati

Mungasaji Maharaj Mahavidyalaya, Darwaha

Jijamata Arts College, Darwaha

B.B.Arts, N.B.Commerce and B.P.Science College, Digras

Yashwantrao Chavan Arts and Science Mahavidyalaya, Mangrulpir





13	जागतिकीकरणाचा सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेवरील प्रभाव डॉ. पुरुषोत्तम रामराव बांडे	62
14	वृद्धांच्या समस्यांचे विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रा. डॉ. अमरिष एस. गावडे	69
15	भारतीय स्त्रीचे समाजातील स्थान डॉ. सुनिल बी. चकवे	74
16	क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे सामाजिक क्षेत्रातील योगदान प्रा- डॉ-मंजुषा एच- धापुडकर	77
17	सामाजिक कार्य करणाऱ्या स्त्रियांच्या आत्मचरित्रांचे मराठी साहित्यातील योगदान प्रा. डॉ. संतोष विष्णू चतुर	80
18	कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा : आकलन, वास्तविकता आणि आव्हाने प्रा. व्ही. एम. मुधाने	85
19	भारतीय राजकारणामध्ये महिलांचे योगदान डॉ विजय मु. गावडे	90
20	आधुनिक समाज सुधारणेत महिलांचे योगदान डॉ. शरद जा. वाघोळे	93
21	आधुनिक काळातील पालक-बालक संबंध एक अध्ययन प्रा. रूपाली सुभाषराव कणसे	96
22	स्त्री आणि शेती व्यवसाय   प्रा. सौ. सुषमा सु. जाजु	101
23	भारतातील महिला शिक्षण: एक विश्लेषण   डॉ. मधुकर श्रीराम ताकतोडे	105
24	महिला सक्षमीकरणासाठी भारतीय कायदे आणि सद्यस्थिती सरिता दिनकरराव देशमुख	109
25	किशोरवयीन मुलांच्या शारिरीक वाढीसाठी उपयुक्त आहार तालीकाचे महत्व प्रा. कल्पना वामनराव गोडे	113
26	महिलांचे सामाजिक योगदान कुटुंबाचे आरोग्य व पोषण संदर्भात प्रा डॉ. अपर्णा अ. पाटील	117
27	शेतकऱ्यांसाठी डॉ. आंबेडकराचे कार्य प्रा. डॉ. सिध्दार्थ वाठारे	121



## THE RUBRICS

Journal of Interdisciplinary Studies

Volume 5 Issue 2 March 2023

[www.therubrics.in](http://www.therubrics.in)

ROAD  
ROBUSTNESS OF ACCESS  
TO KNOWLEDGE  
AND  
DISSEMINATION

CiteFactor  
ANALYZING SCIENTIFIC PUBLICATIONS

# वृद्धांच्या समस्यांचे विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रा.डॉ. अमरिष एस. गावंडे

प्रमुख, समाजशास्त्र विभाग  
श्री. धाबेकर कला महाविद्यालय, खडकी, अकोला

## संशोधन लेख

प्रस्तावना :

'वृद्धाश्रम' हा शब्द ऐकल्यानंतर वृद्धापकाळाची आठवन येते. वृद्धाश्रमाकडे संवर्धन केंद्र म्हणून पाहणे की, आधुनिक काळातील समस्यांचे माहेरघर म्हणून पाहणे, हा वादाचा विषय आहे, आजच्या समस्यांमध्ये वृद्धांच्या समस्या पाहता ही समस्या किती गंभीर स्वरूप घेत आहे हे जाणवू लागते. मोठ मोठ्या समस्यांची निर्मिती, कुटुंबसंस्थेतील बदल, व्यक्तीवादी प्रवृत्ती, पाश्चिमात्य संस्कृतीचा प्रभाव सभ्यतेच्या नावाखाली मनोरंजनाची साधने इत्यादी मुळे वृद्धावस्था आज समस्या वाटायला लागली आहे. वर्तमानपत्र टेलीव्हिजन, इतर मिडीयाच्या माध्यमांद्वारे आपल्यापर्यंत वृद्धांच्या समस्याची मांडणी समाजापर्यंत पोहचत आहे. यावरून एक प्रश्न मनात येतो की 'वृद्धावस्था' ही पूर्वी समस्या का वाटत नव्हती थोडे मागे वळून पाहिले तर त्याचे उत्तरही त्यामध्ये शोधता येते. वर्तमान काळात वृद्धांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन व्यवहारवादी स्वार्थी झालेला दिसतो. व्यक्ती शारिरीक आणि मानसिकदृष्ट्या निवृत्त झाला की तो वृद्ध झाला असे समजले जाते. भौतिक वस्तुप्रमाणे वृद्धांकडे पाहले जाते युझ आणि श्रो.

सामान्यपणे मानवी जीवनातील शेवटची अवस्था म्हणून वृद्धावस्थेकडे पाहिले जाते, निसर्गामध्ये प्रत्येक वस्तुचा उदय, विकास आणि : ऱ्हास हा ठरलेला क्रम आहे या चकाला मानवप्राणी अपवाद नाही जीवन मुल्य या चकालातील शेवटची अवस्था म्हणजे 'वृद्धावस्था' होय. या अवस्थेमध्ये मनुष्याच्या सामाजिक, शारिरीक, आर्थिक, मानसिक घटकांमध्ये ऱ्हासात्मक बदल झालेला असतो. या बदलांकडे व्यक्ती, कुटुंब, समाज कशाप्रकारे पाहतो यावरून वृद्धावस्था समस्या आहे वा नाही ते ठरत असते. समाजातील प्रत्येक घटकांचा याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण वेग-वेगळा असल्याने वृद्धावस्था एक सापेक्ष संकल्पना आहे. वृद्धावस्था ही संकल्पना आज समस्या म्हणून समोर आलेली आहे. समाजसंरचनेतील बदलाचा तो एक भाग आहे. कुटुंब संस्थामध्ये झालेले प्रतिकूल बदल वृद्धावस्था ही समस्या ठरवतात.

वृद्धापकाळामध्ये व्यक्तीला जर मानसिक आधार मिळाला नाही तर ती समस्या वाटणारच आहे. वर्तमानमध्ये अनौपचारिक संबंधाऐवजी औपचारिक संबंधांचे प्रमाण वाढत चाललेले आहे. व्यक्तीवादी प्रवृत्ती, करार इत्यादीमुळे ही समस्या दिवसेंदिवस तिघे रूप धारण करित आहे. प्राचीन हिंदुधर्म संस्कृतीनुसार मानवी जीवनाची विभागणी चार भागांमध्ये करण्यात आलेली होती त्यालाच आपण 'आश्रमवस्था' असेही म्हणतो. याचार भागापैकी शेवटचा भाग वृद्धावस्था म्हणून ओळखला जातो. आधुनिक काळामध्ये मानव चंद्रावर राहण्याची तयारी करित आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये मानवाने कधी नव्हती ऐवढी प्रगती केलेली आहे परंतु सामाजिक संबंध मानव त्याप्रमाणात जोपासू शकलेला नाही. त्यामुळेच 'वृद्धावस्था' समस्या वाटत आहे.

साधारणतः वृद्धावस्थेतील शेवटच प्रवास हा दुःखदायक असल्याचे चित्र आज समोर येत आहे. मुलांकडे किंवा मुलीकडे राहणे, दोघानी चांगली वागणुक दिली नाही तर शेवटचा पर्याय म्हणुन वृद्धाश्रमाचा आधार घेतला जातो. या पर्यायाकडे जाण्यापूर्वीच काही वृद्ध व्यक्ती आत्महत्या करण्याचे समोर आले आहे. प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ एमिलदुर्खीम यांनी आपल्या निष्कर्षामध्ये असे म्हटले आहे की, 'सर्वसामाण्यांमध्ये आत्महत्या करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये वृद्धावस्थावर प्रकाश टाकण्यात आलेला असुन वर्तमानकाळामध्ये वृद्धांच्या समस्येमध्ये वेगवेगळ्या कारणामुळे कशाप्रकारे वाढ होत आहे हे सुद्धा स्पष्ट केलेले आहे. शोधनिबंधाची उद्दिष्टे

१) वृद्धावस्था ही संकल्पना स्पष्ट करणे

२) वर्तमानकाळामध्ये वृद्धांच्या समस्यावर प्रकाश टाकून त्यावर उपाययोजना सुचविणे.

३) कुटुंबामधील बदलांचा वृद्धावर कशाप्रकारे प्रभाव पडतो हे स्पष्ट करणे.

वरील उद्देश्यांच्या पूर्तीकरीता प्रस्तुत संशोधनासाठी कांही गृहीतकृत्याची मांडणी करण्यात आलेली आहे ती

पुढीलप्रमाणे

गृहीतकृत्ये

१) सामाजिक संस्थेतील बदलामुळे वृद्धांच्या समस्या वाढत आहेत.

२) संयुक्त कुटुंबांच्या विघटनामुळे 'वृद्धावस्था' ही समस्यावत वाढत आहे.

३) ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागामध्ये वृद्धांच्या समस्यांची तीव्रता जास्त आहे.

४) वृद्धामध्ये शारिरीक आणि मानसिक समस्यांची तीव्रता अधिक आहे.

वरील गृहीतकृत्यांच्या आधारावर वर्तमानकाळातील वृद्धांची स्थिती स्पष्ट केलेली आहे. आज वृद्धांच्या अनेक समस्या आहेत. त्या समस्यांसाठी कारणांची साखळीच आहे, हे स्पष्ट दिसून येते त्या सर्व घटकांचा विचारकरण्यापूर्वी वृद्ध व्यक्ती कोणाला म्हणायचे? वृद्धावस्था म्हणजे काय? हे पाहणे क्रमप्राप्त ठरेल.

वृद्धव्यक्ती कोणाला म्हणायचे

एलीझाबेथ हरलॉक यांच्याशाब्दामध्ये म्हणायचे झाल्यास वृद्धावस्था ही मानवी जीवनातील अंतीम चरण होय. तर समाजशास्त्रीय विश्वकाषानुसार 'व्यक्तीजीवनाचा अंतीम कालखंड म्हणजे वृद्धावस्था होय.'

वरील विचारांच्या मतानुसार जन्म ही मानवी जीवनाची पहिली पायरी आहे तर वृद्धावस्था ही शेवटच्या टोकाकडे नेनारी पायरी आहे. या अवस्थेमध्ये व्यक्तीमध्ये शारिरीक, मानसिक, सामाजिक बदल मोठ्या प्रमाणात होतांना दिसतात.

वृद्धावस्था ही स्थळ, काळ, परिस्थिती सापेक्ष संकल्पना आहे. अर्थात प्रत्येक काळामध्ये, प्रदेशामध्ये व्यक्तीची आयुमर्यादा वेगवेगळी असल्याने कोणत्या वयाच्या व्यक्तीला वृद्ध म्हणायचे याबाबत ठामपणे सांगता येत नाही. आश्रमव्यवस्थेनुसार वयाच्या ७५व्या वर्षानंतरच्या व्यक्तीला वृद्ध समजले जात होते. अर्थात संन्यासश्रमाध्ये प्रवेश करणारी व्यक्ती वृद्ध समजली जात होती. आज मानवाची सरासरी आयु मर्यादा ६० वर्षे ठरलेली आहे. त्यामुळे ६० वर्षे पूर्ण करणारी व्यक्ती 'वृद्ध' समजली जाते. वयाच्या आधाराप्रमाणेच कार्यक्षमता या आधारेही वृद्धावस्था ठरविली जाते. यानुसार पर्यावरणासी जुळवुण घेतांना व्यक्तीला शारिरीक, मानसिक अडचणी असल्यास वृद्धापकाळाची सुरुवात समजल्या जाते. म्हणुन असे म्हटले जाते की, वृद्धत्व म्हणजे व्यक्तीची शारिरीक, सामाजिक, बौद्धिक, मानसिक क्षमता घटविणारी स्थिती होय.

व्यवहारामध्ये 'वृद्धावस्था' वेगवेगळ्या नावाने ओळखल्या जाते जसे की- 'पिकलेले पान', निवृत्त होणे, कार्यक्षमता घटणे शासकीय योजनांची पात्रता पूर्ण करणे इत्यादी नावाने ओळखले जाते. म्हणुन पाश्चिमात्य विचारवंत हेन्री क्युमिंग असे म्हणतात की, 'जीवनातील उपयोगी आणि अभिलाषा असणाऱ्या आरंभीच्या अवस्थेपासुन दुर जाण्याच्या प्रक्रियेला वृद्धावस्था असे म्हणतात.



**वृद्धावस्था ठरविणारे घटक**

१.	वय	सरासरी ६०वर्ष (५८ वर्ष ते ६५ वर्ष)
२	कार्यक्षमता	कमी-कमी होणे, हात-पाय अकार्यक्षम होणे, शारीरिक व मानसिक थकवा येणे
३	शारीरिक व्यंग	कान, डोळे सामान्यपणे काम करणे

**सद्यस्थितीत वृद्धांची स्थिती**

वर्तमानस्थितीमध्ये वृद्धांच्या समस्यावर उपाययोजना करण्यासाठी शासन स्तरावरून त्याचप्रमाणे, शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ, गैरसरकारी संघटना इत्यादीद्वारे प्रयत्न केले जात असले तरी कुटुंबाप्रमाणे काळजी घेतली जात नाही. संयुक्त कुटुंबामध्ये अपंग, वृद्ध व्यक्तींना चांगल्या प्रकारे वागणूक दिली जाते. त्यांच्या निर्णयक्षमतेवर विश्वास ठेवला जातो. एवढेच नाही तर वृद्ध व्यक्ती हेच कुटुंब प्रमुख असतात. सद्यस्थितीत विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा विकास प्रचंड गतीने झालेला आहे, होत आहे. त्याचा परिणाम मानवी संबंधांवर पाहायला मिळत आहे. व्यक्ती-व्यक्ती, व्यक्ती-समाजाचा संपर्क वाढला परंतु नाते कुठेतरी हरवून गेल्यासारखे झाले आहे, त्या नात्यामध्ये हरविलेला एक प्रमुख घटक म्हणजे वृद्ध व्यक्ती होय. त्यामुळे वृद्ध व्यक्तींना अनेक समस्यांना सामना करावा लागतो.

**मानसिक स्थिती**

या धकाधकीच्या काळामध्ये मानसिक समस्या ही सर्वासाठी सामान्य आहे. नातेदारी हरविल्यामुळे याचा सामना सर्वांना कमी-अधिक प्रमाणात करावा लागतो. वृद्धामध्ये ही स्थिती अधिकच बिकट आहे. साधारणतः वृद्ध व्यक्तींना खालील मानसिक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. वृद्ध व्यक्तींना आपण एकटेच आहोत आपल्या निर्णयाला कोणत्याही प्रकारे महत्त्व दिले जात नाही. कुटुंबामध्ये आपली काहीही गरज नाही ही भावणा निर्माण झाली आहे. प्रामुख्याने एकलकोंड्याची वृत्ती वृद्ध व्यक्तीमध्ये जास्त पाहावयास मिळते. एमील दुखीम याला 'आत्मकेंद्रीतता' असे म्हटलेले आहे. या प्रकारामुळे व्यक्ती समाज, कुटुंबापासून दूर जातो. दोन पिढ्यांतील अंतर, त्यांच्या विचारातील भेदभाव यामुळे वृद्धामध्ये परकेपणाची भावणा निर्माण होते, अशा परिस्थितीत ते कुटुंबापासून दूर जातात. त्यातून मानसिक परावलंबनाची भावणा वाढत जाते. वृद्धापकाळात स्मरणशक्तीचा मोठ्या प्रमाणात न्हास होतो. वृद्धावस्थेमध्ये वृद्धामध्ये प्रामुख्याने परावलंबणाची स्थिती वाढत असल्याने समोर आलेले आहे. सर्व प्राणीमात्रामध्ये माणव हा सर्वाधिक परावलंबी सामाजिक प्राणी आहे. जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत त्याला इतरांवर अवलंबून राहावे लागते विशेषतः वृद्धापकाळामध्ये शारीरिक शीथीलता आल्याने परावलंबाची भावणा अधिकच वाढलेली असते. अशावेळेस त्याला मानसिक आधार मिळणे आवश्यक आहे.

**शारीरिक स्थिती**

वृद्धावस्थेमध्ये व्यक्तीच्या शरीरामध्ये बराच बदल घडून आलेला असतो. शारीरिक बदल हे अंतर्गत आणि बाह्य स्वरूपाचे असतात. बाह्य बदलामध्ये केस पांढरे होणे, चेहऱ्यावर सुरुकुत्या पडणे, दातपडणे, शिराचा आकार बदलणे हातापायाला कंप सुटणे. शारीरिक बदला अंतर्गत बदलामध्ये पचनसंस्थेचे कार्य असंतुलीत होणे श्रवणशक्ती, तोतरे बोलणे मलमुत्र विर्सजनाला त्रास होणे, अस्थि ठिसुळ होणे, पेशीचे विभाजन होणे, रोग प्रतिकारशक्तीचा न्हास होणे, वेगवेगळ्या व्याधीचा उदय होणे इत्यादीचा सामावेश करता येतो. वृद्धावस्थेत वृद्धामध्ये अनेक प्रकारचे शारीरिक बदल होत असतात. त्याचा परिणाम त्यांच्या जीवनमानावर दिसून येतो. वृद्धावस्थेत वृद्धामध्ये झालेले शारीरिक बदल पुढील तक्त्यावरून दिसून येतात.

अ.क्र.	पर्याय	आजाराचा प्रकार	आजाराचा प्रकार	आजाराचा प्रकार
--------	--------	----------------	----------------	----------------



१	अंतर्गत बदल	मुत्रविकार ५८% वृद्धांना	डोळे-कान ३५%	अस्थी व्यंग ४१%
२	बहिर्गत बदल	केसपांढरे होणे ८०%	दात पडणे ६५%	चेहऱ्यावर सुरकुत्या ९९%

वरील तक्त्यावरून वृद्धावस्थेत होणाऱ्या शारीरिक बदलांचा (अंतर्गत-बाह्य) आढावा लक्षात येतो. ५८ टक्के वृद्धांना मुत्रविकार, ४१ टक्के वृद्धांना अस्थी व्यंग सारख्या समस्यांनी ग्रसले असल्याचे दिसून येते.

आर्थिक स्थिती :

एका विशिष्ट वर्गापर्यंत व्यक्ती उत्पादन प्रक्रियेमध्ये भाग घेवू शकतो. कारण व्यक्तीची कार्यक्षमता उतरत्या वयानुसार हळू हळू कमी कमी होत असते. त्यामुळे वृद्धपकाळात व्यक्तीची आर्थिक स्थिती हालाखीची असल्याचे समोर आले. भारतामध्ये वयाच्या ५८ ते ६५ वर्षांपर्यंतची व्यक्ती नोकरी करू शकते. त्यानंतर निवृत्त व्हावे लागते. वृद्धपकाळात नोकरदार व्यक्तींना कमी त्रास सहन करावा लागतो परंतु सामान्य नागरीकांना वृद्धावस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते.

वृद्धांची आर्थिक स्थिती

अ.क्र.	पर्याय	चांगली%	सरासरी%	हालाखीची%
१	नोकरदार वर्ग	३०	५६	१४
२	सर्वसामान्य वृद्ध	१८	१५	६७
३	महिला	३०	६०	१०

वरील सारणी वरून दिसून येते की, नोकरदार वृद्धापेक्षा सर्वसामान्य वृद्धांची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची आहे व त्याचे प्रमाण ६७ टक्के इतके आहे. वृद्ध महिलांची स्थिती सारासरी अल्याचे अध्ययनामधून स्पष्ट झाले आहे आणि त्याचे प्रमाण ६० टक्के इतके आहे.

सामाजिक स्थिती :

वृद्धत्व हे वैयक्तिक असले तरी ते केवळ एका व्यक्ती पुरते मर्यादित नसते तर त्याचा समाजावरही परिणाम होत असतो. त्यामुळेच वृद्धांची समस्या सामाजिक समस्या ठरत आहे. वृद्धावस्थेमध्ये व्यक्तीच्या दर्जा आणि भूमिकामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झालेले असताच सामान्यपणे दर्जा व भूमिकामधील बदल हे न्हासात्म असते. त्यामुळे वृद्ध व्यक्तीच्या मनामध्ये न्युनगंडाची भावना तयार झालेली असते. वृद्धावस्थेमध्ये न्युनगंड निर्माण होण्याकरिता पुढील कारणे कारणीभूत आहे.

- १) शारीरिक दुर्बलता निर्माण होणे.
- २) उत्पादन प्रक्रियेतील सहभाग कमी होणे किंवा उत्पन्न कमी होणे.
- ३) निर्णय प्रक्रियेपासून अलिप्त असणे.
- ४) पूर्वीचा मान सन्मान प्राप्त न होणे.
- ५) सामाजिक परिवर्तनामध्ये आपल्या भूमिकांना योग्य स्थान नसणे.

अन्य स्थिती :

वृद्धावस्थेमध्ये वृद्धांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. वृद्धावस्थेमध्ये व्यक्तीमध्ये अनेक प्रकारचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष बदल पुढील प्रमाणे पाहावयास मिळतात.

- १) परावलंबत्वाची भावना मोठ्या प्रमाणात वाढत जाणे. कारण व्यक्ती शारीरिक, मानसिक, आर्थिकदृष्ट्या इतरांवर अवलंबून असतो. त्याचा परिणाम त्याच्या वागण्यावर झालेला दिसून येतो.



- २) वृद्धावस्थेमध्ये समायोजन करण्यासाठी अनेक अडचणी निर्माण झालेल्या असतात. मित्रांमध्ये, कुटुंबामध्ये, समाजामध्ये तसेच निसर्गातली बदला सोबत व्यक्तीला समायोजन करावे लागते. परंतु वृद्धावस्थेमध्ये झालेल्या बदलामुळे परिस्थितीशी समायोजन साधत असतांना मर्यादा येत असल्याने सर्वच वृद्धांना समायोजन शक्य होत नाही.
- ३) सेवानिवृत्त वृद्धांना काम नसणे, पैसा नसणे यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात विशेषतः आर्थिक समस्या कारण गरजा कमी झालेल्या नसतात परंतु पैशाचा ओघ कमी झालेला असतो. कुटुंबामध्ये वेगळी भूमिका पार पाडावी लागते त्यामुळे वैचारीक मतभेद निर्माण होत असतात.
- ४) आरोग्यामध्ये चडउतार होणे हे वृद्धावस्थेचे लक्षण मानल्या जाते. आरोग्यातील बदलाचा परिणाम मानसिक स्थितीवर होतो. वृद्धावस्थेमध्ये चिडचिड करणे, मानसिक अस्वस्थता, हेकेखोरपणा, इत्यादी समस्या जास्त असल्याचे निदर्शनास येते.

#### वृद्धावस्थेमध्ये वृद्धांची स्थिती बिकट होण्याची कारणे

- १) संयुक्त कुटुंबपद्धतीचा न्हास होणे.
- २) नागरीकरण आणि शहरीकरणचा वाढता प्रभाव.
- ३) पाश्चात्य संस्कृतीचे मोठया प्रमाणात झालेले अनुकरण आणि विकास.
- ४) ग्रामीण समाजव्यवस्थेत झालेले परिवर्तन.
- ५) सामाजिक मूल्य आणि प्रमाणकामध्ये निर्माण झालेली विसंगती.
- ६) औद्योगिककरणाची व्यवस्था आणि त्यामध्ये कुशल कारागीना देण्यात येणारे प्रधान्य.
- ७) सामाजिक जाणीवेच्या विचारांचा प्रभावी प्रसार न होणे.
- ८) वृद्धावस्थेमध्ये शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक घटकामध्ये ण्णलेल्या परिवर्तनाशी समायोजना अभाव.

#### शोध निबंधाचे निष्कर्ष :

- १) संयुक्त कुटुंबपद्धतीपेक्षा विभक्त कुटुंब पद्धतीमध्ये वृद्धांच्या समस्यांची त्रिवृता अधिक आहे.
- २) ग्रामीण भागापेक्षा नागरी भागामध्ये वृद्धांच्या समस्या अधिक आहेत.
- ३) वृद्धावस्थेत बहुतांश वृद्धांना आर्थिक समस्या मोठया प्रमाणात असल्याचे दिसून येते.
- ४) बहुतांश वृद्धांना मानसिक समस्या असल्याचे दिसून येते.
- ५) सामाजिक परिवर्तनामुळे वृद्धांकडे समाजाचा पाहण्याचा दृष्टिकोनामध्ये बदल झालेला दिसून येतो.
- ६) पुढच्या पिढीला जीवनाचा वारसा देण्याच्या वृद्ध जीवनाच्या शेवटी हालाखीची अवस्थेत जीवन जगत आहेत.

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :

- १) आगलावे प्रदिप, भारतीय सामाजिक संरचना आणि समस्या, साईनाथ प्रकाशन, २००९
- २) लोटे रा.ज., भारतीय समाज व सामाजिक समस्या, पिंपळापुणे अँड पब्लीशर्स, नागपूर,
- ३) आगलावे प्रदिप, भारतीय सामाजिक संरचना आणि समस्या, साईनाथ प्रकाशन, २००९
- ४) लोटे रा.ज., भारतीय समाज व सामाजिक समस्या, पिंपळापुणे अँड पब्लीशर्स, नागपूर
- ५) लोटे रा.ज., भारतीय समाज व सामाजिक समस्या, पिंपळापुणे अँड पब्लीशर्स, नागपूर,
- ६) आगलावे प्रदिप, भारतीय सामाजिक संरचना आणि समस्या, साईनाथ प्रकाशन, २००९



"ज्ञान, विज्ञान आणि सुसंस्कार यासाठी शिक्षण प्रसार"

- शिक्षणमंत्री श्री. बापूजी राऊत

**Dattajirao Kadam Arts, Science and Commerce College, Ichalkaranji**  
Shri Swami Vivekanand Shikshan Sanstha's  
Tal. Hatkanangale, Dist. Kolhapur - 416115. Phone: (0230) 2420412. Website : www.dkasc.ac.in, E-mail : dkasccollege@gmail.com

Department of Sociology

And

Marathi Samajshashtra Parishad

Jointly Organized Two Days National Conference

on

**"Environment, Labour, Health and Globalized Society"**

5<sup>th</sup> and 6<sup>th</sup> April, 2023

**CERTIFICATE**

This is to certify that Dr./Mr./Mrs./Ms./Prof. Ameish Sheikhishna Gawande of Shri Dhobekar Kala Mahavidhyalaya Khadki - Akola has participated in two days National Conference on "Environment, Labour, Health and Globalized Society" as a Delegate/Resource Person/Chair Person/Member of the Organizing Committee. He/She has individually/ jointly presented the paper entitled अपराधी विभागातील स्वारस्यीत क्षेत्रातील पारिपूर्यातील

व्यापिक व्यवस्थाने सामाज्यात्मिक अर्थव्यवस्था

Dr. Sampat Kale  
Convener

R.C.C. Committee (R.C.No..7..)

Dr. Rahul Bhagat  
President

Marathi Samajshashtra Parishad

Dr. Arjun Jadhav  
Convener

D.K.A.S.C. College, Ichalkaranji.

Dr. Anil Patil  
Principal

ISSN Impact Factor - 8.31

ISSN 0022-274X

# समाजशास्त्र संशोधन पत्रिका

वर्ष-४० / अंक-२४ / मार्च २०२३



३२ वे राष्ट्रीय अधिवेशन विशेषांक

संपादक

डॉ. राहुल भागत

कार्यकारी संपादक

डॉ. अर्जुन जाधव

मराठी समाजशास्त्र परिषदेचे मुखपत्र



अ.क्र.	लेखाचे शीर्षक	लेखकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
१००.	समाज बदलात आणि नृत्वायुष्या	डा.सुनील	२३१-२३१
१०१.	समाज माध्यमांवरील जातिरातीचा समाजशास्त्रीय परिणाम	डा.सुनील	२३२-२३४
१०२.	समाजमाध्यमांच्या परिणामांचा समाजशास्त्रीय परिणाम	प्रा.डा.सुनील	२३५-२४२
१०३.	पर्यावरण संवर्धनात प्रसार माध्यमांची भूमिका	डा.गोपाळ	२४३-२४३
१०४.	चढती जीवनशैली आणि आरोग्य	प्रा.डा.महाती	२४४-२४४
१०५.	चढती जीवनशैली आणि आरोग्य	कुरलाकर	
१०६.	शेतकरी (क्राउड फंडिंग) द्वारे पर्यायी व्यवसाय चढता : एक टीका	डा.मेघा देशपांडे	२४५-२४५
१०७.	चढती जीवनशैली आणि आरोग्य	डा.आनंद ममळ	२४६-२४६
१०८.	नागरी समाजातील समस्या एक दृष्टिकोन	प्रा.डा.गंगाधर चानू चव्हाण	२४७-२४७
१०९.	आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाच्या समस्यांचा समाजशास्त्रीय अध्ययन	प्रा.डा.सुनील प्रकाश	२४८-२४८
११०.	शेतकरी काम करणाऱ्या कष्टकरी महिलांच्या समस्या : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	गायगोळ	
१११.	भारतातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा अभ्यास	डा.सुनिता एम. धोपटे	२४९-२४९
११२.	शेतकरी आत्महत्या एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	(पाडर)	
११३.	भारतातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा अभ्यास	प्रा.डा.श्रीराम खाटे	२५०-२५०
११४.	शेतकरी आत्महत्या एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	प्रा.डा.संजय जे. भगत	२५१-२५१
११५.	शेतकरी कुटुंबाच्या समस्यांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी एक अध्ययन	डा.बामणे मारोती	२५२-२५२
११६.	शेतकरी चळवळी व वर्तमान कृषी व्यवस्था (विशेष संदर्भ : महाराष्ट्रातील सन १९८० ते १९९० दरम्यान प्रमुख आंदोलने)	डा.एच.यु.पेटकर	२५३-२५३
११७.	लिव गावातील रासायनिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे व्यष्टी अध्ययन	डा.राज चव्हाण	२५४-२५४
११८.	पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन काळाचा गरज	कु.वैष्णवी कमलेश सावंत	२५५-२५५
११९.	पश्चिम महाराष्ट्रातील कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या चळवळीचा समाजशास्त्रीय अभ्यास	कु.पुर्वा शंकर मापारी	२५६-२५६
१२०.	अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील पाणोपट्ट्यातील सामाजिक समस्यांचे समाजशास्त्रीय अध्ययन	प्रा.डा.प्रतिभा रंगराव	२५७-२५७
१२१.	अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळ : वैज्ञानिक दृष्टिकोन	विरादार	
१२२.	भारतीय नागरिकांची सामाजिक व राजकीय कर्तव्ये एक समाजशास्त्रीय सिंहावलोकन	डा.संजय शामराव कांबळे	२५८-३०३
१२३.	राष्ट्राच्या विकासाकरिता संविधानातील समतेच्या मूल्याची आवश्यकता	प्रा.डा.अमरिष एस. गावंडे	३०४-३०७
१२४.	कोविड-१९ लॉकडाऊनचा भारतीय महिलांच्यावर झालेल्या सायबर हिंसाचाराचा समाजशास्त्रीय अभ्यास	डा.संतोष गोविंद गांगुडे	३०८-३११
१२५.		डा.प्रदीप एच.गजभिये	३१२-३१५
१२६.		डा.माधुरी झाडे	३१६-३२०
१२७.		प्रा.राजेंद्र पुंडलिक पवार	३२१-३२९

## अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील पाणीपट्ट्यातील सामाजिक समस्यांचे समाजशास्त्रीय अध्ययन

\* प्रा. डॉ. अमरिप एस. गावंडे

### प्रस्तावना :

भारत हा कृषीप्रधान देश असल्यामुळे भारताची ग्रामीण अर्थव्यवस्था सर्वांशीन कृषीवरच आधारलेली आहे. भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ७१ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागामध्ये वास्तव्य करताना असते. भारताच्या ग्रामीण भागामध्ये राहणाऱ्या बहुतांश लोकांचा व्यवसाय शेती हाच आहे. म्हणूनच भारत हा कृषीप्रधान देश आहे, असे म्हटल्या जाते. पश्चिम विदर्भाचा विचार केल्यास या भागातील बहुतांश शेतकरी कोरडवाहू शेती करतात. अमरावती महामूल विभागातील पान जिल्ह्यांपैकी अमरावती, अकोला व बुलडाणा या तीन जिल्ह्यांमध्ये खारजमीन क्षेत्राचा समावेश होतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून खारजमीन क्षेत्रातील शेतकरी दुष्काळाची झळ सहन करीत असल्यामुळे दारिद्र्य व सामाजिक समस्यांनी ग्रस्त झालेला आहे. अमरावती, अकोला व बुलडाणा जिल्ह्यांमध्ये खार जमिनीचे क्षेत्र ४,६९,२२२ हेक्टर इतके आहे. यामध्ये एकूण १६ तालुके व ८९४ गावांचा समावेश होतो. याच क्षेत्रामध्ये शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे संशोधनाने संशोधन प्रकल्पाकरीत प्रस्तुत अध्ययन विषयाची निवडकेली आहे.

अमरावती विभागातील याच खारजमीन क्षेत्राला पूर्ण खोऱ्यातील खारे पाणी पट्टा असे देखील म्हटले जाते. खार पाणी पट्ट्यातील जमीन प्रचंड क्षारयुक्त आहे. या भागातील क्षारयुक्त आहे. या भागातील क्षारयुक्त जमीनीमुळे जमीनीत झीरपणारे पावसाचे पाणी देखील क्षारयुक्त बनते. क्षारयुक्त जमीन आणि जमीनीतील पाणी तसेच या भागात जलसिंचनाकरीत कुठलाच मोठा प्रकल्प नसल्यामुळे जल सिंचनाची सोय होवू शकत नाही. परिणामतः शेतकऱ्यांना कोरडवाहू शेतकरी लागते. विशेषतः याच भागात पावसाचे अत्यल्पप्रमाण असल्यामुळे शेतकऱ्यांना नेहमीच कोरडा दुष्काळाला सामोरे जावे लागते. या भागातील खारजमीन क्षेत्राचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्ना वर विपरित परिणाम होत असल्यामुळे शेतकरी स्थानांतरण करीत असल्याचे चित्र पहावयास मिळते. शेती क्षेत्राकरीत पाण्याचे दुर्मिळ असण्यासोबत या भागात पिण्याकरीत आवश्यक असणाऱ्या शुध्द जल पुरवठ्याचा देखील प्रचंड अभाव आहे. परिणामतः खारे पाणी पट्ट्यातील लोकांना क्षारयुक्त पाण्यानेच आपली तहान भागवावी लागत आहे. त्यामुळे या भागातील लोकांना मोठ्या प्रमाणावर किडनीचे आजार, काविळाचे आजार तसेच हगवण, कुपोषणासारखे आजारांची भिषणता देखील या ठिकाणी पहावयास मिळते. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला त्यांच्या दारिद्र्य या बरोबरच त्यांच्या सामाजिक समस्या व त्यांची खालावलेली सामाजिक स्थिती सुध्दा जबाबदार आहे. या भागातील शेतकऱ्यांसमोर प्रामुख्याने खारजमीन, जमीनीतील खारे पाणी याच बरोबर अनारोग्य, सकस आहाराचा अभाव, दारिद्र्य, कुपोषण, कर्जवाजारीपणा, शिक्षणाचा अभाव, विजेची समस्या, जलसिंचनाचा अभाव, तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव इ. समस्या प्रमुख आहेत. पोषीच्या समोर अनेक सामाजिक, आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या सामाजिक, आर्थिक समस्यांची योग्य कारणे शोधून त्यांच्या सामाजिक स्थितीचा शास्त्रीय पध्दतीने अभ्यास करून त्यांच्या सामाजिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्याकरीत या शोध निबंधाचे सहकार्य होईल.

### संशोधनाचे महत्त्व :

जल प्रकल्पांमध्ये केलेला पाणीसाठा हा दुर्मिळ आणि अमूल्य आहे. हा साठा करण्यासाठी समाजाचा पैसा खुप मोठ्या प्रमाणावर खर्च पडलेला आहे. दर बारा कोसावर भापा बदलते या प्रमाणे प्रत्येक ठिकाणी पाण्याची वेगवेगळी चव चाखायला मिळते. महाराष्ट्रातील एक विशिष्ट भाग म्हणून विदर्भाचे नाव घेतल्या जाते. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लाभलेल्या या विदर्भात पूर्णा नदीच्या खोऱ्यात अमरावती, अकोला, बुलडाणा या तीन जिल्ह्यात अतिशय सुपिक परंतु क्षारयुक्त जमिनीचा विस्तृत मोठा भूप्रदेश आहे. या भागातील जमीन खोलवर निव्वळकाळी, भारी, गाळाची व उपजत सुपिक आहे. हा भूप्रदेश पूर्वपश्चिम १७० कि.मी. लांब व उत्तर दक्षिण सरासरी ५५ कि.मी. रुंदीचा आहे. विदर्भातील १६ तालुक्यांचा कमी अधिक भूभाग पूर्णा खोऱ्यातील खारेपाणी पट्टाप्रदेशात समाविष्ट आहे. पूर्णा खोऱ्यातील सुपिक जमीन क्षारयुक्त व भूगर्भातील पाणी सुध्दा क्षारयुक्त दूषित व आरोग्य दृष्टय अपायकारक असल्यामुळे हा बहुमोल विभाग विविध समस्यांनी ग्रस्त तथा टंचाई ग्रस्त आहे. या खारेपाणीपट्टा प्रदेशात जीवनावश्यक पिण्याचे पाणी या प्रमुख समस्यांला सतत तोंड द्यावे लागते. पिण्याचे पाणी अर्थात गोडे पाणी टंचाई निवारण, कृषी व इतर सर्वांगीण विकास साध्य व्हावा या साठी तसेच विभागातील शेतकरी विशेषतः अल्पभूधारक म्हणजे असे शेतकरी की ज्यांच्याजवळ ५ एकरा पेक्षा कमी जमीन आहे अशा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व सामाजिक समस्यांचा मागोवा घेण्याच्या अनुषंगाने तसेच पाण्यासंबंधीच्या विविध स्तरातल्या जनतेच्या गरजा, शेतकऱ्यांच्या समस्या व निसर्गाच्या स्वतःच्या मागण्या यांच्या संदर्भात जल संबंधीत समस्या विषयी शाश्वत स्वरूपाची उत्तरे शोधण्याकरीत अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील पाणीपट्ट्यातील सामाजिक समस्यांचे समाजशास्त्रीय अध्ययन हा विषय संशोधनासाठी निवडलेला आहे.

संशोधनपद्धती : कोणत्याही सामाजिक संशोधनाचे काही निश्चित तरेचे अस्तित्वात त्या उद्देशांची प्राप्ती करण्यासाठी संशोधकाच्या योजनेनुसार रूपात संशोधन कार्य करावे लागते. त्यासाठी संशोधकाच्या यत्नात संशोधन आराखडा तयार करावा लागतो. यात संशोधन आराखड्यांशिवाय वस्तुनिष्ठ संशोधन करणे अशक्य आहे. म्हणूनच सदर अध्ययनाचा विषय व संशोधनाची उद्दिष्टे लक्षात घेऊन संशोधनास उपयुक्त अशा वर्णनात्मक व निदानात्मक संशोधन आराखड्याची संशोधकाचे निवड केली. वर्णनात्मक संशोधन हे एखादी व्यक्ती, समूह, समाज किंवा घटना व त्याची स्थिती यांच्या वैशिष्ट्यांचे यथायोग्य वर्णनकरण्याच्या हेतूने प्रेरित झालेले असते. तर निदानात्मक संशोधनामध्ये एखाद्या समस्यांची वास्तविक कारण परंपरा समजून घेऊन ती समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने योग्य उपाय योजना सुचविल्या जातात. म्हणूनच प्रस्तुत संशोधनाच्या उद्दिष्टांमध्ये वर्णनात्मक व निदानात्मक अशा दोन्ही आराखड्यांतून आग्रहस्थळे किंवा लक्षणे एकत्रित केली आहेत.

संशोधन विषय निश्चित केल्यानंतर संशोधनाच्या विविध पध्दतीशास्त्रीय पायऱ्यांची चर्चा सदर प्रकरणात करण्यात आलेली आहे. सर्वसाधारणपणे संशोधनासाठी खालील प्रमुख पध्दती शास्त्रीय पायऱ्यांचा किंवा पॉल्यूच्या अनुषंगाने सदर संशोधनाचा कृती आराखडा प्रस्तुत केला आहे.

१. क्षेत्रकार्य अध्ययन पध्दती, २. नमुनानिवड योजना, ३. तथ्य संकलन योजना, ४. संख्याशास्त्रीय योजना.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख सामाजिक समस्या : समस्या म्हणजे असा प्रश्न किंवा अडचण की ज्या वर काही तरी उपाययोजना करणे गरजेचे असते प्रत्येक समाजात सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजकीय इत्यादी विविध प्रकारच्या समस्या आढळत असल्या तरी प्रत्येक समाजातील समस्यांचे स्वरूप आणि त्यांची तीव्रता या मध्ये तफावत असते. भारतीय समाज हा प्रामुख्याने नागरी समाज, ग्रामीण समाज, आदिवासी समाज या तीन समुदायांमध्ये विभागलेला असून या समुदायातील कृषी क्षेत्राशी निगडित व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या ह्या अत्यंत विकट स्वरूपाच्या आहेत. खारजमीन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या : खारजमीन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीचे अध्ययन करतांना तेथील शेतकऱ्यांना कोणत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता पुढील समस्या समोर आल्या आहेत या समस्यांचे वर्गीकरण तिन भागात करण्यात आले असून ते प्रामुख्याने जमीनीच्या समस्या, पाण्याच्या समस्या आणि शेतकऱ्यांना उद्भवणाऱ्या समस्या यांच्याशी संबंधित आहे.

जमिनी बाबत समस्या-

१. या जमिनीतील मातीच्या कणात सोडीयम असल्यामुळे या जमिनीत अनेक घातक गुणधर्म निर्माण झालेले आहेत. जसे जमिनीच्या पोटातून पाणी निघून न जाणे, जमीन चिभडवणे, जमिनीत डेरे पडणे व वाळल्यावरती खुपटणक बनणे.
२. या जमिनीतील जलवाहकता अत्यल्प आहे.
३. पावसाळ्यात जमिनी फुगणे, उन्हाळ्यात आकुंचनपावून खोल व रुंद भेगा (भुड्या पडणे) या समस्या उद्भवतात.
४. या जमिनीचा सामु (पी.एच.) वाजवी पेक्षा अधिक असल्यामुळे पीक पोषक अन्न द्रव्यांच्या समतोल पणात बिघाड होऊन त्याचा उत्पादक जिवानुच्या वाढीवर अनिष्ट परिणाम होतो. परिणामी पिकाचे उत्पादन घटते.
५. अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील पाणी विमल्युक्त असून ते ओलीतासाठी उपयुक्त नाही. या पाण्याने सतत ओलीत केल्यास जमिनीच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मात अधिकच बिघाड होऊन तिची उत्पादन क्षमता घटते. असा शेतकऱ्यांचा सुध्दा अनुभव आहे.

खार पाण्याबाबत समस्या-

१. अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील भूगर्भाचे पाणी हे खारे असून त्यामध्ये क्लोराईड व सोडीयम क्षार हे अधिक प्रमाणात आढळतात.
२. पाण्यातील क्षारतेच्या समस्येमुळे या भागातील जमिन ओलीतासाठी अयोग्य असलेली आढळून येते.
३. या पाण्याचा वापर ओलीतासाठी केल्यास या जमिनी अधिक टणक बनतात व अशा जमिनीमध्ये पुढील पिके चांगली येत नाहीत.
४. पिण्याच्या पाण्यावर आरोग्य अवलंबून असल्याने या परिसरातील लोकांना पिण्याच्या पाण्यातून अनेक आजार जसे-किडनीस्टोन व पोटाचे विकार यांना सामोरे जावे लागते.

शेतकऱ्यांच्या समस्या-

१. दारिद्र्य : अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील सर्वेक्षित अल्पभूधारक शेतकऱ्यांमध्ये जवळपास ७८.२५ टक्के शेतकरी हे दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणारे हे शेतकरी स्वरूपाच्या मूलभूत गरजा देखील पूर्ण करू शकत नाहीत. त्यांच्या जवळील जमीनीचे आकारमान सुध्दा अतिशय कमी त्यामुळे त्यांना उत्पन्न मिळू शकत नाही व त्यांच्यातील दारिद्र्य ही समस्या वाढतच चालली आहे.

२. निसर्गाचा लहरीपणा : शेती व्यवसाय हा निसर्गाचा अवलंबून आहे. शेती ही पूर्णपणे नियंत्रित करता येऊन असते असे अनेक अर्थशास्त्रज्ञ, अनियमित वृष्टी या चक्रात भारतीय शेती असून महाराष्ट्रातील पर्यायाने अमरावती विभागातील शेती खाली आणून नारी विदर्भातील शेती ही निसर्गाच्या अवलंबून राहून राहिली असते असे शिवाय या विभागात शेतकऱ्यांच्या सुविधा सुद्धा कमी आहेत. त्यातल्या त्यात खारेपाणी पट्ट्यातील शेती ही निसर्गाच्या गोडपाण्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. अशा वेळी अनियमित पावसाच्या प्रमाणाचा खराफटका येथील शेतकऱ्यांना बसतो आहे त्यामुळे त्यांचा उत्पादकता कमी होत असून त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक जीवनावर त्यांचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे. जेव्हा भरपूर पाऊस पडतो आणि ज्या भागात रब्बीसाठी भरपूर पाणी असते, अशा बहुतेक भागात धुकें आणि दव पडते. यामुळे भुरी, करपा, डाउनी असे गेम येतात. या रोगामुळे सर्वाना फटका बसतो. नुकसान शेतकऱ्यांचेच होते. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि त्यामुळे होणाऱ्या शेणकिडींमुळे होणाऱ्या खर्चातही वाढ होते आणि नुकसानात ही वाढ होते.

३. अल्पउत्पादन : अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील अल्प उत्पादकता ही एक प्रमुख समस्या असून तेथील जमीन क्षारयुक्त असल्यामुळे तेथील जमीनीची उत्पादकता कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अतिशय हालखिचे जीवन जगावे लागते. जमीनीचे अल्प उत्पादकतेमुळे त्यातून उत्पादित होणाऱ्या धान्यातून शेतकऱ्यांची अन्न धान्याची दैनंदिन गरज भागविली जात नाही.

४. क्षारयुक्त पाण्यामुळे होणारे आजार : अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना क्षारयुक्त पाण्याचा वापर शेतासाठी आणि पिण्यासाठी करावा लागतो. क्षारयुक्त पाणी हे जड असल्यामुळे या पासून अनेक शारीरिक व्याधी मध्ये वाढहोताना आढळून येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा बराच खर्च हा आरोग्यावर होतो.

५. पिण्यायोग्य पाण्याचा अभाव : अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील पिण्याचे योग्य पाणी नाही. या करीता शासनाची कुठलीही नळ योजना नाही. मुलगांवी व प्रतिगांवी योजनेसाठी कुठलेही नियोजन नाही. त्यामुळे तीन जिल्ह्यातील जवळपास ५० लाखा वर नागरीकांना नाईलाजस्तव हे पाणी प्यावे लागते. त्यामुळे जीवनास मारक असणारे पाणी मारक ठरत आहे.

६. कर्जबाजारीपणा : शेतकऱ्यांना त्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नातून त्यांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता होत नाही त्यामुळे शेतकरी कर्ज काढतात. शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यामध्ये अधिकोष आणि सावकार या दोन स्रोतांचा समावेश होत असून अधिकोषाकडून जे कर्ज दिले जाते ते प्रामुख्याने बागायती शेतकऱ्यांना दिले जाते कोरडवाहू शेतकऱ्यांना मात्र अधिकोषाकडून कर्ज मिळत नसल्यामुळे हे शेतकरी सावकाराकडून कर्ज घेतात. परंतु शेतातून होणाऱ्या अल्पउत्पादनामुळे शेतकरी वेळेवर कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत व त्यांच्या वरील कर्जाचा बोझ वाढत जातो. महाराष्ट्रातील इतर भागापेक्षा अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील भूमीची उत्पादकता कमी दिसून येते. एकूण अन्न धान्य पिकांच्या बाबतीत अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्र हे पूर्णाव्दिर्भ तसेच महाराष्ट्राच्या तुलनेत उत्पादकतेत कमी दिसून येते याचा सरळपरिणाम शेतकऱ्यांच्या कौटुंबिक उत्पादनावर होतो. आणि शेतकरी आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी शेतकरी विविध स्रोता कडून कर्ज घेते.

७. निरक्षरता : अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील बहुतांश शेतकरी अल्प साक्षर आहेत. त्यामुळे अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. सावकाराकडून होणारी आर्थिक पिळवणूक, शास्त्रोक्त पध्दतीने शेतीकरण्याचे ज्ञान त्यांना अवगत होत नाही. एकंदरीत अल्प साक्षरतेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.

८. मार्गदर्शनाचा अभाव : अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना शेती करण्याचे कुठलेही मार्गदर्शन मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादन क्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होतो.

९. पशुव्यवस्थापनाचा अभाव : अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात जोडधंदा करण्यासाठी पशुंचे फार महत्त्व असलेले दिसून येते. परंतु या पशुंचे योग्य व्यवस्थापन व काळजी घेण्यासाठी योग्य व्यवस्था, जसे त्यांना गोठा, चारा इ. ते उपलब्ध करून देऊ शकत नाहीत त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होताना आढळते. पूर्णा खोऱ्यातील खारेपाणीपट्ट्यातील खान्या पाण्याचा जनावरांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला असून सदर क्षेत्रातचा राटंचाईमुळे पशुधन कमी झाले आहे. त्यामुळे शेतीला आवश्यक असलेले शेणखत, कंपोस्ट खते, सेंद्रीय खते, गांडूळ खत इत्यादीचा वापर शेतकरी करू शकत नाहीत व शेतीची गुणवत्ता घटत आहे.

१०. पाण्यामुळे होणारे जीवांचे नुकसान : अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील क्षारयुक्तपाण्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांच्याच नव्हे तर शेतमजूर शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्य व इतर लोकांच्याही जीवांचे नुकसान होत असून त्यांना अनेक आजारांना सामोरे जावे लागत आहे.

११. आरोग्य विषयक सुविधांचा अभाव : अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रात असणारी क्षारयुक्तपाण्याची समस्या आणि त्यातून उद्भवणारे आजार या पासून बचाव करण्यासाठी किंवा त्या आजाराचे प्रमाण वाढू नये म्हणून आवश्यक आरोग्य सुविधा खारेपाणीपट्ट्यातील बहुतांश गावात अजूनही उपलब्ध नाहीत. खारेपाणीपट्ट्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात संबंधीत

२. निसर्गाचा लहरीपणा : शेती व्यवसाय हा निसर्गावर अवलंबून आहे. शेती ही पूर्णपणे नियंत्रित अवस्थेत असते असा अर्थ अस्वीकार्य. अनियमित वृष्टी या चक्रात भारतीय शेती असून महाराष्ट्रातील पर्यायाने अमरावती विभागातील शेती याला अत्यंत नमी. विदर्भातील शेती ही निसर्गाच्या अवकृपाचा मजल गमना करीत असते शिवाय या विभागात शिन्मनाच्या सुविधा सुद्धा कमी आहेत. त्यातल्या त्यात खारेपाणी पट्ट्यातील शेती हा निसर्गाच्या गोडपाण्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. अशा वेळी अनियमित पावसाच्या प्रमाणाचा खराफटका येथील शेतकऱ्यांना बसतो आहे त्यामुळे त्यांचा उत्पादकता कमी होत असून त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक जिवनावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे. जेव्हा भरपूर पाऊस पडतो आणि ज्या भागात रघोरसाठी भरपूर पाणी असते, अशा बहुतेक भागात धुके आणि दव पडते. यामुळे भुरी, करपा, डाउनी असे रोग येतात. या रोगामुळे सर्वत्र पिकांना फटका बसतो. नुकसान शेतकऱ्यांचेच होते. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि त्यामुळे होणाऱ्या शंकाकिडीं मुळे होणाऱ्या खर्चातही वाढ होते आणि नुकसानात ही वाढ होते.
३. अल्पउत्पादन : अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील अल्प उत्पादकता ही एक प्रमुख समस्या असून येथील जमीन क्षारयुक्त असल्यामुळे तेथील जमीनीची उत्पादकता कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अतिशय हालाखीचे जीवन जगावे लागते. जमीनीचे अल्प उत्पादकतेमुळे त्यातून उत्पादित होणाऱ्या धान्यातून शेतकऱ्यांची अन्न धान्याची दैनंदिन गरज भागविली जात नाही.
४. क्षारयुक्त पाण्यामुळे होणारे आजार : अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना क्षारयुक्त पाण्याचा वापर शेतासाठी आणि पिण्यासाठी करावा लागतो. क्षारयुक्त पाणी हे जड असल्यामुळे या पासून अनेक शारीरिक व्याधी मध्ये वाढहोतांना आढळून येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा बराच खर्च हा आरोग्या वर होतो.
५. पिण्यायोग्य पाण्याचा अभाव : अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील पिण्याचे योग्य पाणी नाही. या करीता शासनाची कुठलीही नळ योजना नाही. मुलगामी व प्रतिगामी योजनेसाठी कुठलेही नियोजन नाही. त्यामुळे तीन जिल्ह्यातील जवळपास ५० लाखा वर नागरीकांना नाईलाजस्तव हे पाणी प्यावे लागते. त्यामुळे जीवनास मारक असणारे पाणी मारक ठरत आहे.
६. कर्जबाजारीपणा : शेतकऱ्यांना त्यांना मिळणाऱ्या उत्पादनातून त्यांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता होत नाही त्यामुळे शेतकरी कर्ज काढतात. शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यामध्ये अधिकोष आणि सावकार या दोन स्त्रोतांचा समावेश होत असून अधिकोषाकडून जे कर्ज दिले जाते ते प्रामुख्याने वागायती शेतकऱ्यांना दिले जाते कोरडवाहू शेतकऱ्यांना मात्र अधिकोषाकडून कर्ज मिळत नसल्यामुळे हे शेतकरी सावकाराकडून कर्ज घेतात. परंतु शेतातून होणाऱ्या अल्पउत्पादनामुळे शेतकरी वेळेवर कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत व त्यांच्या वरील कर्जाचा बोझ वाढत जातो. महाराष्ट्रातील इतर भागापेक्षा अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील भूमीची उत्पादकता कमी दिसून येते. एकूण अन्न धान्य पिकांच्या बाबतीत अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्र हे पूर्णविदर्भ तसेच महाराष्ट्राच्या तुलनेत उत्पादकतेत कमी दिसून येते याचा सरळपरिणाम शेतकऱ्यांच्या कौटुंबिक उत्पादनावर होतो. आणि शेतकरी आपल्या दैनंदिन गरजापूर्ण करण्यासाठी शेतकरी विविध स्त्रोता कडून कर्ज घेते.
७. निरक्षरता : अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील बहुतांश शेतकरी अल्प साक्षर आहेत. त्यामुळे अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. सावकाराकडून होणारी आर्थिक पिळवणूक, शास्त्रोक्त पध्दतीने शेतीकरण्याचे ज्ञान त्यांना अवगत होत नाही. एकंदरीत अल्प साक्षरतेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.
८. मार्गदर्शनाचा अभाव : अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना शेती करण्याचे कुठलेही मार्गदर्शन मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादन क्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होतो.
९. पशुव्यवस्थापनाचा अभाव : अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात जोडधंदा करण्यासाठी पशुंचे फार महत्त्व असलेले दिसून येते. परंतु या पशुंचे योग्य व्यवस्थापन व काळजी घेण्यासाठी योग्य व्यवस्था, जसे त्यांना गोठा, चारा इ. ते उपलब्ध करून देऊ शकत नाहीत त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होतांना आढळते. पूर्णा खोऱ्यातील खारेपाणीपट्ट्यातील खाऱ्या पाण्याचा जनावरांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला असून सदर क्षेत्रातचा राटंचाईमुळे पशुधन कमी झाले आहे. त्यामुळे शेतीला आवश्यक असलेले शेणखत, कंपोस्ट खते, सेंद्रीय खते, गांडूळ खत इत्यादींचा वापर शेतकरी करू शकत नाहीत व शेतीची गुणवत्ता घटत आहे.
१०. पाण्यामुळे होणारे जीवांचे नुकसान : अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील क्षारयुक्तपाण्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांच्याच नव्हे तर शेतमजूर शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्य व इतर लोकांच्याही जीवांचे नुकसान होत असून त्यांना अनेक आजारांना सामोरे जावे लागत आहे.
११. आरोग्य विषयक सुविधांचा अभाव : अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रात असणारी क्षारयुक्तपाण्याची समस्या आणि त्यातून उद्भवणारे आजार या पासून बचाव करण्यासाठी किंवा त्या आजाराचे प्रमाण वाढू नये म्हणून आवश्यक आरोग्य सुविधा खारेपाणीपट्ट्यातील बहुतांश गावात अजूनही उपलब्ध नाहीत. खारेपाणीपट्ट्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात संबंधीत

आजारावर औपचे आपो तज्ज इफरगची नेमणक सुध्दा नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळगळीतून जतना ठिकाणी जाऊन उपचार घेण्यावर खर्च होतो त्यामुळे आमच्यांचे आणि आर्थिक नुकसान त्यांना सहन करणे लागत आहे.

१२. भांडवलाची कमतरता : भारतीय शेतकरी कर्जांमध्ये बुडालेला असल्याने त्यांचे एकूण उत्पन्न वाढविण्याचा मार्ग हा शेतमालाच्या विपणनाशी संबंधित आहे. शेतकरी उत्पादित झालेल्या शेतमालास उचित मूल्य प्राप्त होण्यासाठी शेतमालाच्या विपणनाची व्यवस्था चांगली असली पाहिजे. प्रत्यक्षात मात्र गावातील सावकार, अडने, व्यापारी किंवा त्याचे प्रतिनिधी यांनाच शेतकऱ्यांकडून शेतमालाविक्री केल्या जात असल्यामुळे शेतमालास उचित मूल्य प्राप्त होत नाही. एकूण उत्पादनातून कौटुंबिक निर्वाह, बी-वियाणे आणि मजुरांना देण्यासाठी लागणारे धान्य इत्यादीची तरतूद केल्यानंतर विक्री योग्य आधिक्य अतिशय कमी राहते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे एकूण उत्पन्न कमी राहते. म्हणूनच शेतकरी शेततोग्य भांडवलाची उपलब्धता करू शकत नाही.

१३. शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी नाही : अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्राच्या विकासासाठी अनेक योजना कागदोपत्री मंजूर केल्या जाऊन, शासकीय दरबारात मंजूर योजनांची अंमलबजावणी मात्र योग्य रितीने होत नाही परिणामतः शेतकरी वर्गाला त्याचालाभ मिळत नाही.

१४. अधिकारी वर्गाची उदासिनता : अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्राच्या विकासासाठी नेमण्यात आलेला अधिकारी वर्ग आपले कर्तव्य योग्य रितीने पार पाडत नाहीत. ते शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करीत नाही तसेच ते शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात देखील कसूर करताना आढळतात.

१५. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या : आधुनिक काळात ग्रामीण भागात अनेक समस्या आहेत. उदा रू-कर्जबाजारीपणा, बेकारी, दारिद्र्य, नापीकी, इत्यादीमुळे या व्यवसायाप्रति दुरावा निर्माण होत आहे. ज्यामुळे गैर किसानीकरण होऊन ग्रामीण भागात उदर निर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होताना आढळून येतो. परिणामतः भारतात प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करताना दिसून येतात. या समस्येकडे लवकरच लक्ष दिले नाही तर ही समस्या विक्राळ रूप धारण करून देशाचा पोशिंदा वर्ग नष्ट करेल व त्याचे परिणाम सर्व देशालाच भोगावे लागतील.

शेतकऱ्यांच्या समस्या अत्यंत बिकट होत आहेत. पूर्वीनापिकी, साथीचे रोग, मालाला हमीभाव न मिळणे, शेतकऱ्यांचे आरोग्य, निवासाच्या समस्या, शेतकऱ्यांची निरक्षरता, अंधश्रद्धाव्युपणा, परंपरागत उत्पादन पध्दतीचा वापर, अतिवर्षण-अवर्षणाची समस्या, कृषप्रथा, वेठविगारी इत्यादी समस्या प्रमुख होत्या. त्यातील काही समस्या आजही कायम असून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही समस्या नव्याने निर्माण होऊ पाहत आहे. खार पाणीपट्यातील शेतकरी सुध्दा याला अपवाद नाही. उपरोक्त विविध समस्यांमुळे अमरावती विभागातील खारजमीन क्षेत्रातील शेतकरी पाणी आणि जमीन यांच्या दृष्टिक्रान्त अडकलेला दिसून येतो.

संदर्भ ग्रंथ सूची :

- १) कन्हाडे बी.एम., शास्त्रीय संपोधन पद्धती, पिंपळपुरे अँड कं. पब्लिपर्स, महाल नागपूर ४४००३२
- २) <https://maharashtratimes.indiatimes.com/nagpur-vidarbha-news>
- ३) पाटील वा. भ., पंचायतीराज्य, विद्याप्रकाशन नागपूर,
- ४) आगलावे प्रदिप, ग्रामीण व नागरी समाजशास्त्र, श्री. साईनाथ प्रकाशन-१ भगवाघर कॉम्प्लेक्स धरमपेठ नागपूर.
- ५) हजारें अण्णा, माझे गाव माझे तिर्थ, स्वामी विवेकानंद कृतज्ञता निधी, राळेगण सिद्धी जि.अहमदनगर.
- ६) ठोंवरे सतिष, ग्राम प्रशासन, कैलाप पब्लिकेपन्स, औरंगाबाद
- ७) <https://www.loksatta.com/lokrabha/pustkachepanan/marathi-book-review-22-1163923>
- ८) <https://maharashtratimes.com/editorial/column/time-to-time/shrirang-sharangpani-article-on-problem-of-farmers/article/show/79114293.cms>

\*प्रमुख, समाजशास्त्र विभाग, श्री.धाबेकर कला माविद्यालय, खडकी, अकोला

\*\*\*



Department of English and IQAC, Mungasaji Maharaj Mahavidyalaya, Darwha

In collaboration with

IQAC, SGBAU, Amravati, Department of English and IQAC, Jijamata Arts College, Darwha,  
B.B.Arts, N.B.Commerce and B.P.Science College, Digras, Yashwantrao Chavan Arts and Science Mahavidyalaya, Mangruppir  
On the occasion of International Women's Day



# CERTIFICATE

This is to certify that

Prof./Dr./Mr./Mrs./Ms. Rahul P. Shuge

has actively participated in One Day National Multidisciplinary Conference on "Current Issues In  
Higher Education & Women's Contribution" (CIHEWC-2023) held on  
Friday, 10th March 2023

He/She published, presented oral papers/an invited talk entitled, women  
and Indian politics. Hence the certificate is issued.

Prof. S.A. Waghuney  
Director IQAC

Sant Gadge Baba Amravati  
University, Amravati

Dr. V.B. Raut  
Principal  
Mungasaji Maharaj  
Mahavidyalaya, Darwha

Dr. A.P. Jadhao  
Principal  
Jijamata Arts College,  
Darwha

Dr. A.R. Ladole  
Principal  
B.B.Arts, N.B.Commerce  
and B.P.Science College, Digras

Dr. S.H. Kanherkar  
Principal  
Yashwantrao Chavan Arts  
and Science Mahavidyalaya,  
Mangruppir



ISSN 2454-1974

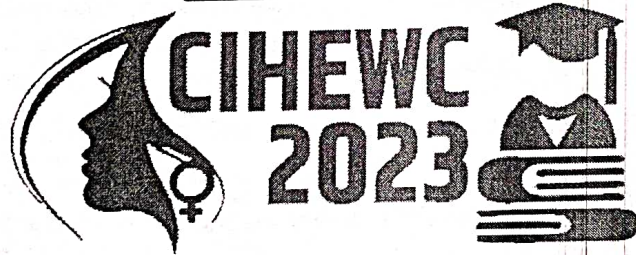
# THE RUBRICS

Journal of Interdisciplinary Studies  
International, Peer Reviewed, Indexed



One Day National Multidisciplinary Conference On  
Current Issues in Higher Education and Women's Contribution

10<sup>th</sup> March 2023



Conference Proceeding: Special Issue Editors  
Ms. Priyanka Ruikar, Dr. Manoj Bhagat  
Dr. Pritee Thakare, Dr. Shrikant Rasekar

Organized by

SGBAU Amravati University, Amravati

Mungasaji Maharaj Mahavidyalaya, Darwaha

Jijamata Arts College, Darwaha

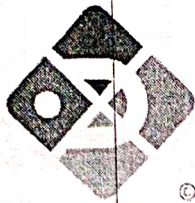
B.B.Arts, N.B.Commerce and B.P.Science College, Digras

Yashwantrao Chavan Arts and Science Mahavidyalaya, Mangrulpir





29	Role of Women in Agriculture   <i>Dr. Shubhangi Vijay Gawande</i>	150
30	Status Of Women in Higher Education in Indian Context <i>Mr. Milind Haribhau Dhale</i>	154
31	Gender Inequality in Higher Education: Indian Context <i>Dr. Pritee Deorao Thakare</i>	158
32	Empowering Women in India's Agrarian Economy <i>Dr. Nilima Tidke</i>	162
33	Some Educated Women Unraveled in Literature <i>Bharat Dnyanba Pattebahadur</i>	165
34	Identity Crisis in Manju Kapur's <i>Difficult Daughters</i> <i>Dr. Nilesh Prakashrao Sulbhewar</i>	170
35	Noise Pollution During Ganesh Utsav Immersion In 2022 In Darwaha City   <i>P. H. Bhagwat</i>	174
36	Women And Administration   <i>Prof. Dr. Lalachand Kisan Ramteke</i>	180
37	Role of Women Entrepreneurs in Economic Development <i>Dr. Shankar Maroti Sawant</i>	186
38	The Role of Women in Indian Agriculture Sector   <i>Dr. K. V. Dhawale</i>	190
39	Role of Education in the Empowement of Women <i>Dr. Priti P Gawande</i>	194
40	Contribution of Indian Women in Asian Games <i>Mr. Sunil A. Damhare</i>	199
41 ✓	Women and Indian Politics   <i>Prof. Rahul P. Ghuge</i>	204
42	Woman as the Oppressed Lot in The God of Small Things <i>Ku. Goldie Kishor Jambhulkar</i>	208
43	Women's Empowerment and Governmental Policies in India <i>Dr. Ajay D. Jadhao</i>	213



## Women and Indian Politics

**Prof. Rahul P. Ghuge**

*Assistant Professor, Department of English, Shri.Dhabekar Kala Maha. Khadki, Akola.*

### FULL PAPER

Political participation of women can be measured in three different dimensions –their participation as a voter, their participation as an elected representatives and their participation in the actual decision making process. The first session of Indian National Congress was attended by six women delegates. Women played a crucial role in Swadeshi and Boycott movement. Women took active part in boycotting foreign goods, packeting in schools, colleges and courts, organizing processions, spinning wheel (charka). Thousands of women and girl students took active part in the Quit India movement of 1942. Women's participation in decision making process is vital to sustain democracy.

It is very difficult for a woman to make up her mind to enter politics. Once she makes up her own mind, then she has to prepare her husband, and her children, and her family. India, being the largest democratic country in the world has very low representation of women in politics. Lesser women are seen in holding key positions and decision making positions in the political arena. Men and women have always equally shared their dedication towards the development of the nation. Contribution of Rani Laxmi Bai, Savitribai Phule, Sarojini Naidu, Annie Besant, Aruna Asaf Ali, Kasturba Gandhi, Kamala Nehru, Vijaylaxmi Pandit, Sucheta Kriplani. Padmaja Naidu, Kalpana Dutta, Sarla Bhen, etc. in the Indian freedom struggle is highly noticeable. It is the need of the hour in a country like India to have equal participation of women in mainstream political activity. The nature of society has a crucial impact on the extent and effectiveness of women's political participation. Their low representation in decision making institutions signifies deep flaws in the political structure of country. Historical, social and cultural factors have restricted women from enjoying their rights of participation in political processes. Women empowerment may mean equal status to women, opportunity and freedom to develop herself.

Women's involvement in political parties is tied to the increasing demand for equal rights. Gender gap exists regarding access to education and employment. It is found that



acceptance of unequal gender norms by women are still prevailing in the society. In India, political participation of women is not impressive when compared with men. This is the case in most of the countries across the world. However, women's political participation now is quite encouraging compared to the older times. It ranked 148 out of the 193 nations, with only 11.48 per cent women in the Lower House of Parliament and 11 per cent in the Upper House. That was the highest number of women MPs elected to the Parliament since Independence. Simultaneously, Rajya Sabha witnessed 10.6 per cent women's participation. In the 16th Lok Sabha, 61 women leaders have made their way to the Parliament. This is the highest ever number of Lok Sabha seats won by women and constitutes 11.23 per cent of the total 543 Parliamentary seats. Going back to the initial days after independence, it appears that the situation had been more than grim. The first Lok Sabha had only 4.4 per cent women members. The sixth Lok Sabha in 1977 witnessed the smallest proportion of women in Parliament at mere 3.5 percent. Although the number of women MPs increased from 59 to 61 under the Modi government, it still remains far below the global average of 21.3 per cent. In a recent study conducted by the Inter-Parliamentary Union (IPU), India is placed at 111th position in the list of 189 countries having women representatives in Parliament.

It has been long since women have stepped out of their homes and have gained eminent positions and status in almost every field of society, then be it education or corporate world or Politics. Talking about India women has been involved in politics since ages. The very first name of a woman in Indian politics who became a torch leader for other women was Razia Sultan. She was the only woman to have ruled Delhi ever. The role of women in Indian politics witnessed in ancient India widened more in British India. Annie Besant though was not an Indian but became the first women president of Indian National Congress (INC) in 1915. In 1916 she launched a Home League Movement to fight for Indians and actively participated in Indian Independence Movement. Then there was Sarojini Naidu who became the first Indian woman to be the president of INC in 1925 and became the Governor of United Provinces (present Uttar Pradesh) on 15 Aug 1947.

The status of women in Indian politics was never more significant than after independence. This golden era for women in Indian politics started with the name of Mrs. Vijayalakshmi Pandit. She was an active worker in Indian Nationalist Movement and was the first Indian to be elected the president of UN General Assembly in 1953. Then came Sucheta Kriplani who became Chief Minister of UP in 1963. The most important name in the category of women politicians came in 1966 and that was Mrs. Indira Gandhi. She became the first woman Prime Minister of India in 1966 and made the world stop and notice the immense potential of women.

Today as per 73rd and 74th amendment acts, all local elected bodies reserve 1/3rd of their seats for women. The names such as Mamta Banerjee, J.Jayalalitha, Uma Bharti, Vasundhara Raje Sindhia, Sushma Swaraj, Rabdi Devi, Mayawati and last but not the least the two young MP's Agatha Sangma and Supriya Sule are the well known politicians. Mrs. Sheila Dikshit have been elected the CM of Delhi 3rd time, Mrs. Pratibha



Devi Singh Patil is holding the post of the President of the biggest democracy in the world and Mrs. Sonia Gandhi following the footsteps of her mother in law is heading INC the party ruling the nation. Though today the number of female politicians is less as compared to male politicians but they seem to be standing at more dominant and powerful positions.

Over the past two decades, the rate of participation of women in the National Parliaments worldwide has incremented from 11.8% in 1998 to 23.5 in recent times. But we still have a long way to go to ensure equitable and fair representation to women. It's not just these women, there are many other women like Ambika Soni, Supriya Sule, Jayalalitha, Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi, Mayavati who are counted as the most influential women in Indian Politics. Their political brilliance and schemes have been appreciated by many and at the same time criticized. However, their political contributions to the development of the country and its citizens cannot be left unnoticed.

### **Conclusion**

No country could be developed unless the women are politically empowered. One of the key challenges faced by women is lack of education which hinders their political involvement. We recommend bridging this gap by providing quality education to women in the country. Awareness about their rights and privileges as mentioned in the Constitution can only be ensured once women are appropriately educated. The issue of gender-based violence and provision of safety and security of women should also be addressed on a priority basis to promote gender equality in the social and political arenas. Although the Government of India has initiated the National Mission of Empowerment of Women in 2014 with the broad objective of gender empowerment, the progress of this project is not up to the mark. It is thus imperative to strengthen its functioning and implementation. To secure women's rightful place in society and to enable them to decide their own destiny and for the growth of genuine and sustainable democracy, women's participation in politics is essential. This will not only uplift their personality but will open the way for their social and economic empowerment. Their participation in public life will solve many problems of society.

### **Reference:**

1. Bjorkert, S. Thapar. Women in the Indian National Movement: Unseen Faces and Unheard Voices, 1930-42. New Delhi: SAGE, 2006.
2. Chadha Anuradha (2014) " Political Participation of Women : A case study in India" OIDA International Journal Sustainable Development, Vol 07, No 2, pp 91-108.  
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2441693](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2441693)
3. Ganesamurthy, V. S. Empowerment of women in India: social, economic and



---

political. New Delhi: New Century Publications, 2008.

4.Kuldeep Fadia, women's empowerment through political participation in India, [www.iipa.org.in](http://www.iipa.org.in)

5.Mohini Giri, V. Emancipation and Empowerment of Women. Gyan Books, 1998.

6.Pamela Parton (June 2017), women's political empowerment a global index, 1900-2012, [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)



PROF. RAHUL  
P.GHUGE

Asst. Professor,  
Department of English,  
Shri.Dhabekar kala  
Mahavidyalaya, Khadki,  
Akola.

One Day International Multi-Disciplinary Conference  
**RESEARCH, INNOVATION, CHALLENGES & OPPORTUNITIES  
IN HIGHER EDUCATION**

On 13<sup>th</sup> January, 2023 @  
Smt Salunkabai Raut Arts & Commerce College, Wanoja,  
In collaboration with  
Saraswati Kala Mahavidyalaya, Dahihanda  
Arts And Science College, Kurha,  
Physical Education Foundation of India, New Delhi.

**USE OF ICT IN HIGHER EDUCATION**

**ABSTRACT**

The abbreviation ICT stands for Information and Communication Technology. It is defined as a diverse set of technological tools and resources used to communicate, create, disseminate, store, and manage information. The purpose of this paper is to discuss the uses of Information Communication Technology (ICT) use in higher education. It highlights the impacts and benefits of ICT in higher education. This paper also highlights various impacts of ICT on contemporary higher education.

**Keywords:** Higher Education, ICT, teaching and learning process, information, strategies, knowledge.

**Introduction: What is ICT?**

ICT is an acronym that stands for "Information Communication Technologies". Information and communication technologies are an umbrella term that includes all technologies for the manipulation and communication of information. ICT considers all the uses of digital technology that already exists to help individuals, business and organization. ICTs stand for information and communication technologies and are defined, for the purposes of this primer, as a "diverse set of technological tools and resources used to communicate, and to create, disseminate, store and manage information. The role of Information & Communication Technology (ICT) in Higher Education is undisputed globally. ICT have potentially powerful tool for extending educational opportunities. ICT have the potential for increasing access to and improving the relevance and quality of Education. It is related not only to the development of the individual and the acquisition of knowledge but also to character formation. The growing use of ICT has changed strategies employed by both teachers and students in teaching learning processes.

ICT plays a vital role in imparting education in modern scenario. The way of imparting education in modern era has changes due to the use of ICT. ICT has opened new challenges for quality education. It has changed many aspects of the lives. Mere learning of ICT skills is not enough, but using ICT to improve the teaching and learning paradigm improves the concept and application of teaching and learning ICTs are making dynamic changes in the society. They are influencing

every aspect of human life. Application of ICT tools in teaching and learning process has changed the total scenario of teaching and learning process.

ICTs greatly facilitate the acquisition and absorption of knowledge, offering developing countries unprecedented opportunities to enhance educational systems, improve policy formulation and execution, and widen the range of opportunities for business and the poor. One of the greatest hardships endured by the poor, and by many others, who live in the poorest countries, in their sense of isolation, and ICTs can open access to knowledge in ways unimaginable not long ago.

The ICT has been developing very rapidly nowadays. Therefore, in order to balance it, the whole educational system should be reformed and it should be integrated into educational activities. Traditional learning was hard, introduction of ICT has change the traditional concept. It has the potential to transform the nature of education. ICT and their role have a tremendous potentiality of serving its cause and helping the persons connected with the process and product in a number of ways. ICT may help student to satisfy their urges of curiosity, inventories and construction.

ICT helps enhance the quality of education by facilitating new forms of interaction between students, teacher, education employees and the community. ICT act as and provides students and teachers with new tools that enable improved learning and teaching and adds to skills formation. ICT improve quality and structure of the syllabi by enforcing competency and performance based approach towards it. Access to the learning programme

any time convenient to the learner, learner can be at any place to log on. The teacher gets sufficient help from ICT, in their task of teaching.

**Uses of ICT in Teaching :-** ICTs are a potentially powerful tool for extending educational opportunities, both formal and non-formal, to previously underserved constituencies—scattered and rural populations, groups traditionally excluded from education due to cultural or social reasons such as ethnic minorities, girls and women, persons with disabilities, and the elderly, as well as all others who for reasons of cost or because of time constraints are unable to enroll on campus.

**Anytime, anywhere:** One defining feature of ICTs is their ability to transcend time and space. ICTs make possible asynchronous learning, or learning characterized by a time lag between the delivery of instruction and its reception by learners. Online course materials, for example, may be accessed 24 hours a day, 7 days a week. ICT-based educational delivery (e.g., educational programming broadcast over radio or television) also dispenses with the need for all learners and the instructor to be in one physical location. Additionally, certain types of ICTs, such as teleconferencing technologies, enable instruction to be received simultaneously by multiple, geographically dispersed learners (i.e., synchronous learning).

Teachers and learners no longer have to rely solely on printed books and other materials in physical media housed in libraries (and available in limited quantities) for their educational needs. With the Internet and the World Wide Web, a wealth of learning materials in almost every subject and in a variety of media can now be accessed from anywhere at anytime of the day and by an unlimited number of people. This is particularly significant for many schools in developing countries, and even some in developed countries, that have limited and outdated library resources. ICTs also facilitate access to resource persons—mentors, experts, researchers, professionals, business leaders, and peers—all over the world

Teachers are an important element in education system. We can't imagine better educational environment without a better teacher. In earlier times the teacher was the central point of education, but now the role of teachers have changed a lot. He is considered as a guide and friend of students. He helps in learning, does not provides knowledge. ICT can be useful for a teacher in the following ways. (i) It can be helpful in the professional development of the teachers. A teacher can learn various skills with the help of information and communication technologies. He can do various certification programmes run by the famous international educational institutions like Oxford University, Cambridge University, British Council etc. These programmes help in enhancing his

capacity to teach and to make his subject content easy, economic and more understandable.

(ii) We know that research is a difficult process and collection of data is the most difficult stage of a research. With the use of Information and Communication Technologies online data collection and surveys have become very easy. A teacher can get responses easily. ICT also helps in the analysis of data, study of related literature and in the publication of his research work.

(iii) A teacher can increase his domain of Knowledge with the help of e-journals, e-magazines and e-library that can be achieved only through the use of information and communication technologies. He can also participate in discussions and conferences with the experts of his subject to improve his knowledge and skills through audio and video conferencing.

(iv) With the help of ICT a teacher can learn modern methods of teaching. He can work with the students on various project and assignments. It also helps in providing teaching contents, homeworks etc. with the use of Power Point presentations he can make the students understand complex processes and theories. (v) ICT makes him able to guide students about the materials available on internet, e-books, e-journals, e-magazines and social sites like linked-in which are helpful in better learning.

(vi) ICT also helps him framing curriculum. He can study curriculums of different countries to study their merits and demerits, challenges as well as sociological and psychological issues. These all helps him in framing a curriculum that leads to achieve national goals.

(vii) Evaluation is a important part of educational systems. It informs about the strengths and weaknesses of the system. ICT also helps a teacher in better evaluation. With the help of ICT he may be familiar with the new tools and techniques for evaluation. He can evaluate each and every aspect of the development of students easily with the tools and techniques. ICT in Learning Earlier it was considered that learning can be achieved through teachers and all the teaching learning activities go round the teacher but the scenario has changed. Now learning can be achieved in the absence of teachers and without classrooms. It has become possible only due to information and communication technologies.

**Conclusion:** The role of ICTs in the education is recurring and unavoidable. Rapid changes in the technologies are indicating that the role of ICT in future will grow tremendously in the higher education. ICT also focuses modification of the role of teachers. In addition to classroom teaching, they will have other skills and responsibilities. Teachers will act as virtual guides for students who use electronic media. The use of ICT will enhance the learning experiences of students. Also it helps them to think independently and communicate

creatively. It also helps students for building successful careers and lives, in an increasingly technological world.

Teachers and colleges face a range of challenges, including infrastructural issues such as lack of power, telephone and Internet access, which hinder the effective use of ICT in teaching and learning. Information and Communication Technologies (ICTs) is increasingly becoming indispensable part of the higher education system. ICTs greatly facilitate the acquisition and absorption of knowledge, offering developing countries unprecedented opportunities to enhance educational systems, improve policy formulation and execution, and widen the range of opportunities for business and the poor. ICT is one of the source of rural development as it helps in reaching the education to rural areas and hence develop it. Introduction of New policies and technology in world has raised the Level of education in India. The raising standard of education system helps deeply in development of Human and directly the Nation.

#### References:

1. Anjaneleyu A.N.K. Prasanna. Facets for Quality in Higher Education, Delhi : MacMillan Publishers India Pvt. Ltd 2011.
2. Bikas C. Sanyal, "New functions of higher education and ICT to achieve education for all", International

Institute for Educational Planning, UNESCO, 12 September 2001.

3. Das, B.C. Educational Technology. New Delhi. Kalyani Publishers 2002.
4. Kumari Kumkum 2011. Facets for Quality in Higher Education. Delhi : MacMillan Publishers India Pvt. Ltd.
5. Joanne Capper, "E-learning growth and promise for the developing world", In: "TechKnowLogia", May/June, 2001.
6. Shukla S. Satish Prakash, Information and Communication Technology in Teacher Education., Agra : Agrawal Publication, 2012.
7. Washington DC, "Report of the Web-Based Education Commission", December 2000.
8. <http://www.imfundo.org/Advisory/basicedu.htm> [6] Ron Oliver, Edith Cowan. University. Perth, Western Australia.



12

**B.Aadhar'** International Peer-Reviewed Indexed Research Journal



Impact Factor - (SJIF) - 8.575, Issue NO, 398 -B

ISSN :  
2278-9308  
March,  
2023

Impact Factor - (SJIF) -8.632

ISSN - 2278-9308

# B.Aadhar

Single Blind Peer-Reviewed & Refereed Indexed  
Multidisciplinary International Research Journal

**March- 2023**

ISSUE No - 398 -B

## A Journey of Indian women

**Prof. Virag.S.Gawande**

Chief Editor

Director

Aadhar Social Research &, Development Training Institute, Amravati.

**Dr.V.R.Kodape**

Editor,

Principal,

Shri Kisanlal Nathmal Goenka Arts & Com,  
College Karanja (LAD) Dist. Washim

**Aadhar International Publication**

For Details Visit To : [www.aadharsocial.com](http://www.aadharsocial.com)

© All rights reserved with the authors & publisher

67	ग्रामिण महिलांच्या मुलभूत समस्या आणि उपाय	कु.पायल केशवराव पाटील	277
68	ग्रामीण स्त्रीयांचे आरोग्य, समस्या व उपाय	प्रा. प्रणिता थेर	280
69	भूमिहिन आंदोलन चळवळ: आणि नांदेड जिल्हयातील दलित स्त्रीयांचे योगदान	छाया भिमराव उमरे	284
70 ✓	आर्थिक विकासात महिलांची भूमिका	प्रा. डॉ. नीता नंदलाल तिवारी	287
71	संस्कृती संवर्धनात महीलांचे योगदान व महीला सक्षमीकरण	प्रा. प्राची भांबुरकर	291
72	हिराबाई बडोदेकर यांचे नाट्य संगीतामधील योगदान	प्रा. विद्या प्र. गावंडे	294
73	भारतीय विकासाच्या वाटचालीत आदिवासी महिलांचे योगदान	डॉ. वैजनाथ अनमुलवाड	297
74	भारतीय चित्रपट आणि स्त्री	श्री. उज्वल राहुल शेगावकर	300
75	संगीत स्वरयोगिनी : "पद्मविभूषण" डॉ. प्रभा अत्रेजी	प्रा. कु.प्रिती बी. इंगळे (वाकपांजर)	303
76	स्वातंत्र्यपूर्व काळातील महाराष्ट्रीयन महिलांचे साहित्य रचनेतील योगदान	प्रा.भाऊराव रामेश्वर तनपुरे	307
77	मराठीतील दलित स्त्रियांची आत्मकथने : स्वरूप व वैशिष्ट्ये	संजय नामदेवराव आठवले	311
78	महिलांच्या सेवाभाव ,नेतृत्व आणि शौर्यगाथा यामध्ये सावित्रीबाई फुले यांचे योगदान	प्रा रेखा दिगांबर आढाव	318
79 ✓	पंचायतराज व्यवस्थेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी	प्रा. डॉ. संतोष एस. मिसाळ	325
80	भारतीय स्त्री आणि कौटुंबिक स्वास्थ्य एक अभ्यास	प्रा. डॉ. ठकसेन दादारावजी राजगुरे	329
81	गर्भसंस्कारने गर्भवती महिलांचे स्वास्थ्य संवर्धन करुन बालकाच्या वाढ व विकासात योगदान देणे	प्रा. कु. जयश्री त्र्यंबकराव कात्रे	334
82	भारतीय शेती विकासात महिलांचे योगदान	डॉ. रमाकांत गजभिये	336
83	स्त्रीया आणि मानवाधीार	डॉ. प्रसन्नजीत रा. तवई	339
84	लोककला विश्वातील लोकप्रिय महिला कलावंत लावणी सम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर	प्रा. जगन्नाथ इंगोले	342
85	विज्ञान के क्षेत्र मै महिलाओ का योगदान	डॉ. अंजुम नहिद रउफ खान	344
86	महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	प्रा. डॉ. जे. जे. जाधव	346

## आर्थिक विकासात महिलांची भूमिका

प्रा. डॉ. नीता नंदलाल तिवारी

अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख श्री धावेकर कला महाविद्यालय, खडकी, अकोला  
मोबाईल नं. ९९२३०३६१२६, g-mail- nectatiwari201456@gmail.com

### भूमिका

प्राचीन काळापासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत स्त्रिया या ना त्या मार्गाने योगदान देत आहेत. स्त्रियांच्या आर्थिक आणि उत्पादक कार्याचा निर्धारण मानवी सभ्यतेच्या सुरुवातीच्या काळापासून चालत आला आहे, कारण 'आखेट युगात' जरी स्त्रिया शिकारीला जात नसल्या तरी त्या कुटुंबात राहून धान्य साफ करणे, चाळणे, दळणे अशी विविध कामे करत. जेव्हा पशुपालन युग सुरू झाले तेव्हा त्यातही महिलांना अनेक घरगुती कामे करावी लागत होती, ज्यामध्ये जनावरांची काळजी घेणे, दुधापासून अनेक पदार्थ बनवणे, जनावरांची काळजी घेणे आदी कामे मुख्य होती. यानंतर जेव्हा शेतीचे युग आले, तेव्हा स्त्रियांना घरातील विविध कामे करावी लागली, त्यापैकी कापड विणणे, भांडी बनवणे, टोपल्या बनवणे ही प्रमुख कामे होती.

औद्योगिक क्रांतीपूर्वी स्त्रिया घरात राहून पुरुषांना विविध प्रकारे मदत करत असत. जसे-

### 1. औद्योगिक क्रांतीचा प्रभाव

देशात औद्योगिक क्रांती झाली तेव्हा त्याचा परिणाम महिलांच्या आर्थिक स्थितीवरही झाला. याचा परिणाम असा झाला की, कौटुंबिक बंधने सोडून स्त्रिया घराबाहेरही काम करू लागल्या, कारण औद्योगिक जगात महिलांना आता काम करण्याच्या अधिक संधी मिळाल्या. याचे मुख्य कारण म्हणजे मालकांकडून महिलांना कमी दरात मजूर मिळत असे. ज्या वेळी एकोणिसावे शतक संपुष्टात आले, त्या वेळी संपूर्ण महिला वर्गाने कामगार वर्गाच्या रूपाने आपले स्थान घेतले होते. त्यावेळेस विविध देशांत काम करणाऱ्या महिलांची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे होती - अमेरिकेत ३३%, जर्मनमध्ये ३६%, पोलंडमध्ये ४४.८%, रशियात ४५% आणि भारतात २७%, ज्या आजही विविध व्यवसायांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत. .

### 2. भारतीय महिलांची व्यावसायिक स्थिती

भारतात स्त्रियांच्या घरगुती कामाचा निर्धारण प्राचीन काळी होत असला, तरी एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या टप्प्यात या कामांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय वाढला होता, त्याचा परिणाम प्रत्येक वर्गातील स्त्रियांवर स्पष्टपणे दिसून आला. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे-

(i) खालच्या वर्गातील महिलांची प्रमुख कामे:- औद्योगिक क्रांती संपली तेव्हा महागाई शिगेला पोहोचली होती. या महागाईमुळे समाजातील खालच्या वर्गातील महिलांना कुटुंब सोडून विविध व्यावसायिक कामे करावी लागली. या वर्गातील स्त्रियांचे मुख्य काम शेत नांगरणे, दगडाच्या खाणीतील चहाची पाने काढणे, चहाच्या बागा इत्यादी होते.

(ii) मध्यमवर्गीय स्त्रियांची मुख्य कार्ये :- भारतीय व्यवसायात मध्यमवर्गीय स्त्रियांचा प्रवेश बऱ्याच काळानंतर झाला. या संदर्भात सुप्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ श्री.पी.सेन गुप्ता यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिले आहे की, "स्त्रियांच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी आणि महिलांना आर्थिकदृष्ट्या त्यांच्या पायावर उभे करण्यासाठी, सर्वप्रथम शिक्षक व्यवसायाचे दरवाजे खुले झाले. " महिलांचे दुसरे प्रमुख कार्य परिचारिकाचे होते. म्हणूनच ब्रिटीश सरकारने 1875-76 मध्ये स्त्रियांना मुख्यतः 'परिचारिका' म्हणून प्रशिक्षण दिले. देशाच्या आर्थिक विकासाबरोबरच महिलांचे व्यावसायिक उपक्रमही वाढत गेले.

जसजशी शैक्षणिक प्रगती होत गेली, तसतशी सरकारी प्रशिक्षण व्यवसायांमध्ये महिलांचा सहभाग उत्तरोत्तर वाढू लागला. 1920 मध्ये महिलांनी व्यवसाय क्षेत्रात निश्चित स्थान निर्माण केले होते. स्वतंत्र भारतातही मध्यमवर्गीय महिलांच्या कामाच्या अधिकाराला मान्यता देण्यात आली आणि त्यांच्या विविध समस्या लक्षात घेऊन सरकारकडून विविध कायदे करण्यात आले. श्रीमती पी. सेन गुप्ता यांनी त्यांच्या 'बुमन वर्कर्स ऑफ इंडिया' (इंडियाज वर्किंग बुमन) मध्ये मध्यमवर्गीय महिलांनी केलेल्या मुख्य कामाचा तपशील खालीलप्रमाणे मांडला आहे-

1. शैक्षणिक कार्य:- मध्यमवर्गीय महिलांचे पहिले आणि प्रमुख काम म्हणजे अध्यापनाचे काम. त्यामुळेच आज महिला शिक्षिका, प्राध्यापक, निरीक्षक किंवा मुख्याध्यापिका म्हणून काम करत आहेत.

2. आरोग्य कार्य:- मध्यमवर्गीय महिलांचे दुसरे प्रमुख काम आरोग्य कार्य आहे. त्यामुळेच आज आरोग्य विभागात दाई, परिचर आरोग्य निरीक्षक, जनरल डॉक्टर किंवा डॉक्टर या पदांवर बहुतांश महिला कार्यरत आहेत.



3. कारखान्याशी संबंधित काम: आज, विविध प्रकारच्या कारखान्यांमध्ये महिलांना विविध कामांसाठी काम दिले जाते, ज्यामध्ये कपडे, तंबाखू, पिठाच्या गिरण्या, तेल आणि काजू इत्यादी प्रमुख आहेत.

4. खाणीशी संबंधित काम:- कोळसा, पोलाद, दगड, अन्नक, मॅंगनीज, पोलाद इत्यादी खाणींमध्ये सर्वाधिक महिला आहेत.

5. बागकाम :- आज महिला चहा, कॉफी आणि रबर मळ्यातही पुरेशा प्रमाणात काम करत आहेत.

6. कलेशी संबंधित काम:- प्राचीन काळी नृत्य करणाऱ्या स्त्रियांकडे टीकेच्या नजरेने पाहिले जायचे कारण हे काम केवळ बाहेरच्या मुली किंवा वेश्या यांच्यासाठीच मानले जात होते, पण आजकाल तसे नाही. आज समाजात नृत्य, संगीत आणि कलेला खूप महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रात महिलांचा प्रवेश आदरणीय झाला आहे.

7. विधिक क्षेत्रात:- आज महिलांनी विधिक क्षेत्रातही आपला हक्क प्रस्थापित केला आहे, कारण आजकाल महिला वकील, बॅरिस्टर किंवा न्यायाधीश म्हणून काम करत आहेत, विधिक क्षेत्राव्यतिरिक्त, महिला राजनैतिक क्षेत्रातही कार्यरत आहेत.

8. ग्रामीण भागाशी संबंधित काम:- आधुनिक काळात, सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सामुदायिक योजनेतर्गत, ग्रामसेवकांच्या पदावर महिलांची नियुक्ती केली जाते, ज्यांचे कार्यक्षेत्र केवळ ग्रामीण भाग आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणूनही महिलांची नियुक्ती केली जाते.

9. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे:- आज महिलांकडून विविध प्रकारची बांधकामे स्वस्त दरात केली जातात, ज्यामध्ये नवीन रस्ते बांधणे, इमारती बांधणे, नदी योजनांमध्ये बंधारे बांधणे इत्यादी कामे महत्त्वाची आहेत.

10. लहान व्यवसाय:- स्त्रिया घरी राहून काही व्यवसाय करतात, कारण त्यांना मशीन आणि विजेची गरज नसते. मासेमारी, विडी बनवणे, रंगरंगोटी, शिवण-भरतकाम, विणकाम इ., छपाईचे काम, खेळणी बनवणे इत्यादी कामे या कामांमध्ये प्रमुख आहेत. काही महिला घरात राहून पापड आणि लोणची बनवतात. घरच्या घरी कागदी पिशव्या तयार करणे, पुढ्याचे खोके तयार करणे, चट्या व टोपल्या बनवणे आदी कामांचाही समावेश आहे.

11. काही महिला रेल्वे, गोदी आणि इतर विभागांमध्ये होस्टेस म्हणूनही काम करत आहेत.

12. इतर कामे:- वरील कामांव्यतिरिक्त महिला दुकाने, कार्यालये आणि वितरण केंद्रातही काम करत आहेत. महिला सहाय्यक, टायपिस्ट, टेलिफोन ऑपरेटर इत्यादी म्हणूनही काम करतात. आज अनेक महिला केवळ शिवणकामाच्या दुकानातच काम करत नाहीत, तर बँका इत्यादींकडून कर्ज घेऊन स्वतः त्यांची केंद्रे चालवत आहेत.

वरील वर्णनावरून हे स्पष्ट होते की आज भारतीय अर्थव्यवस्थेत महिलांचे योगदान पुरुषांपेक्षा कमी नाही. ज्या स्त्रीला काही काळापर्यंत दुर्बल, खालच्या दर्जाची स्त्री समजली जात होती, आज तीच स्त्री पुरुषांशी संबंधित क्षेत्रात त्यांच्या पुढे गेली आहे.

पुढे जाण्याचा मार्ग:

सध्याच्या काळात, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महिलांच्या वाढत्या सहभागासह, कामाच्या ठिकाणी प्रचलित भेदभाव आणि महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित आव्हानांवर मात करण्यासाठी बहुआयामी प्रयत्नांचा अवलंब केला पाहिजे.

असंगठित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांसाठी लक्षित योजनांसह (प्रशिक्षण, सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा इ.) अर्थव्यवस्थेच्या सर्व स्तरांवर महिलांचा सहभाग आणि त्यांच्या हितांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारला विशेष लक्ष द्यावे लागेल.

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, शौचालय सुविधा इत्यादी व्यवस्था मजबूत करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

महिलांना उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणात सहभागी होण्यास मदत करण्यासह ग्रामीण भागातील उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे लागेल. यासोबतच धोरण ठरविणाऱ्या सर्वोच्च व्यवस्थेत आणि महत्त्वाच्या संसाधनांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेत महिलांचा मोठा वाटा आहे. कृषी कार्य आणि उच्च बचत दर निर्मितीसह विविध आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये महिला महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भारताचा विकास दर अलीकडच्या काळापर्यंत उच्च होता आणि हे बचत आणि भांडवल निर्मितीचा उच्च दर यामुळे आहे. भारतातील बचत दर जीडीपीच्या 33 टक्के आहे, त्यापैकी 70 टक्के देशांतर्गत बचत, 20 टक्के खाजगी क्षेत्रातील बचत आणि 10 टक्के सार्वजनिक क्षेत्रातील बचत आहे. बचत, उपभोग-प्रवृत्ती आणि पुनर्वापर-प्रवृत्ती या बाबतीत भारताची अर्थव्यवस्था महिला केंद्रित आहे यात शंका नाही. कृषी उत्पादनात महिलांच्या सरासरी सहभागाचा अंदाज एकूण श्रमाच्या ५५ टक्के ते ६६ टक्के आहे. दुग्धउत्पादनात महिलांचा सहभाग एकूण रोजगाराच्या ९४ टक्के आहे. वन-आधारित लघुउद्योगांमध्ये कार्यरत एकूण कामगारांपैकी 54 टक्के महिला आहेत.

ग्रामीण महिलांना श्रमाच्या बाबतीत दुहेरी भूमिका पार पाडावी लागते. एकीकडे कुटुंबाच्या अन्न आणि इतर गरजा भागवणे ही त्यांची भूमिका असते आणि दुसरीकडे गरज पडेल तेव्हा त्यांना शेतीच्या कामात सहकार्य करावे



लागते. श्रमिक क्षेत्रात शहरांमध्ये राहणाऱ्या महिलांची भूमिका वेगळी आहे. श्रमिक महिला आणि घरगुती महिला अशा दोन श्रेणी आहेत.

जगातील तिसरे अर्धे म्हणजेच तीन अर्धे स्त्रिया आगामी काळात कोणती भूमिका निभावतील आणि जगातील सरकारी आणि भांडवलशाही संस्था त्यांना संरक्षण आणि प्रोत्साहन देतील की त्यांच्या मार्गात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करतील, हा प्रश्न समोर येतो. अलीकडेच, आंतरराष्ट्रीय सल्लागार आणि व्यवस्थापन संस्था 'वूड अँड कंपनी'ने 'थर्ड बिलियन इंडेक्स' नावाच्या संशोधन अहवालात असा निष्कर्ष काढला आहे की, पुढील दशकात एक अर्धे महिला जगातील एकूण कर्मचार्यांमध्ये सामील होतील, परंतु आर्थिक सक्षमीकरण आणि व्यावसायिक यश देखील अनेक असेल. त्यांच्यासमोर आव्हाने. थर्ड बिलियन हा शब्द विकसनशील आणि औद्योगिक देशांतील महिलांचे प्रतिनिधित्व करतो ज्या 2020 मध्ये प्रथमच मुख्य प्रवाहातील अर्थव्यवस्थेत सामील होतील आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत ग्राहक, उत्पादक, कामगार आणि उद्योजक म्हणून स्थान घेतील. या महिलांचा किमान भारत आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम होण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते कारण या देशांमध्ये त्यांची लोकसंख्या एक अर्धाहून अधिक आहे.

अर्थव्यवस्थेतील माहिती तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक दृश्यमान वापरकर्ते म्हणून महिलांची भूमिका दिवसेंदिवस विस्तारत आहे. एअरलाइन्स हे एक मोठे सेवा क्षेत्र आहे ज्यामध्ये महिलांना चांगले व्यक्तिमत्व, संधारण कौशल्य आणि संगणक योग्यता यासह प्राधान्य दिले जाते. बँकिंग तंत्रज्ञानाद्वारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, वेस्टर्न मनी ट्रान्सफर, टेलर सिस्टीम आणि ई-बँकिंग सिस्टीम वेगाने विकसित झाल्या आहेत. स्त्रिया ही कामे कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन्सद्वारे शक्य करत आहेत. त्याचप्रमाणे आयटीच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात महिलांसाठी संधी वाढल्या आहेत. मोबाईल फोन, इंटरनेट आदी सुविधांसोबतच इतर सेवांमध्येही महिलांची मागणी प्रचंड वाढत आहे. वैद्यकीय प्रतिलेखन सेवा क्षेत्र गेल्या काही वर्षांत उदयास आले आहे. हे प्रामुख्याने महिलांचे उपचार आणि संबंधित वैद्यकीय परिस्थिती स्पष्ट करते. ई-पुस्तके, ई-नियतकालिके, ई-प्रकाशन आणि वेब-डिझाइनमधील नवीन करिअर संध्यांच्या परिस्थितीत लोकप्रिय आहेत जेथे महिलांची संख्या आणि भूमिका वेगाने वाढली आहे. थर्ड बिलियन इंडेक्स अहवालात असे म्हटले आहे की जर महिलांचा रोजगार दर पुरुषांच्या रोजगार दराच्या बरोबरीने असेल तर भारताचा जीडीपी 27 टक्क्यांनी वाढू शकतो. हे ज्ञात आहे की युनायटेड अरब अमिराती आणि इजिप्त सारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्था महिला आणि पुरुषांच्या रोजगार दरात समानता आणून अनुक्रमे 42 आणि 34 टक्के GDP वाढवू शकतात. कमी-अधिक प्रमाणात विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थेबाबतही असेच घडू शकते. महिलांचा रोजगार दर पुरुषांच्या रोजगार दराच्या बरोबरीने आणल्यास अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 5 टक्के आणि जपानची अर्थव्यवस्था 9 टक्के दराने वाढू शकते. अर्थव्यवस्थेच्या दाराबाहेर उभ्या असलेल्या भारतीय महिलांच्या स्थितीवर भाष्य करताना अहवालात असे म्हटले आहे की "बहुतेक भारतीय महिलांना पुरेशी आरोग्यसेवा, सामाजिक सेवा, वाहतूक आणि दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध नाही. जर त्याला आपल्या महिला लोकसंख्येला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत बनवायचे असेल तर त्याने या मूलभूत समस्या सोडवायला ह्यात. भारतातील शिक्षणाच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर सुधारणा करण्यावर बऱ्यापैकी भर देण्यात आला असला तरी, भारतातील उत्पादन क्षेत्र जपाट्याने वाढत आहे आणि त्यासाठी व्यावसायिकदृष्ट्या कुशल लोकांची गरज आहे, तर देशाची शिक्षण व्यवस्था ही मागणी पूर्ण करण्यास सक्षम नाही.

महिलांच्या भूमिका मजबूत करण्यासाठी खालील सूचना केल्या जाऊ शकतात, ज्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे:

1. सकारात्मक आर्थिक आणि सामाजिक धोरणांद्वारे महिलांच्या विकासासाठी एक वातावरण तयार करणे ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या पूर्ण क्षमतेची जाणीव होईल.
2. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि नागरी क्षेत्रात पुरुषांबरोबरच महिलांना विधिक आणि वास्तविक मानवी हक्कांचा उपभोग घेण्यासाठी समान संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे.
3. देशाच्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक जीवनात सहकार्य आणि निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा समान सहभाग असावा.
4. आरोग्य, सर्व स्तरांवर दर्जेदार शिक्षण, करिअर आणि व्यावसायिक मार्गदर्शन आणि नोकरीमध्ये समान मोबदला, व्यावसायिक आरोग्याचे संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि सार्वजनिक कार्यालयात समान प्रवेश इ.
5. महिलांवरील सर्व प्रकारचे भेदभाव नष्ट करण्याच्या उद्देशाने विधिक व्यवस्था मजबूत करण्याची गरज.
6. स्त्री-पुरुषांच्या सक्रिय सहभागाने सामाजिक वर्तन आणि सामुदायिक पद्धतींमध्ये बदल.
7. विकास प्रक्रियेत लैंगिक दृष्टीकोन मुख्य प्रवाहात आणणे.
8. महिला आणि मुलींवरील भेदभाव आणि सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराचे उच्चाटन.
9. विशेषतः महिला संघटनांसह भागीदारी तयार करा आणि मजबूत करा.

निष्कर्ष



महिला सक्षमीकरणाची गरज संपूर्ण समाजाला जाणवू लागली असेल, पण त्यासाठी प्रभावी व्यवस्था निर्माण झालेली नाही हे कटू सत्य आहे. बालसंगोपन असो की खाजगी व्यवसायासाठी कर्ज व परवाने मिळणे, सर्वत्र अडथळे आहेत. महिलांच्या सुरक्षेबाबतचे कायदे अनिच्छेने पाळले जात आहेत. घराबाहेर पडणाऱ्या महिलांसमोरील अराजक घटकांपासून दूर राहणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. प्रभावी अंमलबजावणीअभावी चांगले कायदेही निरुपयोगी ठरत आहेत. विनयभंग आणि अॅसिड हल्ल्यापासून ते सामूहिक बलात्कारापर्यंतच्या प्रकरणांमध्ये पोलिस एफआयआर नोंदवण्याचे टाळतात.

अर्थव्यवस्थेच्या यशासाठी महिला सक्षमीकरण ही मूलभूत अट आहे, हे प्रत्येकाने समजून घेतले पाहिजे. हे घडताना पहायचे असेल, तर महिलांची सुरक्षितता प्रत्येक वेळी आणि सर्वत्र सुनिश्चित केली पाहिजे. त्यासाठी कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत सुलभीकरणापासून ते पोलीस आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारणे आवश्यक आहे. तरच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होऊ शकेल.

संदर्भ-

- 1) <https://timesofindia.indiatimes.com/women-and-economy->, Women and economy: The Indian perspective, April 22, 2017, LALITA NIJHAWAN
- 2) <https://www.shethepeople/womens-contribution-to-indian-economy> GUNJAN NAGPAL, Updated On April 18, 2022
- 3) <https://www.drishtiiias.com/hindi> भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी 17 Nov 2020
- 4) <https://www.civilhindipedia.com/> role-of-women-in-the-economy अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका Posted on March 20th, 2020
- 5) <https://www.samareducation.com/2022/04/role-of-women-in-economic-development>



RESEARCH NEBULA  
AN INDEXED, REFERRED &  
PEER REVIEWED JOURNAL



ISSN 2277-8071

13

# RESEARCH NEBULA

*An International Refereed, Peer Reviewed & Indexed Quarterly Journal in  
Arts, Commerce, Education & Social Sciences*

DOI PREFIX 10.22183

JOURNAL DOI 10.22183/RN

IMPACT FACTOR 7.399

## **TWO - DAY 46<sup>th</sup> ANNUAL CONFERENCE OF VIDHARBHA ARTHASHASTRA PARISHAD**

4<sup>th</sup> & 5<sup>th</sup> February, 2023

*Organized by*

### **LOKMANYA TILAK MAHAVIDYALAYA, WANI DIST. YAWATMAL**

Guest Editor

**DR. PRASAD KHANZODE**

Principal

Lokmanya Tilak Mahavidyalaya,  
Wani, Dist. Yavatmal

Executive Editor

**DR. KARMSING RAJPUT**

Head, Dept. of Economics

Lokmanya Tilak Mahavidyalaya,  
Wani, Dist. Yavatmal

Chief Editor

**DR. G. P. KHANDARE**

Y.C. Arts and Science Mahavidyalaya,  
Matgrulpir, Dist. Washim

Special Issue Published on 4<sup>th</sup> February, 2023  
[www.ycjournal.net](http://www.ycjournal.net)



34.	अभिषेक संजय पद्मावार रा.तू.म.नागपूर विद्यापीठ,नागपूर, डॉ.करमसिंग रा.राजपूत अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, लोकमान्य टिळक महाविद्यालय, वणी जि.यवतमाळ	कोविड-19 चे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम-एक दृष्टीक्षेप	196
35.	प्रा.डॉ.दीपक शृंगारे अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, आदर्श महाविद्यालय, धामणगाव रेल्वे, प्रा.विशाल मोकाशे अर्थशास्त्र विभाग, आदर्श महाविद्यालय, धामणगाव रेल्वे	कोविड-19 चे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम	200
36.	प्रा.दिपाली अतुल पडोळे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय अमरावती.	कोविड -19 साथीच्या रोगाचे भारतीय शेतीवरील परिणाम	205
37.	प्रा. डॉ. नीता नंदलाल तिवारी अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, श्री धाबेकर कला महाविद्यालय,खडकी, अकोला	कोविड-19 महामारीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम	208
38.	प्रा.डॉ.व्ही.जी.जायभाये सहाय्यक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग, विद्या सागर कला महाविद्यालय खैरी (बिजेवाडा), रामटेक.	कोविड १९ चे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरिल परिणाम	211
39.	प्राचार्य, डॉ. संजय धनवटे नारायणराव काळे स्मृती मॉडेल कॉलेज कारंजा (घाडगे), जिल्हा - वर्धा डॉ. महेंद्र पांडुरंगजी गावंडे सहयोगी प्राध्यापक, नारायणराव काळे स्मृती मॉडेल कॉलेज, कारंजा (घाडगे), जिल्हा - वर्धा	कोविड-19 चा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम	214
40.	डॉ. ममता आर साहू अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख स्व.वसंतराव कोल्हटकर कला महाविद्यालय, रोहणा , ता. आर्वी जि.वर्धा	कोविड - १९ चे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरिल परिणाम	220
41.	डॉ. सुनिल शिंदे अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख भिवापूर महाविद्यालय, भिवापूर जि. नागपूर (म.रा.)	कोविड-19 चा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रावरील परिणाम: एक दृष्टीक्षेप	223
42.	प्रा. मिल्हीद ढाले सहायक प्राध्यापक, पि.प्र.म. विज्ञान व गिलाणी कला वाणिज्य महाविद्यालय घाटंजी जि.यवतमाळ	कोविड 19 चे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम	227
43.	डॉ. गजानन सोमकुवर सहयोगी प्राध्यापक बॅरिस्टर शेषराव वानखेड कला व वाणिज्य महाविद्यालय खापरखेडा जिल्हा नागपूर	कोरोना 19 चा भारतीय कृषी उद्योग व पर्यटन क्षेत्रावर वरील परिणाम	231





प्रा. डॉ. नीता नंदलाल  
तिवारी

अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख  
श्री धाबेकर कला  
महाविद्यालय, खडकी,  
अकोला

Two - Day 46<sup>th</sup> Annual Conference of Vidharbha Arthashastra Parishad  
@ Lokmanya Tilak Mahavidyalaya, Wani Dist. Yawatmal  
4<sup>th</sup> & 5<sup>th</sup> February, 2023

कोविड-19 महामारीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

कोविड-19 महामारीमुळे गेली दोन वर्षे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी कठीण गेली आहेत. संक्रमणाच्या नवीन लाटा, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि अलीकडच्या महागाईमुळे धोरणनिर्मितीसाठी हा काळ विशेषतः आव्हानात्मक आहे. या आव्हानांना तात्काळ प्रतिसाद म्हणून, भारत सरकारने समाजातील असुरक्षित घटकांसाठी आणि व्यावसायिक क्षेत्रासाठी एक विस्तृत सुरक्षा जाळे उभारले. त्यानंतर, मध्यम-मुदतीची मागणी पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्चात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आणि अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन विस्तारासाठी पुरवठा-बाजूचे उपाय लागू करण्यात आले. 2020-21 मध्ये 7.3 टक्क्यांच्या आकुंचनानंतर, आगाऊ अंदाजानुसार, 2021-22 मध्ये वास्तविक जीडीपी 9.2 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. एकूणच, आर्थिक क्रियाकलाप पूर्व महामारी/2019-20 स्तरांवरून उदयास आले आहेत. जवळजवळ सर्व निर्देशकांनुसार, आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीत कोविड-19 च्या "दुसऱ्या लाट" चा आर्थिक परिणाम पहिल्या लाटेदरम्यान पूर्ण-लॉकडाउन टप्प्यापेक्षा खूपच कमी होता, जरी आरोग्यावर परिणाम अधिक गंभीर होता.

#### प्रस्तावना

कृषी आणि संलग्न क्षेत्रे या महामारीमुळे सर्वात कमी प्रभावित झाले आहेत आणि मागील वर्षी 3.6 टक्क्यांनी वाढल्यानंतर 2021-22 मध्ये या क्षेत्राची वाढ 3.9 टक्क्यांनी होण्याची अपेक्षा आहे. 2020-21 मध्ये 7 टक्क्यांच्या आकुंचनानंतर, 2021-22 मध्ये उद्योगाचे एकूण मूल्यवर्धित आगाऊ 11.8 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. सेवा क्षेत्राला साथीच्या रोगाचा, विशेषतः मानवी संपर्काचा समावेश असलेल्या विभागांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. गेल्या वर्षी 8.4 टक्क्यांच्या आकुंचनानंतर या आर्थिक वर्षात क्षेत्र 8.2 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे.

2021-22 मध्ये एकूण वापर 7 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यामध्ये सरकारी खर्चाचे योगदान लक्षणीय आहे. पायाभूत सुविधांवरील सार्वजनिक खर्चात वाढ झाल्याने एकूण स्थिर भांडवल निर्मिती पूर्व-महामारी पातळीपेक्षा जास्त आहे. 2021-22 मध्ये दोन्ही वस्तू आणि सेवांची निर्यात

अपवादात्मकपणे मजबूत झाली आहे, तर वाढती देशांतर्गत मागणी आणि आंतरराष्ट्रीय वस्तूंच्या किमतीमुळे आयात देखील मजबूत झाली आहे.

#### प्रभाव

कोविड-19 महामारीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. कोविड-19 मुळे देशभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला, त्यामुळे लोकांच्या रोजगार आणि व्यवसायावर परिणाम झाला. जागतिक बँकेने जून 2020 मध्ये जारी केलेल्या ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स अहवालानुसार, भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी -3.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. या महामारीचा खालील भागांवर परिणाम झाला आहे-

मागणीत घट: कोविड-19 महामारीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा दिसून आला. परंतु लॉकडाऊनच्या काही दिवसांतच, खरेदी न केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात खरेदीदार आणि रेस्टॉरंट्स बंद झाल्यामुळे भाज्या आणि फळांची मागणी जवळपास

60 टक्क्यांनी कमी झाली. जीवनावश्यक वस्तू, भाजीपाला आणि फळांच्या किमती घसरल्यानंतर वीज, डिझेल आणि पेट्रोलच्या मागणीत घट झाली असली तरी जून महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरात वाढ होत आहे.

अत्यावश्यक वस्तू आणि इंधनाच्या मागणीत घट झाल्याबरोबरच अत्यावश्यक वस्तू यांसारख्या क्षेत्रातील मागणीत अचानक घट झाली आहे. भारतात दरमहा सुमारे 3.3 लाख कोटी रुपयांनी खर्च कमी होऊ शकतो.

पुरवठ्यात व्यत्यय: लॉकडाऊनमुळे मोठ्या कंपन्यांच्या पुरवठा साखळींवर परिणाम झाला आहे आणि केवळ आवश्यक वस्तूंचे उत्पादन आणि वितरण मर्यादित झाले आहे. देशातील विविध मंडईमध्ये कमी व्यापार, मजुरांचा तुटवडा, वाहतुकीच्या समस्या आणि शेतकऱ्यांची अनिच्छा इत्यादींमुळे कृषी उत्पादनाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे घाऊक किमती घसरल्या आहेत.

किमतीत घट: मागणी आणि पुरवठ्यासह बाजारातील बदलांमुळे किमतीतील अस्थिरता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे संपूर्णपणे उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये वस्तूंच्या किमतीत मोठी घट झाली आहे.

देयकच्या शिल्लकवर परिणाम: जागतिक लॉकडाऊनमुळे आयात-निर्यात ऑर्डर 50 टक्क्यांहून अधिक कमी झाल्या आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट, सोने आणि इतर आयातीतील घट यामुळे व्यापार तूट कमी होऊ शकते. सोन्याच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात वाढ झाली आहे, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने म्हटले आहे.

मुद्रास्फीति : कमी उत्पन्न आणि तणावग्रस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमुळे मागणीत घट झाल्यामुळे, RBI च्या मते, FY 2020-21 च्या चौथ्या तिमाहीत महागाई 2.4 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली.

करांवर परिणाम: कोविड-19 मुळे नफा आणि उत्पन्न पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाले आहे, त्यामुळे

प्रत्यक्ष कर वाढवता येत नाही किंवा अप्रत्यक्ष कर वाढवता येत नाही. कारण अप्रत्यक्ष करातील वाढ महागाई वाढवणारी ठरेल आणि त्याचा सर्वाधिक परिणाम गरीब लोकांवर होईल तसेच मागणी आणखी कमी होईल.

गुंतवणूक: अर्थव्यवस्थेत बचत जितकी जास्त तितकी गुंतवणूक जास्त. परंतु कोविड-19 मुळे देशव्यापी लॉकडाऊनच्या प्रभावामुळे देशात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे, त्यामुळे बचत कमी झाली आहे. ताज्या अहवालानुसार, गुंतवणुकीच्या शक्यतांचा अभाव आहे.

### समाधान

मालमतेचे वर्गीकरण: मालमतेला नॉन-परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) मानण्याच्या संदर्भात, केंद्रीय बँकेने निर्णय घेतला आहे की, एखाद्या मालमतेचे एनपीए म्हणून वर्गीकरण करताना स्थगन कालावधीचा विचार केला जाणार नाही. 27 मार्च 2020 रोजी आरबीआयच्या घोषणेनुसार कर्ज देणाऱ्या संस्थांना मंजूरी देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की ज्या खात्यांसाठी कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी स्थगन किंवा स्थगिती देण्याचे ठरवले आहे आणि 1 मार्च 2020 रोजी देय अशा मानक किंवा मानक खात्यांसाठी 90-दिवसांच्या एनपीए मानदंडाचा विचार करताना स्थगन कालावधी विचारात घेतला जाणार नाही..

समाधान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुदत वाढ: न भरलेली मालमत्ता किंवा सध्या एनपीए असलेल्या किंवा एनपीए असलेल्या खात्यांशी संबंधित विवादांचे निराकरण करण्याची आव्हाने लक्षात घेऊन, समाधान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कालावधी 90 दिवसांनी वाढविण्यात आला आहे. जे सध्या एनपीए आहेत किंवा एनपीएहोण्याची शक्यता आहे. लाभांशाचे वितरण: अनुसूचित व्यावसायिक

बँका आणि सहकारी बँका 2019-20 या आर्थिक वर्षाशी संबंधित नफ्यातून कोणताही लाभांश देणार नाहीत. आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या दुसऱ्या तिमाहीच्या शेवटी बँकांच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे त्याच्या निर्णयाचे

पुनरावलोकन केले जाईल. हे बँकांना भांडवलाचे संरक्षण करण्यास सक्षम करण्यासाठी केले गेले आहे जेणेकरून ते अर्थव्यवस्थेला समर्थन देण्याची त्यांची क्षमता टिकवून ठेवतील आणि वाढत्या अनिश्चिततेच्या वातावरणात नुकसान शोषून घेतील.

लिव्हिडिटी कव्हेरेज रेशोमध्ये घट: विविध संस्थांची तरलता स्थिती सुधारण्यासाठी, शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांसाठी तरलता कव्हेरेज रेशोची आवश्यकता 100 टक्क्यांवरून 80 टक्क्यांवर आणली गेली आहे.

आपत्कालीन पत समर्थन हमी योजना: केंद्र सरकारने कोविड-19 महामारीच्या काळात त्यांच्या संचालन गरजा लक्षात घेऊन सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त कर्जे देण्यासाठी आपत्कालीन पत समर्थन हमी योजना सुरु केली. ही योजना 19 लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना लॉकडाऊननंतर त्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यास मदत करेल.

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना: या योजनेअंतर्गत 1.7 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर करण्यात आले. यामुळे तरलतेला चालना मिळेल आणि मागणी वाढेल तसेच औपचारिक आणि अनौपचारिक दोन्ही क्षेत्रांसमोरील आव्हाने कमी होतील.

#### सुझाव

वैयक्तिक खर्च किंवा उपभोग खर्च अर्थव्यवस्थेतील वाढीला पुनरुज्जीवित करण्यात महत्वाची भूमिका बजावेल. त्यामुळे पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या मदत पॅकेजच्या रकमेत वाढ करण्याची गरज आहे.

• लॉकडाऊनच्या परिणामामुळे अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचे त्यांच्या गावात स्थलांतर झाल्यामुळे ग्रामीण जीवनमानावर परिणाम होऊ शकतो. यावर उपाय म्हणून ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करता येईल आणि विशेषतः अन्नप्रक्रियासारख्या उद्योगांना प्रोत्साहन देता येईल.

#### निष्कर्ष

प्रगत आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये चलनवाढ ही जागतिक समस्या म्हणून पुन्हा समोर आली आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये भारतातील ग्राहक किमतीची चलनवाढ वार्षिक आधारावर 5.6 टक्के होती, जी लक्ष्याच्या मर्यादेत आहे. मात्र, घाऊक महागाईचा दर दुहेरी आकड्यात आहे. हे अंशतः अल्प-मुदतीच्या आधारभूत परिणामांमुळे झाले असले तरी, भारताने आयातित चलनवाढ, विशेषतः जागतिक कूडच्या किमतींवरून लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

एकूणच, समष्टि आर्थिक स्थिरता निर्देशक सूचित करतात की भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 च्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सज्ज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असण्याचे एक कारण म्हणजे तिची अनोखी प्रतिसाद रणनीती आहे. कठोर प्रतिसादासाठी पूर्व-प्रतिबद्ध होण्याऐवजी, भारत सरकारने एकीकडे कमकुवत वर्गासाठी सुरक्षा देण्याचा पर्याय निवडला.

भारताच्या प्रतिसादाचे आणखी एक वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे मागणी व्यवस्थापनावर पूर्ण विसंबून राहण्याऐवजी पुरवठ्याची बाजू सुधारणांवर भर देणे आहे. या पुरवठा बाजूच्या सुधारणांमध्ये अनेक क्षेत्रांचे नियंत्रणमुक्ती, कार्यपद्धतींचे सुलभीकरण, 'पूर्वलक्ष्य कर' सारख्या जुन्या समस्यांचे निराकरण, नसबंदी, उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन इत्यादींचा समावेश आहे. सरकारच्या भांडवली खर्चातही तीव्र वाढ ही मागणी व्यवस्थापन तसेच पुरवठा बाजूचा प्रतिसाद म्हणून पाहिली जाऊ शकते, कारण ती भविष्यातील वाढीसाठी पायाभूत सुविधांची क्षमता निर्माण करते.

#### संदर्भ

1. <https://www.chronicleindia.in>
2. <https://www.indiabudget.gov.in>
3. <https://www.rbi.org.in>
4. Journal of Ravishankar University. कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव. सेठी, पाण्डेय, and पाण्डेय (2021)



# Platinum

ISSN 2231-0096

A Peer Reviewed  
National Multidisciplinary Journal

Volume - 13 Number - 2 June 2022



For this Issue - Editor Board)

### Chief Editor

Prof. (Dr.) Santosh Kayande

### Editor

Prin. (Dr.) Sunil Pande

Prof. (Dr.) Vilas Tayade

Prof. (Dr.) Ashok Ingle

Dr. Moreshwar Nannavare

Mr. Sachin Kothekar

Mr. Gajanan Tayade

### Managing Editor

Mr. Yuvraj Mali

### Editorial Office

Atharva Publications

Plot No.17, Devidas Colony

Varkhedi Road, Dhule - 424 001

[www.atharvpublications.com](http://www.atharvpublications.com)

E-Mail : [atharvpublications@gmail.com](mailto:atharvpublications@gmail.com)

### Branch :

Circulation & Advertisement

Atharva Publications

Basement, Om Hospital, Near Anglo Urdu

Highschool, Dhake Colony, Jalgaon - 425001

Ph.No. 0257-2239666

### Subscription Rates

Single Copy for reader Rs. 350.00 or

US \$ 35.00 Only (extra postage charge)

For printing/ Publication of research Paper

Individuals Rs. 1200.00 (each research paper) Or

US \$ 100.00

Institutions Rs. 1400.00 per annum Or Us \$ 140.00

1. Editing of the research journal is processed without any remittance. The Selection and publication is done after recommendation of subject expert Refree.
2. Thoughts, Language vision and example in published research paper are entirely of author of research paper. It is necessary that both editor and editorial board are satisfied by the research paper. The responsibility of the matter of research paper is entirely of author.
3. Along with research paper it is compulsory to sent Membership form and copyright form.
4. In any condition if any National/ International university denies to accept the research paper published in the journal then it is not the responsibility of Editor, Managing Editor Publisher and Management.
5. Before re-use of published research paper in any manner, it is compulsory to take written acceptance form Managing Editor unless it will be assumed as disobedience of copyright rules.
6. All the legal undertaking related to this research journal are subjected to be hearable at Dhule Jurisdiction only.
7. The research journal will be sent by normal post. If the journal is not received by the author of research paper then it will not the responsibility of Editor and publisher. The amount or registered post should be given by the author of research paper. It will be not possible to sent second copy of research Journal.
8. Authors are requested to follow the author's Guide lines Contact Managing Editor - 9764694797
  - For book reviews, please send two copies of the book (one for the Reviewer and other for the library of the journal) to the Managing editor.
  - Donations of books /journals / cash / gift are welcome and will be gratefully acknowledged. All disputes concerning the journal will be settled in the court of Jalgaon, Maharashtra.

प्लॅटिनम या त्रैमासिकात प्रसिद्ध झालेली मते संपादक, सहसंपादक, कार्यकारी संपादक, आणि सल्लागार मंडळ यांना मान्य असतीलच असे नाही. या नियतकालिकात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या लेखातील लेखकांची मते ही त्यांची वैयक्तिक मते आहेत. तसेच शोधनिबंधाची जबाबदारी ज्या-त्या लेखकांवर राहिल.

मेसर्स अथर्व पब्लिकेशन्सच्यावतीने कार्यकारी संपादक श्री.युवराज माळी यांनी प्लॉट नं.१७, देविदास कॉलनी, धुळे-४२४ ००१ (महाराष्ट्र) येथे प्रकाशित केले व झरोका प्रिंटर्स, जळगाव येथे मुद्रित केले. मोबाईल : ९४०५२०६२३०. जळगाव (ऑ.) : ०२५७-२२३९६६६.

## Index

• Gandhian Philosophy of Satyagraha .....	7
- Dr. Santosh Narayan Kayande	
• Relevance of Mahatma Gandhi's Nonviolence Today .....	10
- Dr. Chandrashekhar Malviya	
• Non-Violence of Mahatma Gandhi .....	13
- Mr. Gajanan, D. Tayade	
• Gandhism the Panacea for 21st Century Maladies .....	16
- Dr. Anagha P. Somwanshi	
• The Relevance of Gandhian Thought for International Peace .....	18
- Mr. Awadhut Vitthal Borkar	
• Mahatma Gandhi and Indian Literature: A Brief Outline.....	21
- Aakansha R. Bhumber	
• Mahatma Gandhi : An Ideology Towards Peaceful World and Social Upliftment.....	24
- Prof. Gajanan B. Ingle	
• महात्मा गांधी आणि अहिंसा .....	२७
- प्रा. डॉ. योगेश दा. उगले	
• महात्मा गांधी आणि ग्रामस्वराज्य .....	३०
- डॉ. प्रशांत विघ्ने	
• म. गांधीजींच्या ग्रामराज्याच्या विचारांची प्रासंगिकता.....	३३
- प्रा. डॉ. ममता विजयराव पाथ्रीकर	
• गांधी-आंबेडकर भावविश्वाचा अन्वयार्थ .....	३६
- डॉ. अशोक इंगळे	
• महात्मा गांधी : स्वराज्याची संकल्पना .....	३८
- डॉ. ए. डी. जाधव	
• महात्मा गांधींचे ग्रामस्वराज्यासंबंधीचे विचार .....	४२
- प्रा. डॉ. बाळासाहेब जी. जोगदंड	
• महात्मा गांधीजींची ग्रामस्वराज्याची संकल्पना .....	४६
- प्रा. डॉ. बबिता येवले	
• महात्मा गांधीची सत्य व अहिंसा संकल्पना.....	४९
- प्रा. डॉ. मनिषा शंकर यादव	
• महात्मा गांधीजींचा स्वतंत्रता आंदोलनातील सहभाग (महिलांचे विशेष संदर्भात) .....	५२
- प्रा. डॉ. प्रिया भानूदास बोचे	
• महात्मा गांधी यांच्या अर्थशास्त्रीय विचारांची प्रासंगिकता .....	५४
- डॉ. एम. के. नन्नावरे	
• महात्मा गांधी आणि राज्यविरहित समाज.....	५७
- प्रा. डॉ. संतोष सदाशिवराव मिसाळ	
• भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील महात्मा गांधीजींचे योगदान .....	५९
- डॉ. जयवंत पिराजी जुकरे	



- प्रा. डॉ. संतोष सदाशिवराव मिसाळ  
राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख  
श्री धाबेकर कला महाविद्यालय, खडकी अकोला

### प्रस्तावना

महात्मा गांधी यांचे राजकीय तत्वज्ञानातील व राजकारणातील स्थान अद्वितीय आहे. मॅचेस्टर गाडीयनने त्यांचे वर्णन राजकारण यांमधील संत व संतांमध्ये राजकारणी असे केले आहे. म. गांधींनी नैपुण्य ब्रिटिश राजवट भारतीय जनता आणि जगातील राष्ट्रांचे लक्ष घेतले. गांधी हे जणू काही एक राजकीय संमोहनतज्ञ होते. तसेच महात्मा गांधी हे एक आदर्शवादी आणि अध्यात्मवादी पुरुष होते. गांधीजींच्या विचारांवर अनेक विचारवंतांच्या विचारांचा प्रभाव पडला असल्याचे आढळते. थोरिओ (Thoreau) पासून त्यांनी सविनय कायदेभंगाची कल्पना घेतली. रस्किनच्या 'Unto this Last' आणि Crown of wild Olives मधूनही श्रमप्रतिष्ठा व इतर कल्पना घेतल्या. टॉलस्टॉयपासून अराज्यवाद आणि अहिंसात्मक असहकाराची कल्पना स्वीकारली. म. गांधीजींचे राज्यविरहित समाजविषयक विचार पुढील प्रमाणे आहेत.

### ग्राम

देशाच्या उन्नतीसाठी गांधीजींनी ग्राम महत्त्वपूर्ण मानले आहेत. प्रत्येक गाव स्वावलंबी राहिल. सहकार्य हा त्याचा आधार राहिल. गावातील लोक शांती पूर्व व गौरवशाली जीवन व्यतीत करतील. प्रत्येक गावात पंचायत राहिल. आदर्श समाजाची स्थापना गावात शक्य आहे. गांधीजी राजकीय शक्तीच्या विकेंद्रीकरणाचे समर्थक होते. गावातील पंचायत तेथील प्रशासन पाहिल. आपल्या सर्व आवश्यकतांची पूर्ती गावाची साधने ग्रामपंचायती जवळ उपलब्ध राहतील. गांधीजींचा आदर्श समाज पिरॅमिड सारखा नव्हे तर गोलाकार राहिल. व्यक्ती त्याचा केंद्रबिंदू राहिल.

### समाजव्यवस्था

म. गांधीजींच्या आदर्श राज्यातील प्रत्येक व्यक्ती सारखीच श्रेष्ठ राहिल. समाजात गांधीजी सर्वांना समान स्थान देतात, प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या कुटुंबातील व्यवसाय करावा असे गांधीजींचे मत होते. जेव्हा प्रत्येक गाव स्वावलंबी तर होतेच पण व्यवसायातही कुशलता येते. अस्पृश्यता हा हिंदू समाजावर लागलेला कलंक आहे. असे ते मानते होते. स्त्रियांच्या शिक्षणावर त्यांनी जोर दिला. मादक द्रव्यांच्या सेवनाच्या ते विरोधी होते.

### शारीरिक श्रम

म. गांधीजींच्या आदर्श समाजात शारीरिक श्रमाला महत्त्व आहे.

प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःचे अन्न मिळविण्याइतके तरी श्रम केले पाहिजेत. व्यक्ती श्रीमंत असो वा गरीब असो, प्रत्येकाने श्रम केले पाहिजे सर्वांनी श्रम केल्यास समाजातील वर्ग व्यवस्था नष्ट व्हायला मदत तर होतेच, पण शिवाय शारीरिक स्वास्थही चांगले राहते म्हणूनच श्रमाची प्रतिष्ठा वाढवली पाहिजे.

### राज्याचे कार्यक्षेत्र

आदर्श राज्यात व्यक्ती सरकारच्या नियंत्रणापासून जास्तीत जास्त मुक्त असेल. राज्यविहीन समाज निर्माण करतांना मार्क्सवादी राज्याचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण समाजजीवन व्यापून टाकते. परंतु गांधीजींचे विचार तसे नाहीत.

### राज्याला विरोध करण्याचा अधिकार

म. गांधीजी राज्याला विरोध करण्याचा अधिकार देतात पण राज्य जर जनतेच्या इच्छेने प्रतिनिधित्व करित नसेल तर जनतेने राज्यांच्या कायद्याचा विरोध करावा. अशावेळी राज्याला विरोध करणे जनतेचा अधिकार नव्हे तर ते कर्तव्य ठरते. विरोध मात्र अहिंसात्मक मार्गानेच करण्यात यावा यावर गांधीजींचा कटाक्ष आहे .

### न्यायव्यवस्था

म. गांधीजींच्या राज्यात न्याय स्वस्त राहिल. गंभीर गुन्ह्यांचे खटले फक्त वरच्या न्यायालयात जातील. साधारण खटले पंचायतीमार्फत सोडविले जातील वकिलाची योग्यता समाजसेवा समजण्यात यावी. वकिलाची फी कायद्याने निश्चित व्हावी. न्याय लवकर मिळावा हा देखील गांधीजींचा आग्रह होता.

### कारावास व्यवस्था

महात्मा गांधीजींना कारावासात बदल्याच्या भावनेने देण्यात येणारी शिक्षा त्यांना मान्य नव्हती. शिक्षेचा उद्देश गुन्हेगाराला सुधारण्याचा असावा. त्याची मानसिक स्थिती लक्षात घेऊन त्याच्यावर मानसोपचार करावेत. मानसोपचाराने त्याच्यातील दोष दूर करावेत. गुन्हेगारांशी कठोर व्यवहार करण्यापेक्षा त्यांना योग्य मार्गदर्शन करावे. गुन्हेगाराला धंदे शिक्षण देण्यात यावे. कारावासा तून तो बाहेर पडल्यानंतर एक स्वावलंबी व्यक्ती म्हणून तो जगू शकला पाहिजे.

### आर्थिकतेचा सिद्धांत

गांधीजींच्या राज्यविहीन समाजाचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे आर्थिकतेचा आणि विश्वस्ततेचा सिद्धांत होय. गांधीजींचे राजकारण, अर्थकारण आणि समाजकारण ह्यांचा पाया मानवता होय. समाजात

असलेली संपत्ती कोणत्याही व्यक्तीचा मालकीची नसून ती समाजाच्या मालकीची आहे. कोणत्याही व्यक्तीने गरजेपेक्षा जास्त संपत्ती ठेवणे याला गांधीजीचा सक्त विरोध आहे. व्यक्तीच्या गरजांपेक्षा अतिरिक्त असलेली संपत्ती जनतेही आहे. जमीनदार आणि भांडवलदार यांनी ही संपत्ती ट्रस्टी म्हणून सांभाळावीत आणि तिचा उपयोग आम जनतेच्या कल्याणासाठी करावा. त्यामुळे कोणी कोणाला लुटण्याचा किंवा आर्थिक शोषण करण्याचा प्रश्नच निर्माण होणार नाही. परिणामतः धनिकांचा गरीब आणि दारिद्री लोकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सहानुभूतीचा बनेल. प्रत्येक व्यक्तीने आपली संपत्ती मर्यादित ठेवावी.

म. गांधी विचारातून विनोबा भावे यांनी भूदान चळवळ उभी केली की जेणेकरून आपणास आर्थिक विषमता दूर करता येईल प्रत्येकाला जमीन कसता येईल आणि यामुळे सामाजिक व आर्थिक क्रांतीची बीजे रुजतील व जगांत शांती प्रस्थापित होईल. गांधीजींना आर्थिक समता मान्य आहे. परंतु त्याचा अर्थ प्रत्येकाला राहण्यासाठी घर, पुरेसे अन्न आणि घालायला कपडे असा आहे.

संपूर्ण संपत्तीचा मालक ईश्वर आहे. गांधी विचाराभोवती अध्यात्मिक तेजोवलय दिसून पडते. सर्व मनुष्यप्राणी ईश्वराची संपत्ती आहे. ईश्वर मनुष्या मनुष्यात कोणताच भेदभाव करित नाही म्हणून संपत्तीचा आधारावर श्रीमंत-गरीब असा भेदभाव करो गांधीजींना मान्य नाही. धनवान व्यक्तींनी संपत्तीचा उपयोग स्वतःच्या चैनीसाठी करू नये. गरीब लोक दारिद्र्यात खितपत पडले आहेत. त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा या गरजांची पूर्तता करता येत नसतांना श्रीमंतांनी पैशाची चैन करणे म्हणजे निर्धन जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणे होय म्हणून गांधीजी भांडवलशाहीचा विरोध करतात.

परंतु अशी भांडवलशाही नष्ट करण्यासाठी मार्क्सप्रणीत क्रांतीचा मार्ग अवलंब करणे त्यांना अनैतिक आणि बेकायदेशीर वाटतो. त्यासाठी भांडवलदारांचे हृदय परिवर्तन करावे. भांडवलदारांकडून होणारा आर्थिक अन्याय व आर्थिक शोषण यांचे हृदयपरिवर्तन केल्याने नष्ट होईलच अशी त्यांना खात्री आहे. त्यासाठी त्यांच्या विरुद्ध चळवळ, उपोषण, बहिष्कार, असहकार आदी मार्गांचा अवलंब जनतेनेच करावा. परंतु हिंसात्मक मार्ग टाळला जावा. अहिंसा व सत्य या मार्गानेच आपण गेले पाहिजे. तसेच गांधीजी मारक उत्पादक यंत्रे व संहारक यंत्रे यांचे असणारे मोठमोठ्या उद्योगधंदे व यंत्रांच्या सहाय्याने चालविणार्या कारखान्यामुळे भांडवलशाही अधिकाधिक फोफावते आणि गरिबांचे जास्तीत जास्त आर्थिक शोषण होते म्हणून गांधीजी कुटीर किंवा गृहउद्योगांना प्राधान्य देतात. यात मानवी श्रमाला वाव दिल्यामुळे बेकारी उद्भवत नाही असे गांधीजींचे मत आहे.

#### श्रमप्रतिष्ठा

'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' या गीतेतील वचनाला गांधीजी फार महत्त्व देतात. फळाची आशा न करता कर्म करावे. प्रामाणिक प्रयत्न कधीच असफल होत नाही. गीते पासून मिळालेली ही दीक्षा गांधीजींनी जीवनात तंतोतंत पाळली. स्वकर्तव्याचे पालन केल्याने अपेक्षित परिणाम प्राप्त होऊन आरोग्य आणि समाधान लाभते असे त्यांचे मत आहे. कोणते काम हे श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ नाही, उच्च किंवा

निच नाही. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने श्रम केल्यास समाजातील वर्ग व्यवस्था नष्ट होते. काम नाही तर जेवण नाही हे मार्क्सचे विधान त्यांना मान्य होते. समाज आणि राष्ट्र मजबूत करण्यासाठी श्रमाची गरज आहे. अशा श्रमिकाकडे समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने आत्मीयतेने, आदराने पाहावे, श्रमाची अवहेलना करू नये. त्यांचे विचार आजही सर्वश्रेष्ठ आहेत म्हणूनच राज्य विरहित समाजात मतदानाचा अधिकार परिश्रम या आधारावर घ्यावा असे गांधीजींचे आग्रही मत आहे.

#### वर्ग समन्वय

गांधीजींना वर्गसंघर्ष मान्य नाही. वर्ग संघर्षामुळे समाजाचे अतोनात नुकसान होते. म्हणून आपल्या आदर्श राज्यात गांधीजी वर्ग समन्वयाला महत्त्व देतात. प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या कार्याइतकेच महत्त्व इतरांच्या कार्याला देणे, परस्परात सहकार्य आणि सद्भाव निर्माण करणे, समान प्रतिष्ठेची वागणूक देणे, इतरांचे शोषण न करणे, कोणत्याही व्यवसायाला कमी न लेखणे, यालाच गांधीजी वर्ग समन्वय असे म्हणतात. थोडक्यात तुम्ही जगा आणि इतरांनाही जगू द्या.

#### शिक्षण

गांधीजींच्या आदर्श राज्यात प्रारंभिक शिक्षणावर जास्त जोर दिला आहे. शिक्षण म्हणजे मनुष्याचा सर्वांगीण विकास होय. सामाजिक उन्नतीचे एक साधन आहे. अहिंसात्मक तत्वाला शिक्षणात विशेष स्थान दिले पाहिजे. शिक्षणाचा संबंध जीवनाशी असावा. प्राथमिक शिक्षण राज्यात निःशुल्क व अनिवार्य असावे. गांधीजींची शिक्षण योजना बुनियादी शिक्षण योजना म्हणून प्रसिद्ध आहे. या पद्धतीत द्रुतीतून शिक्षण देण्यात येते. 'करा व शिका' हे तत्व या पद्धतीत अमलात आणण्यात येते. शिक्षण मातृभाषेतून दिले जाते. शिक्षण घेतल्यानंतर व्यक्ती स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकते. या शिक्षणामुळे सुशिक्षित बेकारांची समस्या राहणार नाही. व्यक्तीला स्वावलंबी बनविणारे शिक्षण असायला पाहिजे.

गांधीजींचा आदर्श समाज हा राज्यविरहित राहिल. त्यात विभिन्न वर्गांचे अस्तित्व राहणार नाही. राज्यविरहित समाजातील सामाजिक जीवन स्वयंनियंत्रित राहिल. गांधी हे तात्विक अराज्यवादी होते. राज्य ही एक आपत्ती आहे. गांधीजींच्या मते, व्यक्तीच्या नैतिक कमतरतामुळे राज्य व त्यांची सत्ता आवश्यक ठरते. एकदा नैतिक विकास झाला म्हणजे राज्याची सत्ता निरुपयोगी होईल. सत्ता हे हिंसेचे प्रतिक आहे. म्हणून त्यांचा आदर्श समाजात तिला स्थान नाही. या राज्यविरहित समाजात लोकसत्ता राहिल. केंद्रित सत्ता नसल्याने त्याचे दूरउपयोगही त्यात आढळणार नाहीत व जी काही सत्ता असेल ती नैतिक सत्ता राहिल. समाजाच्या कल्याणार्थ व्यक्ती स्वेच्छेने समाजाचे नियंत्रण स्वीकारतील.

#### संदर्भ सूची :

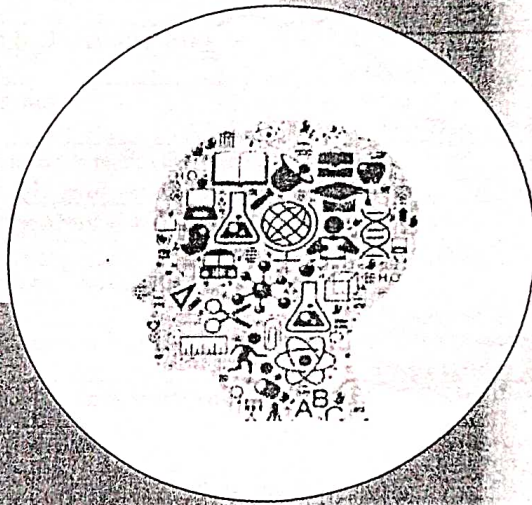
- 1) वैद्य डॉ. सुमन कोठेकर, डॉ. शांता, आधुनिक भारतचा इतिहास. १९२०, १९४७, श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूर
- 2) देवगांवकर डॉ. एस.जी., राजकीय विचारवंत, श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूर
- 3) पवार डॉ. जयसिंगराव, हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्य चळवळींचे इतिहास, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर

22.23

ISSN No 2347-7075  
Impact Factor- 7.328  
Volume-4 Issue-2

15

**INTERNATIONAL  
JOURNAL of  
ADVANCE and  
APPLIED  
RESEARCH**



**Publisher: P. R. Talekar**  
Secretary,  
Young Researcher Association  
Kolhapur(M.S), India

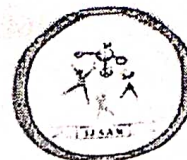
Young Researcher Association





CONTENTS

Sr No	Paper Title	Page No.
1	Effect Of Stretching Exercises On Flexibility Of Volleyball Players Prof. Madhavi Mardikar	1-3
2	The Role Of Health In Personality Development Dr. Alka Anil Thodge	4-5
3	Effects Of Dance Aerobics On Leg Strength Of College Girls Dr. Rajani Murkute , Dr. Saurabh Mohod , Mr. Ankush Ghate	6-8
4	Psychological Wellbeing for Healthy Livelihood Dr. Shashank G. Nikam , Dr. Prakash M. Chopade	9-11
5	A Comparative Study of Knowledge Between Male and Female Taekwondo Coaches of Nagpur City Pravin S. Deulkar	12-13
6	The Study Of The Use Of Technology In Sports And The Impact Of Technology On Cricket Dr. G. Ramchandra Rao	14-17
7	Women In Sports Dr Seema. M. Harde	18-21
8	Injury Rehabilitation in Sports by First aid training Dr. Manojkumar M. Varma	22-25
9	Role of Sports Psychology in Games Dr. Dinesh Kumar Kimta	26-27
10	Use of Information Technology in Sports Performance Chandramohan Singh Bisht, Bhimrao Pawar, Romi Bisht	28-30
11	Yoga And Meditation: Nourishing Mental Health And Wellness DR. Chandrajit B. Jadhav	31-33
12	Significant Role Of Sports Nutrition: Nourishment In Health Dr. Sangita N. Lohakpure	34-37
13	Physical Education And Sports Science: Future Innovations And Development Dr. Satender Balwant. Singh	38-40
14	The Study Of The Use Of Technology In Sports And The Impact Of Technology On The Football Matches Dr. B. V. Shrigiriwar	41-44
15	Barriers To Women Participation In Sport And Physical Activity Mamta Singh Rathour , Dr. Vivek P Gulhane	45-47
16	A Comparative Study Of Mental Health Status Of Working And Non-Working Women Vimal Singh , Dr. Vivek P Gulhane	48-49
17	Psychological Skills Training key to success in Sports Jigmat Dachen , Ujwala Koche	50-54
18	Sports management in physical education Dr. Rahul Madhukarrao Rode	55-56
19	Women in Sport Dr. Naresh P. Borkar	57-61
20	Different Types of Doping Drugs in Sports Dr. Sanjay R. Agashe , Dr. Sarang S. Khadase	62-64
21	Nutrition in Sports Dr. Jayant A. Burade	65-68
22	Sports Management Environment: Trends And Development Kuldeep R. Gond	69-72
23	Yoga And Meditation: Mental And Physical Health Dr. Vijay E. Somkuwar	73-78
24	The Dope on Doping in Indian Sports Dr. Pravin Gopalrao Patil	79-83
25	The Study of The Changing Nature Of Career Opportunities In Sports Dr. Avinash Titarmare	84-87
26	Nutrition and Sports: Enhancing Better Performance of Athlets Dr. Naresh Bhojar	88-90



---

Significant Role Of Sports Nutrition: Nourishment In Health

---

Dr. Sangita N. Lohakpure

Director of Sports and Physical Education Shri Dhabekar Arts college Khadki, Dist.  
Akola

Corresponding Author- Dr. Sangita N. Lohakpure

DOI- 10.5281/zenodo.7543993

---

**Abstract**

Nutrition plays an important role in sports. Therefore, it is often referred to as "unobserved preparation". But when it comes to food and execution, it's not just about skilled competitors. Today, a huge number of novice competitors do physical work every day, both casually and semi-professionally. This population also strives to improve their marks, which can be achieved by following proper health rules. In this way, it is necessary to go through a nutritional method adapted to the competitor and training meetings. In addition, various benefits of achieving satisfactory nutrition in sports are identified with changes in body organization, reduction of injuries and increased duration of skilled work. The purpose of this section is to determine the nutritional needs of the competitors to meet the training goals. Nutritional systems address macronutrient utilization, hydration, and timing based on activity type and intensity. At the most essential level, nutrition is significant for competitors since it gives a wellspring of energy needed to play out the action. The food we eat impacts on our solidarity, preparing, execution and recuperation. Not exclusively is the sort of food significant for sports nourishment yet the occasions we eat for the duration of the day additionally affects our presentation levels and our bodies capacity to recuperate in the wake of working out.

---

**Introduction**

Nutrition is strongly related to health, especially in sports, because the needs for energy and nutrients increase. Knowing the physiology of exercise is necessary to know the different metabolic pathways that occur during sports. Sports nutrition has recently emerged as a claim to fame in the nutrition industry. Competitors constantly challenge their bodies through real preparation and competition. To keep up with the real demands of their activity or game, competitors must fuel their bodies with sufficient consistency. This execution cycle requires a special method;

Therefore, competitors who need to improve their nutrition should seek out experts who are experts in sports nutrition and have experience in creating individualized plans. In its relatively early stages, sports nutrition research is constantly producing new and exciting information. It is important that sports nutritionists stay informed so that they can be experience-based experts. Becoming an evidence-based expert requires using nutritional rules and practices that have been proven successful through peer-reviewed research. Experts who have considered sports nutrition, have knowledge of the industry and are up-to-date with the latest nutritional

research, can recommend individualized nutrition plans that meet important health needs, improve performance and accelerate the recovery of competitors. Becoming an evidence-based gaming nutrition expert can create an invigorating and rewarding calling. Basic nutrition is important for development, well-being and academic success, and energy. Sports nutrition improves athletic performance by reducing fatigue and the risk of illness and injury; In addition, it allows competitors to progress in preparation and recover faster. Replacing energy consumption with energy use is important to avoid energy shortages or excesses. Lack of energy can cause short stature, delayed puberty, female fractures, loss of body mass, and prolonged incapacitation due to fatigue, injury, or illness. An overabundance of energy can lead to overweight and indolence. Before puberty, the minimum food and energy needs (calorie needs) of young men and women are comparable. The energy needs of young people are more factors that depend on age, activity level, rates of development and actual stage of development. These proposed energy allowances are an important basis for ensuring proper development and real capacity. Extra calories are needed to recharge the energy consumed during growth spurts and sports. For example, a 30 kg young woman playing soccer for 60 minutes would typically burn 270 calories, or a 60 kg child playing 60 minutes of ice hockey would typically burn 936 calories.

#### **Carbohydrates**

Carbohydrates are the main fuel hotspot for competitors since they give the glucose used to energy. One gram of carb contains around four kilocalories of energy. Muscle glycogen is the most promptly accessible fuel hotspot for

working muscle and can be delivered more rapidly than other fuel sources. Carbs ought to contain 45% to 65% of complete caloric admission for four-to 18-year-olds. Great wellsprings of starches incorporate entire grains, vegetables, organic products, milk and yogurt.

#### **Protein**

Proteins construct and fix muscle, hair, nails and skin. For gentle exercise and exercise of brief term, proteins don't go about as an essential wellspring of energy. Be that as it may, as exercise length expands, proteins help to keep up blood glucose through liver gluconeogenesis. One gram of protein gives four kilocalories of energy. Protein ought to include roughly 10% to 30% of absolute energy consumption for four-to 18-year-olds. Great wellsprings of protein incorporate lean meat and poultry, fish, eggs, dairy items, beans and nuts, including peanuts.

#### **Fats**

Fat is fundamental nutrient which retain fat-solvent nutrients like (A, D, E, K), to give fundamental unsaturated fats, secure indispensable organs and give protection. Fat likewise gives the sensation of satiety. It is a calorie-thick wellspring of energy (one gram gives nine kilocalories) however is more hard to utilize. Fats ought to contain 25% to 35% of absolute energy consumption for four-to 18-year-olds. Immersed fats ought to include close to 10% of absolute energy consumption. Great wellsprings of fat incorporate lean meat and poultry, fish, nuts, seeds, dairy items, and olive and canola oils. Fat from chips, treats, seared food sources and prepared products ought to be limited.

#### **Micronutrients**

Calcium is significant for bone wellbeing, typical catalyst movement and muscle compression. The day by

day suggested admission of calcium is 1000 mg/day for four-to eight-year-olds and 1300 mg/day for nine-to 18-year-olds. Calcium is contained in an assortment of food varieties and refreshments, including milk, yogurt, cheddar, broccoli, spinach and strengthened grain items.

Vitamin D is important for bone wellbeing and is associated with the retention and guideline of calcium. Competitors living in northern scopes or who train inside (eg, olympic skaters, gymnasts, artists) are bound to be nutrient D insufficient. Wellsprings of nutrient D incorporate invigorated food sources, like milk, and sun openness. Dairy items other than milk, like yogurt, don't contain vitamin D.

Iron is significant for oxygen conveyance to body tissues. During youth, more iron is needed to help development just as expansions in blood volume and fit bulk. Young men and young ladies nine to 13 years old ought to ingest 8 mg/day to stay away from exhaustion of iron stores and iron-inadequacy paleness. Teenagers 14 to 18 years old require more iron, up to 11 mg/day for guys and 15 mg/day for females. Iron consumption is normal in competitors as a result of diets poor in meat, fish and poultry, or expanded iron misfortunes in pee, excrement, sweat or feminine blood.

#### Hydration

Appropriate hydration requires liquid admission previously, during and after exercise or movement. The measure of liquid required relies upon numerous components, including age and body size. Prior to action, competitors ought to devour 400 mL to 600 mL of cold water 2 h to 3 h before their occasion. During donning exercises, competitors ought to devour 150 mL to 300 mL of liquid each 15 min to 20 min. For occasions enduring under 1 h, water is

adequate. Following action, competitors should drink sufficient liquid to supplant sweat misfortunes. This typically requires burning-through roughly 1.5 L of liquid/kg of body weight lost. The utilization of sodium-containing liquids and snacks after practice assists with rehydration by animating thirst and liquid maintenance. For non-competitors, routine ingestion of starch containing sports beverages can bring about utilization of unreasonable calories, expanding the dangers of overweight and stoutness, just as dental caries and, thusly, ought to be dodged.

#### Balanced diet

An even eating routine is fundamental for developing competitors to keep up legitimate development and advance execution in athletic undertakings. An ideal eating regimen contains 45% to 65% starches, 10% to 30% protein and 25% to 35% fat. Liquids are vital for keeping up hydration and ought to be burned-through previously, during and after athletic occasions to forestall parchedness. Timing of food utilization is essential to streamline execution. Suppers ought to be eaten at least 3 h before exercise and tidbits ought to be eaten 1 h to 2 h before movement. Recuperation food sources ought to be devoured inside 30 min of activity and again inside 1 h to 2 h of action to permit muscles to reconstruct and guarantee legitimate recuperation.

#### Conclusion

At the most essential level, nutrition is significant for competitors since it gives a wellspring of energy needed to play out the action. The food we eat impacts on our solidarity, preparing, execution and recuperation. Not exclusively is the sort of food significant for sports nourishment yet the occasions we eat for the duration of the day additionally affects our presentation levels and our

bodies capacity to recuperate in the wake of working out.

#### References

1. Eberle, S. G. "High-intensity games sustenance". Wellness Magazine. 24 (6): 25.
2. Lizcano, Fernando; Guzmán, Guillermo (2014). BioMed Research International. 2014: 757461. doi:10.1155/2014/757461. ISSN 2314-6133. PMC 3964739. PMID 24734243.
3. Jurek, Scott (2012). Eat and Run. London: Bloomsbury.
4. Lemon P. (1995). "Do competitors need more dietary protein and amino acids?". Global Journal of Sport Nutrition. 5: 39-61. doi:10.1123/ijnsn.5.s1.s39. PMID 7550257.
5. Spada R. "High-intensity games sustenance". Diary of Sports Medicine and Physical Fitness. 40 (4): 381-382



16

# National Multidisciplinary Conference on Emerging Trends, Opportunities and Challenges in Higher Education

[ NCETOCHE-2023 ]

Date : 28th January, 2023

## Organized By

Janata Shikshan Prasarak Mandal's  
Smt. Vatsalabai Naik Mahila Mahavidyalaya Pusad,  
Department of Home Science and IQAC  
NAAC RE-ACCREDITED -B GRADE

affiliated to

Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, Maharashtra, India

## Certificate of Participation

Ref : NCETOCHE23/Certificate/10547

28-Jan-2023

This is to certify that **Dr. Sangita N. Lohakpure** has Attended and Submitted a research paper entitled '**Government Policies in Higher Education : An Indian Scenario**' in the NCETOCHE-2023 held on 28<sup>th</sup> January 2023 Organised by Janata Shikshan Prasarak Mandal's Smt. Vatsalabai Naik Mahila Mahavidyalaya Pusad, Department of Home Science and IQAC, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, Maharashtra, India.

*B. Vandana B. Wankhede*

Convener  
Dr. Vandana B Wankhede

*G. T. Pati*

Principal  
Dr. G. T. Pati



# International Journal of Scientific Research in Science and Technology

Print ISSN : 2395-6011 | Online ISSN : 2395-602X

[ UGC Journal No : 64011 ]

Peer Reviewed and Refereed International Scientific Research Journal  
Scientific Journal Impact Factor : 8.014

## Certificate of Publication

Ref : IJSRST/Certificate/Volume 10/Issue 7/10547

28-Jan-2023

This is to certify that Dr. Sangita N. Lohakpure has published a research paper entitled '*Government Policies in Higher Education : An Indian Scenario*' in the International Journal of Scientific Research in Science and Technology (IJSRST), Volume 10, Issue 7, January-February-2023 .

This Paper can be downloaded from the following IJSRST website link

<https://ijsrst.com/IJSRST231053>

IJSRST Team wishes all the best for bright future

Editor in Chief  
IJSRST



Associate Editor  
IJSRST

Website : <https://ijsrst.com>



## Government Policies in Higher Education : An Indian Scenario

Dr. Sangita N. Lohakpure

Director of Sports and Physical Education, Shri Dhabekar Arts college Khadki, Dist. Akola, Maharashtra, India

### ABSTRACT

Further education constitutes the main means of improvement. The changes in India's higher education strategy basically correspond to the changing idea of the Indian Express, its concept of improvement and the shift to neoliberalism. Perhaps the best problem in our schools today is connecting with students and having a passion for learning. Our usually school group was busy "filling the cans" or helping the remedial students with the content given by the address. Motivating undergraduate students to learn and teach is integral to preparing them for future success as students and citizens. To light the flame, teachers must consider limitations, interests and tendencies to underlearn (Egan, 2008). Fundamentally, compelling undergraduate studies require connecting with the creative mind and stoking the fire of the imagination. As noticeable in different areas also, India is seeing expanding stream of capital without the upsides of free enterprise. Advanced education is losing its worth in insight just as truly as a public decent. Request situated 'asset creation' abilities of advanced education may increment. Be that as it may, the fundamental job of advanced education being developed is lessening. In these changes, the best test for the advanced education organizations lies at the comprehension of all encompassing, fair-minded administrative component.

### I. INTRODUCTION

New buzz words like 'changes', 'one window office', 'management transport' are also currently entering the higher education strategy in India. The political regulation following the New Economic Policy and the 201 General Decision cases marked an adaptation of the political scene, raising claims about governance, development and competence in the political-authority discourse of India. Due to the changing mindset of the Indian state, the developed educational frameworks will undoubtedly face changes. The proposed Her: Higher Education and Research Bill 2011, UGC and other changes in further education are called "enhancers for improvement" for the same reasons. Today, higher education, which is considered private and decent, is organized depending on capital speculation and is directed according to need. Special and government skills training has acquired the status of serious highways for companies, while the help and acceptance of humanities and sociologies is declining. Driving worthy of all these arrangements is essentially a matter of professionalism. As seen in various regions, India is seeing increasing capital flows without the sensible benefits of free enterprise. Although higher education is apparently in decline, it is anything but a public decent approach and is generally conceptualized as anything but a vehicle for private and neoliberal change along with medieval real factors and politically influenced frameworks. We currently have extensive political



connections in the field of private further education. Organizations are directly or indirectly "controlled" by government officials. The price of agriculture, tax incentives, legally compulsory training, the directive of NPE 1986 limited to "minimum positions", stable income and guaranteed state approval make further education in political and economic activity attractive. Current changes in continuing education support the success of such organizations. They tend to be minimally useful for primary problems such as expanding organizations or improving unemployed graduates. Such changes could lead to dictatorial powers that could undermine the aims of the further education framework to support research and development and promote socio-political change.

Without a doubt, the Indian country state has encountered huge changes in the political and financial part over recent many years. For advanced education frameworks, this has come about into diminishing the job of government from a gatekeeper in present freedom period on now a controller. Its scene has extended from state syndication to rising market influences. With regards to these changes, this paper examines the advanced education strategy worldview in India. It addresses important arrangements and political changes NPE: National Policy on Education 1986-1992 and the forthcoming HER: Higher Education and Research Bill. It further suggests that the best test for the advanced education organizations in these advances lies at the comprehension of all encompassing, unprejudiced administrative component.

## II. ADVANCED EDUCATION: FOR DEVELOPMENT THAT ENABLES

"Disproportionate improvement shifted against human advancement is an impasse, with monetary development diminishing following 10 years or so of quick development".- UNDP (1996) This surprising finding in UNDP report nullifies the ordinary thought that advancement is just a result of development. Maybe, it builds up the way that improvement is a fundamental peacekeeper for development. Financial development is just conceivable and manageable, if inspires circulation of advantages, improvement in personal satisfaction with decision – as well as the reasonableness to appreciate that decision. Advancement in India can't be limited to rising per-capita pay, however should be perceived as underlying change working with dynamic socio-political exchange in India's multi-class, multi-culture society. Improvement can be characterized as an interaction of empowering individuals to approach status and opportunity. As Amartya Sen (1999) says-"Improvement comprises of the expulsion of different sorts of unfreedom that leave individuals with little chance of practicing their contemplated office... the extension of the capacities' of people to lead the sort of lives they esteem - and have motivation to esteem". It is clear that improvement is an inborn attribute of progress in existences of individuals. As the state, particularly in vote based system, follows up in the interest of individuals, it is answerable for driving this change. While the country creates with its expanded limits and opportunity, it holds more grounded exchange with the country state, in the long run changing its tendency. Along these lines, state turns into the reason just as impact of such turn of events. Advanced education frames an indispensable piece of such empowering improvement, that extends social skylines of opportunity, support and administration in majority rule government. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan accentuated for the 'advancement of college framework that would have elevated expectations and produce residents who could take up duties and give administration in different circles of public life' (Ministry of Education, 1950). The college framework in India, at the center of advanced education, works with for the 'empowering' idea of human turn of events. "Instruction has an assimilating job. It refines sensitivities and insights that add to public attachment, a logical temper and freedom of psyche and soul in this

manner advancing the objectives of communism, secularism and popular government revered in our Constitution." - NPE (Dept., 1998) Hence, the public approach in advanced education the overall standard in India that sets frameworks to work-lies at the base of improvement. For monetary headway and solid information society, the unequivocal part of advanced education can't be disregarded (Tilak, 2013).

### III. POLICY SHAPES: HIGHER EDUCATION IN INDIA

For long time, education in India was treated by a nurturing, communist method of state. Be that as it may, the arrangement on advanced education slowly differed from development of state-upheld less-controlled establishments in 1968 to less-extending, more-directed organizations in 1986, likewise clearing a path for privatization. The Nehruvian model recognized the part of advanced education in country building. India zeroed in on industry situated advancement from second long term plan, provoking prerequisite of talented labor, setting up specialized and proficient organizations. The state put colossally in advanced education before. Subsequently, we have 634 colleges, 33000 schools, 40 focal colleges, 15 IITs, 13 IIMs, 30 NIT and 24 IIITs all as self-governing establishments completely financed by state (Tilak, 2013). Advanced education got need over school instruction, until NPE 1986. The past arrangement NPE 1968 laid less accentuation on state administrative system, yet supported improvement of Center for Advanced Studies just as Clusters of such focuses. NPE 1968 demanded for satisfactory assets before foundation of any organization. Then again, NPE 1986 limits itself to 'least offices' to begin an organization. The current strategy NPE 1986, while empowering the self-governance of organizations, weaves in state subsidizing through an administrative assemblage of UGC. State's immediate interest in advanced education has progressively declined over the period. In spite of the fact that NPE expected state to burn through 6% of GDP on instruction, it has never been carried out so. The strategy likewise accommodated huge number of private foundations, as NPE appeared after New Economic Policy-India's unavoidable advance towards progression of economy.

Notwithstanding expanding privatization and effect of globalization, advanced education in India is yet an issue of worry for government, in the simultaneous rundown for focal and state government after 42nd amendment to the constitution of India (Dept., 1998). Focal commissions and bodies cast significant effect on advanced education strategy in India. They incorporate Education (Kothari) Commission 1964-66, UGC and AICTE councils, National Knowledge Commission and Yash Pal Committee (Pal, 2009) et al. Right now, advanced education is controlled and directed by NPE 1986. Notwithstanding, the strategy making is not any more confined to state, however has reached out to worldwide players. Conspicuous among them are the World Bank Paper on Higher Education (1994) and World Trade Organization's General Agreement on Trades in Services currently including 'schooling administrations'. GATS, the first one to build up exchange quite a while, is one such global approach creator for India. Inside GATS, training is one of the twelve essential administrations and advanced education is one of the five sub-areas of instruction (Division of Higher Education, 2004). The developing part of outside players and changing political scene has landed India into a remarkable move. With the HER bill, India is consolidating the idea of concentrated solitary decision over advanced education a certain control of government on open organizations and conduct of a solitary window office for rising private and unfamiliar parts in instruction.

#### IV. PUBLIC TO PRIVATE GOOD AND SOCIO POLITICAL RELEVANCE

Conflicting with the education strategies up until now, there has been a change in how schooling is seen in India. Up to this point, schooling was viewed as essentially a public decent. It should project public effect and stay in the aggregate interest. The commitment of experts in public advancement has been enormous. Educating was an adored occupation. There was negligible accentuation on private commitments, like charge. Schooling was completely a state subsidized movement. Public help to schooling can be legitimized from multiple points of view. Government has three in number explanations behind supporting tertiary instruction.

1. "Interest in tertiary training creates outer advantages fundamental for monetary and social turn of events" (World Bank, 2002). Gets back from advanced education are not restricted to work. They are viewed as instruments of appropriating development. A reformist information society is worked through advanced education, which isn't just fundamental for financial turn of events yet in addition for accomplishing objectives of equity, fairness, and freedom. Advanced education makes an illuminated class. This class integrates numerous parts of society.

Limit building and status upliftment through advanced education guarantees better dissemination of assets. Private advantages societal position, monetary addition, political hold, social variety are sent to different areas of society through comprehensive advanced education.

2. "Capital business sectors are portrayed by defects and data imbalances that oblige capacity of individual to acquire sufficiently from training" (World Bank, 2002). The main issue in marketization of schooling is 'thought process'. Capital business sectors are run on benefit thought process, dissimilar to express that addresses aggregate. State is equipped for guaranteeing variety, self-rule and correspondence in instruction. Then again, markets are drive by benefit rationale and managed by cost. They will in general make advanced education organizations that are less-available, pseudo-self-ruling and request situated. The job of advanced education in private industry can get diminished to 'provider of human resources' in lieu of a liberal, information creating framework.

As the state accepts accountability of improvement, open schooling turns into its essential concern. Advanced education doesn't just make skilled educators, yet additionally a superior common society. The common society imparts huge space to government and helps in its accomplishment of social goals.

#### V. "REFORMS" AND INTRODUCTION OF THE HER BILL

Political pressing factors and insecurity keep on presenting new difficulties for advanced education strategy in India. As per an investigation, India faces moderate level danger of unsteadiness (Smith, 2001). There are local and ethnic contentions, wrongdoing rates and debasement issues pervasive among the organizations. During circumstances such as the present, the quality as well as independence of advanced education organizations is crucial. The quality and self-sufficiency of establishments will thusly characterize the endurance of information social orders in India. In any event, when advanced education framework is viewed as an instrument delivering private products in open space, we can distinguish changing requirements of the framework as follows (World Bank, 2002).

- Supporting development: Brain channel has been a joined impact of disappointment of advanced education just as that of financial stoppage, cash fall. Establishments in India, numerous yet slacking in quality principles, neglect to draw in brilliant understudies. Examination and advancement is restricted. Indian diaspora has been moderately more fruitful. The proportion of licenses enrolled by non-occupant Indians to inhabitants is unbelievably low (Tilak, 2013). It underlines the disappointment of Indian organizations to support examination and advancement. NPE makes a managed at this point independent component for research. Be that as it may, under the proposed system of NCHER, examination and development is limited to endorsed foundation's supported focus in confined way, self-rule is decreased and possibly influencing the turn of events.
- Contributing to human resources advancement: In the neoliberal model being adjusted in modernizing India, advanced education is a standardized exertion for asset creation. Its advancement is market driven, courses are planned by industry needs and preparing requests are met. There is, thusly, more prominent accentuation on specialized and the board schooling. This sort of market level linkage leaves little degree for information age and liberal improvement of society. Maybe, the social part of high schooling gets invalidated.
- Providing the establishment for vote based system, country building and social attachment: Higher training in India has been a mode of multi-facet changes. Post New Economic Policy period and issues in 2014 general races mark an adjustment of political scene of India. Alongside standing based, religion-based character legislative issues, the issues of administration and responsibility turned out to be progressively important in broad daylight talk.

## VI. CONCLUSION

With the changing idea of Indian state, advanced education frameworks will undoubtedly confront changes. As the state draws nearer to its neoliberal model, the medieval designs of strength will result into more tyrant powers. These impacts will be noticeable in advanced education frameworks also. As noticeable in different areas also, India is seeing expanding stream of capital without the upsides of free enterprise. Advanced education is losing its worth in insight just as truly as a public decent. Request situated 'asset creation' abilities of advanced education may increment. Be that as it may, the fundamental job of advanced education being developed is lessening. In these changes, the best test for the advanced education organizations lies at the comprehension of all encompassing, fair-minded administrative component. The approaches will in general move between limits or only change the shape, not content. A change, predictable with the evolving state, would prefer to request a majority rule, straightforward, responsible administrative just as help organization of government for advanced education with access and opportunity. Provisos in the current arrangement ought to be eliminated and its suggestions should be made reliable with the actual reason for strategy. India can't bear to work in duality.

## VII. REFERENCES

- [1]. CABE: Central Advisory Board of Education (2005) Report of the CABE Committee on Financing of Higher and Technical Education. New Delhi, India: CABE, Ministry of Human Resource and Development.

- [2]. Department of Education. (1998) National Policy on Education 1986 as altered in 1992, with National Policy on Education 1968. New Delhi: Government of India.
- [3]. Division of Higher Education (2004) Higher Education in a Globalized Society UNESCO Education Position Paper. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- [4]. Labour Bureau (2012) Employment and Unemployment Survey Chandigarh: Government of India.



NEBULA  
AN INDEXED, REFERRED &  
PEER REVIEWED JOURNAL

22-23



ISSN 2277-8071

17

# RESEARCH NEBULA

*An International Refereed, Peer Reviewed & Indexed Quarterly Journal in  
Arts, Commerce, Education & Social Sciences*

DOI PREFIX 10.22183

JOURNAL DOI 10.22183/RN

IMPACT FACTOR 7.399

ONE DAY

**INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY CONFERENCE**

On

**RESEARCH, INNOVATION, CHALLENGES &  
OPPORTUNITIES IN HIGHER EDUCATION**

13<sup>th</sup> January, 2023

Organized by



DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION & SPORTS & I.Q.A.C.  
SMT SALUNKABAI RAUT ARTS & COMMERCE  
COLLEGE, WANOJA, DIST. WASHIM (M.S.)



SARASWATI KALA MAHAVIDYALAYA, DAHIHANDA,  
TQ. DIST. AKOLA. (M.S.)



ARTS AND SCIENCE COLLEGE, KURHA,  
AMRAVATI. (M.S.)



in collaboration with  
PHYSICAL EDUCATION FOUNDATION OF INDIA,  
NEW DELHI.

Special Issue Published on 13<sup>th</sup> January, 2023  
[www.ycjournal.net](http://www.ycjournal.net)



	<b>S.E. BHANDARKAR</b> GVISH, Amravati <b>B.P. KHOBRAGADE</b> Assistance Professor, Dept of Chemistry, RDIK and NKD College, Badnera		
146.	<b>MAYUR KUMAR</b> Research Scholar Degree college of Physical Education, H.V.P.M Amravati (M.S.)	EFFECT OF FOOT LENGTH ON DOLPHN KICK: A STUDY OF SWIMMING SKILLS	507
147.	<b>DR. NARENDRA A. THAKARE</b> Matoshri Subhadrabai Patil Mahavidyalaya, Manora.	INNOVATIVE BEST PRACTICES IN LIBRARY SERVICES	509
148.	<b>DR. NAVIN S. VIGHE</b> Director of Physical Education Prof. Ram Meghe College of Engineering & Management, Badnera, Maharashtra, India	EFFECT OF MEDITATION ON SELF CONTROL OF ENGINEERING STUDENTS	511
149.	<b>DR. NILESH V. GORE</b> Librarian Prof. Rajabhau Deshmukh Arts College, Nandgaon Khandeshwar, Amravati.	OPEN AND DISTANCE LEARNING IN INDIA	514
150.	<b>DR. PRAKASH T. KAMBLE</b> College of Physical Education Yavatmal (M.S).	COMPARISON OF PHYSICAL FITNESS COMPONENTS OF B. P. ED AND AGRI. BIO-TECH STUDENTS OF YAVATMAL INDIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM	518 521
151.	<b>DR. PRASANNA P BAGDE</b> Head Department of History Shri Ganesh Arts College Kumbhari Akola		
152.	<b>DR. PRAVIN S. INGLE</b> Department of Geology, G. S. Tompe Arts, Commerce & Science College, Chandur Bazar	TODAY'S EDUCATION POLICIES: A REVIEW	523
153.	<b>PRAVINKUMAR JADHAV</b> Assistant Professor, Ashoka College of Education, Nashik	CHAT GPT-FUTURE OF AI IN EDUCATION	527
154.	<b>PROF. PUNAM NARENDRA MAHALLE</b> Pingalakshidevi Mahavidyalaya Nerpinglai Tq. Morshi Dist. Amravati	CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN HIGHER EDUCATION	530
155.	<b>PROF. RAHUL P. GHUGE</b> Asst. Professor, Department of English, Shri.Dhabekar Kala Mahavidyalaya, Khadki, Akola.	USE OF ICT IN HIGHER EDUCATION	533
156.	<b>RAJNI SHARMA</b> Research scholar <b>DR. R. CHANDRAWANSHI</b> Supervisor	COMPARATIVE ANALYSIS OF SOCIALITY SUB VARIABLE OF SPORTS SPECIFIC PERSONALITY BETWEEN HOCKEY AND ATHLETIC PLAYERS OF HIMACHAL PRADESH	536
157.	<b>ASST. PROF. DR. RAVIJEET O. GAWANDE,</b> Babaji Datey Kala Ani Vanijya Mahavidyalaya, Yavatmal District (M.S.)	COMPARATIVE STUDY OF CREATIVITY AND SELF-CONFIDENCE BETWEEN MALE AND FEMALE TEAM GAME PLAYERS OF YAVATMAL	538
158.	<b>DR. SANGITA N. LOHAKPURE</b> Director of Sports and Physical Eduction Shri Dhabekar Arts college Khadki, Dist. Akola	TRENDS AND INNOVATIONS IN TEACHING AND LEARNING	542



DR. SANGITA N.  
LOHAKPURE

Director of Sports and  
Physical Education  
Shri Dhabekar Arts  
college Khadki, Dist.  
Akola

One Day International Multi-Disciplinary Conference  
**RESEARCH, INNOVATION, CHALLENGES & OPPORTUNITIES  
IN HIGHER EDUCATION**

On 13<sup>th</sup> January, 2023 @

Smt Salunkabai Raut Arts & Commerce College, Wanoja,  
*In collaboration with*  
Saraswati Kala Mahavidyalaya, Dahihanda  
Arts And Science College, Kurha,  
Physical Education Foundation of India, New Delhi.

**TRENDS AND INNOVATIONS IN TEACHING AND LEARNING**

**ABSTRACT**

*The purpose of this article is to raise awareness of the tasks and innovations of information and communication technology in the field of better education in the 21st century. In particular, the publication argues that ICT has so far had little or no impact on approaches to teaching practice, but that the impact will expand impressively in the coming years, and ICT will develop into a stable professional that can be used across multiple teaching practices. The observation reveals that the use of ICT for better education is growing rapidly in exceptional states of India. One of the biggest widely diagnosed problems with the use of information and communication technology (ICT) in education is that choices are made in admiration of the progressive consequences that can be achieved rather than educational needs. In growing countries where better teaching is emphasized with real problems at multiple levels, stress can increase to ensure that the impact of progressive skills is visible according to teaching needs. The usage of ICT in schooling suits extra understudy centered studying settings and frequently this makes someplace withinside the variety of pressures for some educators and understudies. Be that as it could, with the arena transferring fast into automatic media and data, the a part of ICT in better schooling is finishing up more and more more vital and this importance will continue to broaden and create withinside the twenty first century.*

**Introduction**

Education is one of the true drivers of economic prosperity and human betterment. Education is becoming a notable source of superiority as international economic competition intensifies. This promotes economic improvement and makes rural areas more attractive for jobs and investments. Education is also one of the most important determinants of lifetime income. The importance of education of all kinds of exceptional backgrounds has increased with the help of statistics and verbal exchange technology (ICT). In the last 20 years, the use of ICT has usually changed the way teaching works in schools. In today's situation-conscious world, the importance of education and the suitability of ICT as a social need has grown. The social acceptability of statistics and communication tools is crucial to improve public mobility and raise prices and social equality. India's emphasis on better education can be understood from the number of universities in India today and the

enjoyable learning they offer. According to ultra-modern facts from UGC website, as of February 2017, India has 789 universities, 37.20 faculties and 11.3 min. These numbers keep getting better. The Government of India has been active in ICT sports and has defined a national approach to ICT which is considered and implemented through line ministries and ministries. It is implemented through active sports events by National Informatics Center (NIC) and incentives from University Grants Commission (UGC), All India Council for Technical Education (AICTE) and Department of Science and Technology (DST) in selected states. from the country The National Association of Services and Software Companies (NASSCOM) was also instrumental in the detailed development of these strategies. The final has long been about integrating ICT trends into better school structures surrounding the arena. Even then, the effort to expand a better learning tool, it is complex and dynamic, to integrate the era holistically in the management and



delivery of learning programs is daunting. The first part gives a brief overview of better education in India. Objects are located in a two-dimensional segment. Segment 1/3 looks at the explosion of better teaching in India. In the last episode, we give blessings and situations that require ICT.

### Innovative Approaches for students: Growth of ICT in India

Contribution of ICTs in numerous measurements of the Indian better schooling framework is going on at a short pace. Utilization of audio visible aids, radio, TV to assist schooling and broadcasting of statistics for country improvement isn't new. The usage of satellite tv for pc in better schooling started as Satellite Instructional Television Experiment (SITE) in 1975-76. This induced the inspiration of Central Institute Of Educational Technology (CIET) and State Institute Of Educational Technology (SIET) studios for era and transmission of faculty located projects, begin of the country-huge school room of the University Grants Commission (UGC) with Consortium for Educational Communication (CEC) because the nodal workplace through making instructional media aid centers (EMRCs) and audio-visible aid centers (AVRCs) in numerous universities and faculties. Presently those programmers" are intending as Vyas Channel upheld through the CEC and exceptional EMRCs, Gyandarshan II of the IGNOU, Open School and NCERT talk and broadcast channel. Educational Satellite (EDUSAT ) became conceptualized to fulfill the communications necessities of the schooling zone. The Eleventh 5 yr plan is similarly giving impetus to apply of ICTs in schooling through putting in a National Mission in Education thru ICT. In this regard, use of ICTs could make a contribution notably to beautify the get right of entry to and pleasant of schooling however on the identical time it could generate situations, which warrant attention. For example to sell era pushed schooling and open and distance studying the u . s . a . released a devoted satellite tv for pc EDUSAT on September 20, 2004. It became anticipated that EDUSAT could carry each quantitative and qualitative revolution in schooling. However, the quantitative growth seems to were performed in being capable of attain out to massive numbers, but the qualitative revolution expected because of advent of latest offerings and higher pleasant coaching with studying materials, has now no longer been pretty visible.

### ROLE OF ICT IN HIGHER EDUCATION

While for better schooling zone is deliberate to construct a know-how repository of multidisciplinary subjects, as a approach to counter the lack of college in better schooling, EDUSAT can be used to percentage the to be

had knowledge thru modular programmes, finished through networking establishments, digital laboratories, advent of database, get right of entry to to professional lectures and technological trends in industries and studies agencies etc. Teaching and studying can similarly be advanced through changing of traditional coaching in preference to the same old age antique technique of chalk and speak for coaching through progressive strategies like energy factor displays and animations, modelling and simulations, videos and the use of AV aids, LCD projectors etc. ICT in management of instructional establishments play a first-rate function in green usage of current assets and simplifies the management tasks (e.g. in pupil management, workforce management, widespread management etc.) through decreasing the paper paintings and replaces the guide renovation of report maintaining to digital renovation of data which enables in clean retrieval of any statistics of students, workforce and widespread with in a fragment of seconds can get right of entry to the desired statistics. Integration of ICT in better schooling complements the pleasant of studies paintings and extra quantity of people enrolled withinside the studies paintings in numerous fields. ICT helps the hyperlinks internationally in all difficulty remember and made social networking. It saves time, cash and attempt to the researchers of their studies studies.

### E-Learning and ethics

e-Learning is an academic method that leverages at the possibilities of virtual technology for handing over contents, assessing college students' abilities in addition to for reinforcing interplay amongst customers and among educators/instructors and college students. Delivery may be synchronous (wherein interplay among pupil-instructor and pupil-pupil is simultaneous) or asynchronous (wherein interplay among pupil-instructor and pupil-pupil does now no longer take location concurrently with out constraint of time and location). In each types, the scholars want to be encouraged for mastering so as to triumph over the poor results of the separation among each other and from their instructor. Shawar et al stated that, the quantity of interplay performs a high-quality function in effectiveness of tutorial method however loss of bodily interplay stays the largest barrier to the fulfillment of tutorial method in e-Learning. The college students take in ethical and moral values thru bodily interplay of instructors, households and society participants however e-Learning is poor in offering those values.

### Conclusion

In this studies predominant awareness at the function of ICT in better schooling for the twenty first century. The

of ICT has typically modified the operating of better schooling universities and Institutions. In the existing situation aware world, the importance of schooling and adequacy of ICT as a social want has been increasing. Social acceptability of statistics and verbal exchange gear is crucial to beautify the mobility withinside the widespread public and increment the pitch for price and social equity. This paper mentioned the evolution of ICT in India. ICT performed very powerful function for students, teachers, studies and administrative workforce in better schooling. This studies is likewise awareness on ICT as a Change agent in Society and better schooling. This paper mentioned demanding situations and blessings of ICT in better schooling. Based on all above dialogue ICT is extra relevant and powerful platform for better schooling.

#### References

1. Shazli Hasan Khan, "Integration of ICT issue in trainer schooling: Institution unavoidable step

towards reworking the pleasant of gift trainer schooling device".

2. Meenakumari.J, Krishnaveni.R, "ICT primarily based totally and studying in better schooling-A observe", International Journal of Computer Science and rising technology, 2010
3. Shaikh Saleem,"Role of ICT as a pleasant coaching tool",An International multidisciplinary journal, 2012.
4. Sukantha Sarkar, "Role of ICT in better schooling for the twenty first century, Science Probe, Vol 1, 2012. ISSN-2277-9566.
5. Zeininger.C, 2009, "The use of ICT in HEIs in Mozambique: Institutional web sites as Ambassadors for instructional technology 6. John Daneil, "ICT in schooling a curriculum for colleges and programmer of trainer improvement.